शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 7 अंक : 1 1 अगस्त 2014

(श्रावण-भाद्रपद, विक्रम संवत् 2071)

संरक्षक

मुकुन्द कुलकर्णी

प्रो.के.नरहरि

❖

परामर्श

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक

प्रो. सन्तोष पाण्डेय

❖

उप सम्पादक

विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी

भरत शर्मा

❖

प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक

बजरंग प्रसाद मजेजी

❖

प्रेषण प्रभारी

बसन्त जिन्दल 9414716585

प्रकाशकीय कार्यालयः

82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,

जयपुर (राज.) 302001

दूरभाषः 9414040403,9782873467

दिल्ली ब्यूरो

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,

कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाषः 011-22914799

E-mail:

shaikshikmanthan@gmail.com

Visit us at :

www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 15/-

वार्षिक शुल्क 150/-

आजीवन (दस वर्ष) 1200/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक

में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल

का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

शैक्षिक परिवर्तन में शासन की भूमिका - मा. गो. वैद्य

7

चूंकि हमने जनतंत्र की व्यवस्था को स्वीकृत किया है, इसलिये शैक्षिक परिवर्तन में भी शासन की भूमिका रहेगी। किन्तु वह भूमिका नियंत्रक की या प्रशासक की नहीं रहेगी। वह रहेगी एक स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था के निर्मिति की। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शासन ने सबको दिया है, उसी प्रकार शिक्षा देने का भी अधिकार सबको मिलना चाहिये। यह काम शासन को ही करना है। अतः शासन की इस क्षेत्र में भी भूमिका है।

अनुक्रम

4.	शिक्षा व शैक्षिक व्यवस्था में शासन की भूमिका	- सन्तोष पाण्डेय
9.	शासन-निरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था ही समस्याओं ...	- मुकुल कानिटकर
12.	शैक्षिक विकास की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार ले	- बजरंगी सिंह
16.	शिक्षा में शासन की भूमिका कैसी हो?	- डॉ. श्रीमती रेखा भट्ट
18.	मैकालयी व्यवस्था का पोषक है शासनतन्त्र	- विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी
20.	शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक व शासन के प्रयत्नों ...	- बजरंग प्रसाद मजेजी
22.	Need for Right Direction in	- Dr. A. K. Gupta
28.	More than a Million have no School	- Poulomi Banrjee
32.	Education Budget falls short of	-
34.	लाइसेंस राज में फँसी शिक्षा	- तवलीन सिंह
36.	दूर रहें नौकरशाह, तो ठीक होगी उच्च शिक्षा	- देवेश कपूर
38.	In Science, India invests far less	- Hemali Chhapia
40.	मत कीजिये विज्ञान की अनदेखी	- शशांक द्विवेदी
42.	ये युवा कैसा भारत बनाएंगे	- एन. के. सिंह
44.	मानसिकता बदलने से बनेगी बात	- एन आर नारायण मूर्ति
46.	सृष्टि में अतुलनीय विज्ञान के सृजनकर्ता हम	- साकेन्द्र प्रताप वर्मा
49.	शिक्षक की गरिमा	- शारदा कुमारी
50.	शिक्षा से आएगा दुनिया में भारतीय युग	- केविन रैफर्टी
52.	देशी भाषाओं में हों भर्ती परीक्षाएं	- वेदप्रताप वैदिक
54.	अखण्ड भारत कैसे ?	- सत्यपाल हर्ष
58.	गतिविधि	

Higher Education and the Role of State

❑ **Dr. TS Girishkumar**

On a final analysis, I am of the view that education should be state controlled, provided that the vision and wisdom of the state can be taken for granted. Bharat can now hope for strong and meaningful governance, and education ought to be fully under the present government. This is simply because the present government has a lot to do, in undoing the evils of the old and in recreating ancient Bharatiya knowledge tradition, a task, which is not going to be easy or simple. For Bharat, education has to be a long struggle, because the goal we shall have to set is of approximating the Vedopanishadic knowledge tradition and recreating the same in present context, time and space.

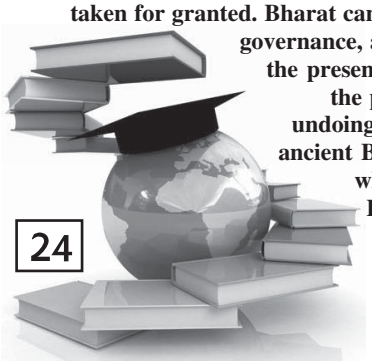

24

शिक्षा व शैक्षिक व्यवस्था में शासन की भूमिका

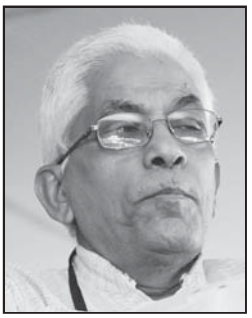

भारतीय शिक्षा व शिक्षा-व्यवस्था की कमजोर व्यवस्था के मूल में जाने पर अनुभव होगा कि यह स्थिति शिक्षा में स्वायत्तता के अभाव, सरकार पर वित्तीय संसाधनों के लिए निर्भरता, पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का व्यावहारिक ज्ञान से विलगाव, सेवा के स्थान पर शिक्षा का लाभदायक उपक्रम में बदलना, रोजगारक्षम शिक्षा प्रदान करने में असफलता के कारण बनी है। शिक्षा की नीति सुस्पष्ट व्यावहारिक होनी चाहिए जिसके उद्देश्य व लक्ष्य सुस्पष्ट होने चाहिए। इसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। शिक्षा दलीय व क्षेत्रीयता की राजनीति से परे व समाज के सभी वर्गों की आम राय के आधार पर बनी आम सहमति को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए।

❑ **सन्तोष पाण्डेय**

संपादकीय

वैदिक काल से ही भारत में ज्ञान की गौरवशाली परम्परा रही है। वेदों, उपनिषदों व ज्ञान के अन्यान्य स्रोतों में ज्ञान का अथाह भंडार संग्रहित है। इसमें शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था का अतुलनीय योग रहा है। गुरुकुल आधारित शिक्षा व्यवस्था एवं गुरु आधारित शिक्षा का ही परिणाम है, यह ज्ञान का यह महान सागर। शिक्षा की यह व्यवस्था पूर्ण स्वायत्त थी, राज्य का संरक्षण तो था, परन्तु उसके प्रभाव से मुक्त थी। वित्तीय संसाधनों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था राज्याश्रित होने के स्थान पर समाजाश्रित थी। गुरुकुल राज्य के प्रभाव व हस्तक्षेप से मुक्त होते हुए भी घनिष्ठ रूप से समाज से जुड़े हुए थे। राज्य (शासन) समाज का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। समाज की सोच सरकार के स्वरूप के रूप में प्रतिबिम्बित होती है। गुरुकुल के प्रतिनिधियों व ऋषियों का राजदरबार में समय-समय पर उपस्थित होना, संकेतक था कि वे समाज की सोच से अवगत हों, समस्याओं को जानें एवं गुरुकुल में वापस जाकर तप के रूप में चिंतन कर मानव के हितकारी समाधान प्रस्तुत करें। जो समान्यत: शासन को स्वीकार्य होते थे। वित्तीय संसाधनों के लिए समाज पर निर्भरता भिक्षावृत्ति के लिए समाज के समक्ष जाने के रूप में प्रकट होती थी। सभी गृहस्वामी व नागरिक भिक्षा के रूप में अपना योग समर्पित करते, यह स्वायतत्ता परन्तु राज्य के संरक्षण व समाज के आश्रय का एक अद्‌भुत उदाहरण था। इस व्यवस्था से स्वतंत्र सामाजिक व वैयक्तिक विचारों की सुदृढ़ सुविचारित एवं स्थायी व्यवस्था का अभ्युदय हुआ। विद्या व अविद्या दोनों का ही पोषण हुआ। देश व समाज भौतिक व आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सका।

आज देश में जिस प्रकार की स्थितियां शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान हैं, चिन्ताजनक हैं। शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: राज्याश्रित होती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की दशा में भारी परिवर्तन हो चुका है। देश, समाज व सरकार की सोच बदली है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भी व्यापक परिवर्तन हुये

हैं। शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। परिवर्तन के लिए समितियों, विशेषज्ञ दलों व आयोगों का समय-समय पर गठन किया गया। अनेकों अनुशंषाओं पर निर्णय हुए, किन्तु अधिकांश अनुशंषायें समय के गर्त में समा गई। बड़ी बहस के पश्चात आम सहमति के नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क बना। उदारीकरण व वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव के बाद स्थितियां फिर से बदली हैं। उच्च शिक्षा में जो भी नाम मात्र की स्वायत्तता थी, वह भी शनैःशनैः तिरोहित हो गई है। वैश्विक शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश की आशंका विद्यमान है। अनुसंधान व वैश्विक रैंकिंग में उच्च शिक्षा पिछड़ रही है। केन्द्र व राज्य सरकारें शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं। स्वाभाविक रूप से निजी उद्यम की शिक्षा में प्रभावशाली उपस्थिति बढ़ी है। सरकारी स्कूलों व अन्य सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रति व्यापक उदासीनता विद्यमान है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बावजूद देश में सभी को एक समान स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना आज भी एक स्वप्न है। लाखों बच्चों विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। कमजोर, गरीब, वंचित वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन व पोषाहार कार्यक्रमों से नामांकन की दर बढ़ी है। परन्तु शिक्षा के स्तर में गिरावट ही आयी है। देश में आर्थिक प्रगति एवं एक शहरी समृद्ध वर्ग की आर्थिक सफलता से शिक्षा, वह भी गुणवत्तापूर्ण की मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं की जर्जर व्यवस्था से निजी शिक्षण संस्थाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्कूली शिक्षा में निजी शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी 27 प्रतिशत तक हो चुकी है। शिक्षा जो कि सबसे बड़ा सामाजिक दायित्व एवं सेवा का माध्यम है, एक विशाल लाभ देने वाले उद्योग में परिवर्तित हो चुकी है। चिन्ता का विषय तो यह है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के स्थान पर वैयक्तिक, आर्थिक लाभ व सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने में व्यस्त हैं। गरीब, वंचित व उपेक्षित वर्ग इनमें शिक्षा प्राप्त करने में आज भी असमर्थ है। यद्यपि शिक्षा के अधिकार कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थान को कुल प्रवेश स्थानों में 25 प्रतिशत इनके लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान है। तदापि इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन का मूल्यांकन अपेक्षित है।

माध्यमिक शिक्षा की दशा भी प्राथमिक शिक्षा से भिन्न नहीं है। माध्यमिक शिक्षा कमजोर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के दुष्प्रभावों से ग्रस्त है ही, यह स्वयं भी छात्रों को न्यूनतम, इतनी भी शिक्षा प्रदान में समर्थ नहीं कि उच्च शिक्षा के लिए मजबूत आधार बन सके। माध्यमिक शिक्षा में भी दो स्तर की शिक्षण व्यवस्थायें विद्यमान हैं एक जो सरकारी स्कूलों में उपलब्ध तथा दूसरी जो शहरी उच्च मध्यम व सम्पन्न वर्ग के लिए पब्लिक स्कूलों के रूप में विद्यमान हैं। अधिकांश छात्र सरकारी व अर्द्धसरकारी

शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां शिक्षकों के अभाव, शैक्षिक सुविधाओं की कमी के चलते सामान्य स्तर की ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। माध्यमिक शिक्षा मिशन के माध्यम से सरकार इसे सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत हैं? माध्यमिक शिक्षा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा प्रोफेशनल शिक्षा, स्वरोजगार हेतु युवकों को तैयार करने उनमें कौशल व उद्यमिता को प्रेरित करने में समर्थ नहीं है।

उच्च शिक्षा जो देश के आर्थिक व सामाजिक विकास का प्रमुख स्रोत है, भी अनेक व्याधियों से ग्रस्त है ? उच्च शिक्षा देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है। उच्च शिक्षा में नामांकन दर भी बहुत कम है। इस कम नामांकन दर के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में 1500 नये विश्वविद्यालयों की स्थापना अति आवश्यक है। उच्च शिक्षा उपलब्ध ज्ञान को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम होने के साथ-साथ नये ज्ञान के सृजन, समस्याओं के समाधान, नई उत्पादन विधि विकसित करने, वर्तमान तकनीक से नए पदार्थ खोजने तथा नए प्रयोगों को प्रेरित करने में समर्थ होनी चाहिए। अनुसंधान व शोध के अभाव में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय न होकर परीक्षा लेने वाला मंडल बनकर रह जाता है। देश की विश्वविद्यालीय शिक्षा की यह सबसे बड़ी कमी है।

भारतीय शिक्षा व शिक्षा-व्यवस्था की कमजोर व्यवस्था के मूल में जाने पर अनुभव होगा कि यह स्थिति शिक्षा में स्वायत्तता के अभाव, सरकार पर वित्तीय संसाधनों के लिए निर्भरता, पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का व्यावहारिक ज्ञान से विलगाव, सेवा के स्थान पर शिक्षा का लाभदायक उपक्रम में बदलना, रोजगारक्षम शिक्षा प्रदान करने में असफलता के कारण बनी है। शिक्षा की नीति सुस्पष्ट व्यावहारिक होनी चाहिए जिसके उद्देश्य व लक्ष्य सुस्पष्ट होने चाहिए। इसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। शिक्षा दलीय व क्षेत्रीयता की राजनीति से परे व समाज के सभी वर्गों की आम राय के आधार पर बनी आम सहमति को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। आज देश की संपूर्ण शिक्षा व इसकी व्यवस्था शासन के आधार-नौकरशाही के कठोर शिकंजे में फंसी है। निर्णय शैक्षिक दृष्टिकोण की उपेक्षा कर नियमों व उपनियमों जिनकी मनमानी व्याख्या नौकरशाही द्वारा की जाती है के आधार पर किये जाते हैं। नौकरशाही के समान ही राजनीतिक दृष्टिकोण व विचारधारा भी शिक्षा व इसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। इन सबके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। गत वर्ष के शिक्षा सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति व यूजीसी के नियमों की उपेक्षा कर चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बेहतर शिक्षा के नाम पर भारी विरोध के बावजूद अपनाया। इस वर्ष सरकार में परिवर्तन होने के साथ ही यकायक यूजीसी को समस्त नियम कायदे याद आ गये और दिल्ली विश्वविद्यालय को पुन: तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अपनाने के निर्देश दिये तथा साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यदि चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये गये तो उन्हें वित्तीय सहायता से वंचित कर दिया जायेगा। यहां प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। प्रश्न यह है कि इस विवाद में किसी की स्वायत्तता का हनन हुआ। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ। इसकी जबावदेही किसकी है? अब समझ में आ गया है कि इन सभी पहलुओं पर निरपेक्ष दृष्टि से विचार कर निर्णय किया जाए।

भारतीय ज्ञान व शिक्षा व्यवस्था का मूलाधार स्वायत्तता व स्वतंत्र चिन्तन रहा है। आज भी शिक्षा को स्वायत्त व वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बना कर शिक्षा को व्याधि मुक्त कर राष्ट्र के हितवर्द्धन हेतु प्रेरित किया जा सकता है। भारत का संविधान शिक्षा की स्वायत्तता के लिए पर्याप्त क्षमता रखता है। इसके अन्तर्गत शिक्षा को शासन से पूरी तरह स्वतंत्र कर न्यायपालिका व अन्य संवैधानिक स्वायत्त निकायों की भांति ही गठित व संचालित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका में जिस प्रकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता एवं इसकी स्वतंत्रता का सम्मान सभी के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका की भांति ही शिक्षा को स्वायत्त बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की भांति देश के स्तर सर्वोच्च शिक्षा निकाय, राज्य व जिला स्तर पर उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय व्यवस्था की भांति ही राज्य व जिला शिक्षा निकायों की व्यवस्था की जा सकती है। सर्वोच्च, उच्च एवं जिला स्तरीय शिक्षा निकाय ही संपूर्ण शिक्षा एवं शिक्षा प्रशासन का संचालन करें। इन शिक्षा निकायों को प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के शैक्षिक संस्थानों के संचालन एवं संबद्धता प्रदान करने का अधिकार होगा। सभी सरकारी एवं निजी शिक्षा संस्थान इन्हीं शिक्षा निकायों द्वारा बनाये गये नियमों व उपनियमों से संचालित होंगे। निजी शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त सभी शिक्षण संस्थाओं का वित्तीय भार देश व राज्यों की सरकारों द्वारा उठाए जाने की गारंटीशुदा व्यवस्था होगी। शासन के हस्तक्षेप व राजनीतिक, क्षेत्रीयता, दृष्टिकोण व विचार भिन्नता से पूर्णता मुक्त ऐसी व्यवस्था की व्यापक रूपरेखा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन पहली आवश्यकता है। अनेक दशकों बाद भारी आशा व जन समर्थन वाली वर्तमान सरकार को राष्ट्रीय हित में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना स्वागत योग्य होगा। शैक्षिक प्रशासन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू पाठ्यक्रम अथवा क्षेत्रीय व स्थानीय आकांक्षाओं, विशेषताओं और विचार आवश्यक है। इस दिशा में गंभीर चिन्तन-मनन के लिए भी पृथक व स्वतंत्र आयोग का गठन भी शिक्षा को दिशा देने वाला प्रयास होगा। अन्तत: राष्ट्र व समाजहित ही शिक्षा का उद्देश्य हो तथा स्वामी विवेकानन्द जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम बने, यही शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था का मूलाधार बने। ❑

शैक्षिक परिवर्तन में शासन की भूमिका

❑ मा. गो. वैद्य

चूंकि हमने जनतंत्र की व्यवस्था को स्वीकृत किया है, इसलिये शैक्षिक परिवर्तन में भी शासन की भूमिका रहेगी। किन्तु वह भूमिका नियंत्रक की या प्रशासक की नहीं रहेगी। वह रहेगी एक स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था के निर्मिति की। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शासन ने सबको दिया है, उसी प्रकार शिक्षा देने का भी अधिकार सबको मिलना चाहिये। यह काम शासन को ही करना है। अत: शासन की इस क्षेत्र में भी भूमिका है। ये जो शिक्षा के स्वतंत्र और स्वायत्त विद्यालय होंगे, उनके मूल्यांकन की व्यवस्था शासन को ही करनी पडेगी। किन्तु यह व्यवस्था उस प्रकार रहेगी जिस प्रकार न्याय क्षेत्र की व्यवस्था रहती है। अपने संविधान की धारा 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की विधि बतायी है। उसी प्रकार शिक्षा के विषय में भी एक उच्चतम व्यवस्था रहेगी। इसी व्यवस्था के नियंत्रण में और देखरेख में प्राथमिक से लेकर उच्चतम संस्थाओं का प्रचलन रहेगा।

चूंकि हमने जनतंत्र की व्यवस्था को स्वीकृत किया है, इसलिये शैक्षिक परिवर्तन में भी शासन की भूमिका रहेगी। किन्तु वह भूमिका नियंत्रक की या प्रशासक की नहीं रहेगी। वह रहेगी एक स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था के निर्मिति की।

जैसी उच्चतम और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था निर्माण करने में शासन की भूमिका है किन्तु शासन, ना उसका नियमन करता है, ना उसका प्रशासन, उसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में भी शासन की भूमिका रहेगी।

न्याय व्यवस्था के सदृश

मैंने इसके पहले 'शिक्षा और मूल्यांकन' इस शीर्षक के एक लेख में, लिखा था कि जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शासन ने सबको दिया है, उसी प्रकार शिक्षा देने का भी अधिकार सबको मिलना चाहिये। यह काम शासन को ही करना है। अत: शासन की इस क्षेत्र में भी भूमिका है। ये जो शिक्षा के स्वतंत्र और स्वायत्त विद्यालय होंगे, उनके मूल्यांकन की व्यवस्था शासन को ही करनी पडेगी। किन्तु यह व्यवस्था उस प्रकार रहेगी जिस प्रकार न्याय क्षेत्र की व्यवस्था रहती है। अपने संविधान की धारा 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की विधि बतायी है। उसी प्रकार शिक्षा के विषय में भी एक उच्चतम व्यवस्था रहेगी। इसी व्यवस्था के नियंत्रण में और देखरेख में प्राथमिक से लेकर उच्चतम संस्थाओं का प्रचलन रहेगा।

शासन की भी भूमिका

वह संस्था, प्राथमिक (1 से 4), पूर्व माध्यमिक (5 से 7), माध्यमिक (8 से 12) और विश्वविद्यालयीन इन सभी स्तरों पर नियामक मण्डलों का गठन करेगी। शिक्षा देनेवाली निजी संस्थाओं के समान शासकीय विद्यालय भी रह सकेंगे। नहीं उनको रहना आवश्यक ही रहेगा। सरकार जनप्रतिनिधियों की होने के कारण, लोग क्या चाहते हैं इस का संज्ञान सरकार को होगा ही। जहाँ निजी अभिक्रम कम दिखता है, वहाँ सरकार की पहल आवश्यक रहेगी। निजी शिक्षा संस्थाएं जिस प्रकार नि:शुल्क या अल्पशुल्क लगाकर अपना कार्य चला सकती हैं, उसी प्रकार ये संस्थाएं अनाप-सनाप शुल्क भी लगा सकती हैं। अत: कम से कम 12 वी कक्षा तक पढाई के लिये सरकार ने नि:शुल्क शिक्षा देने वाले अपने विद्यालय भी खोलने चाहिये। यह नितान्त आवश्यक है।

उच्चतम शिक्षा मण्डल

सम्पूर्ण देश की शिक्षा पर नियंत्रण रखने वाला एक उच्चतम मण्डल रहेगा। उस के सदस्यों की संख्या साधारणत: 21 रहेगी। इन सदस्यों की

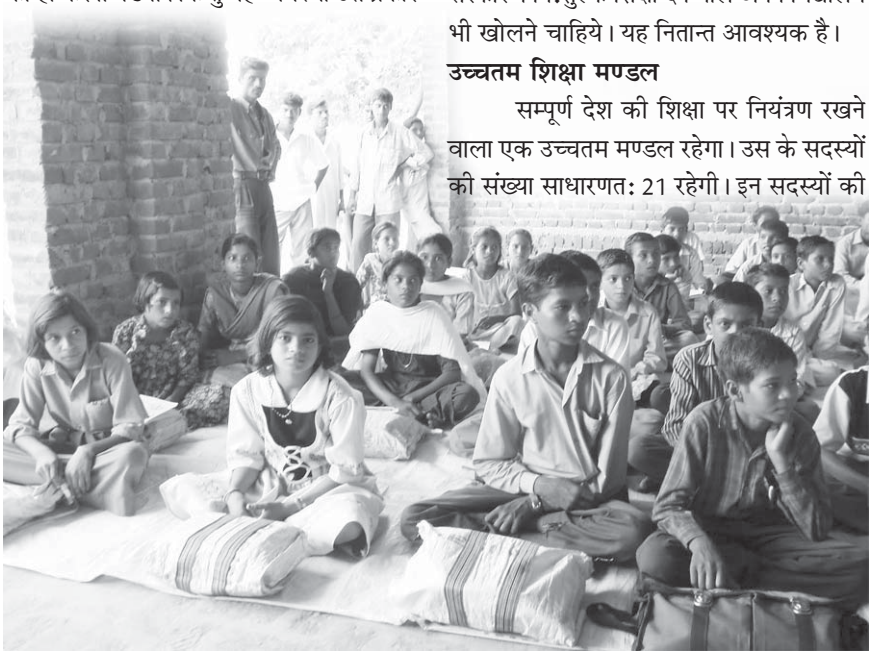

नियुक्ति राष्ट्रपति यानी सरकार ही करेगी। किन्तु उनकी सेवा सरकार के अधीन नहीं रहेगी। जनतंत्र में सार्वत्रिक चुनाव के बाद भिन्न भिन्न दलों की सरकारें सत्तासीन होती है। उन सरकारों के विचार से शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। जो उच्चतम मण्डल बनेगा, वह प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा बनने के पश्चात्, आगे अपनी योजना से काम करेगा। सरकार बदलने के साथ यह मण्डल नहीं बदलेगा।

यह उच्चतम मण्डल, हर राज्य के लिये, 12 वीं तक की कक्षा के लिये अलग अलग मण्डल नियुक्त करेगा। जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिये अलग मण्डल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिये स्वतंत्र मण्डल और माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग मण्डल रहेंगे। ये मण्डल और छोटी इकाइयों के लिये, अपने अधिकार कक्षा में और उप मण्डल बना सकते हैं। ये मण्डल पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। वैसे ही मूल्यांकन की या परीक्षा की पद्धति और व्यवस्था के भी नियम बनायेंगे।

विभिन्न स्तरों के मण्डलों के सदस्यों की नियुक्ति उच्चतम मण्डल करेगा। इस हेतु कितना विकेंद्रीकरण आवश्यक है और कितना केंद्रीकरण आवश्यक है, यह भी उच्चतम मण्डल तय करेगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ है, विभिन्न स्तरों के मण्डल अपना-अपना पाठ्यक्रम तैयार तो करेगा किन्तु उसके मान्यता के लिये, उस उस मण्डल के ऊपर के स्तर के मण्डल की अनुमति आवश्यक रहेगी। उदाहरणार्थ - प्राथमिक शिक्षा मण्डल की योजना के लिये पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता आवश्यक रहेगी।

व्यावसायिक और तांत्रिक अभ्यासक्रम

12 वीं के पश्चात् दो या तीन वर्ष अवधि के व्यावसायिक तथा तंत्रज्ञानात्मक अभ्यासक्रम (डिप्लोमा कोर्सेस) होने चाहिये। इन अभ्यासक्रमों को सरकार तय करे तथा उनका सम्पूर्ण संचालन तथा मूल्यांकन भी सरकार के अधीन रहेगा। स्वयं रोजगार के लिये तथा छोटी मोटी नौकरियों के लिये यह आवश्यक है। जैसे कार-स्कूटर दुरुस्ती के लिये ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग, फिटिंग के लिये मेकॅनिकल इंजिनियरिंग, ग्रंथालयों के लिये ग्रंथालय शास्त्रका पदविका अभ्यासक्रम, लेखापालन (अकाऊंटिंग के लिये) वाणिज्य पदविका, डॉक्टरों के सहायकों के लिये तथा नर्सिंग के लिये वैद्यक पदविका आदि। ये अभ्यासक्रम पूर्ण करने वालों को निजी व्यवसाय प्रारंभ करने में उत्साह मिले, इस हेतु बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार वहन करेगी। 12 वीं के बाद जिन को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में क्षमता नहीं है या अभिरुचि नहीं है, उनके लिये ये अभ्यास क्रम उपयुक्त होंगे। इस योजना में राज्य सरकारों की भी अहम भूमिका रहेगी।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा

विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिये भी मूल तत्त्व यही रहेगा। जैसे सरकारी विश्वविद्यालय रहेंगे, वैसे ही निजी विश्वविद्यालय भी रहेंगे। विश्वविद्यालय के गठन के और संचालन के सम्बन्ध में, वह वह विश्वविद्यालय, स्वतंत्र तो रहेगा, किन्तु अन्तिम मान्यता, उच्चतम मण्डल की अनिवार्य रहेगी। यह उच्चतम मण्डल कुलपति के लिये अर्हता और अन्य नियम बनायेगा। अब जो अंग्रेजी शासन पद्धति के अनुसार राज्यपाल पदेन कुलपति बनता है, वह पद्धति समाप्त होगी। हरेक विश्वविद्यालय के लिये कुलपति अलग अलग होंगे। उप कुलपति का पद नहीं रहेगा। निजी विश्वविद्यालय अपना कुलपति कौन हो, इस की सिफारिश कर सकेगा। किन्तु अन्तिम मान्यता उच्चतम मण्डल की आवश्यक रहेगी।

अनुसंधान के लिये

अनुसंधान के लिये पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना, यह विश्वविद्यालयों का दायित्व होगा। विशेष क्षेत्र में जैसे अणु विज्ञान या सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञान, में संशोधन के लिये सरकार अपनी संस्थाएं बना सकेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन की अनुमति आवश्यक नहीं रहेगी। किन्तु विश्वविद्यालय का सामान्य शैक्षिक वातावरण ही ऐसा रहना चाहिये कि अनुसंधान करने वालों को पर्याप्त साधन और प्रोत्साहन प्राप्त होते रहेगा। इस हेतु शिष्यवृत्ति आदि की व्यवस्था करना यह सरकार का कर्तव्य होगा।

वेतन की व्यवस्था

विभिन्न स्तरों पर जो मण्डल या उपमण्डल बनेंगे, उनके सदस्यों के वेतन की व्यवस्था सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने कितना व्यय ग्रहण करना चाहिये, राज्य सरकारों ने कितना, यह केंद्र सरकार तय करेगा। आज भी सभी स्तरों पर के न्यायाधीशों का वेतन सरकार तय करती है और उसका व्यय भी वहन करती है। इसी पद्धति का शिक्षा क्षेत्र में भी प्रचलन रहेगा।

तात्पर्य

तात्पर्य यह है कि न्याय व्यवस्था के समान शिक्षा व्यवस्था भी स्वायत्त और स्वतंत्र होगी। प्रारंभ में सरकार इसकी निर्मिति करेगी और निरन्तर इस के व्यय का भी प्रावधान करेगी। किन्तु इस पर अपने नियंत्रण का अधिकार नहीं चलायेगी। यह मानसिकता सुलभ नहीं है। किन्तु देश के और शिक्षा के स्तर के लिये आवश्यक है। जिसका दाम उसका काम यह नीति यहाँ नहीं चलेगी। इस हेतु सरकार चलाने वालों का अंत:करण विशाल और सोच मूलगामी होने की आवश्यकता है। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था ऐसी स्वतंत्र और स्वायत्त थी। फिर भी उस समय के राजा आर्थिक दृष्टि से उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। समाजवादी विचार से चलने वाले, ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। किन्तु अब समाजवाद का आकर्षण समाप्त हुआ है। उदारता का माहौल बन रहा है। सरकार ने भी इस उदारता का परिचय देना चाहिये। ❑

(विचारक, लेखक, दैनिक तरुण भारत के पूर्व संपादक व रा.स्व.संघ के पूर्व प्रवक्ता)

शासन-निरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था ही समस्याओं का स्थायी उपाय

शासन निरपेक्ष शिक्षा ही वास्तव में गुणवत्तापूर्ण, सर्वव्यापी तथा शुचितापूर्ण हो सकती है। शासन निरपेक्ष का अर्थ निजीकरण नहीं है। निजी व्यापारियों के हाथ में शिक्षा सौंपना उपाय नहीं हो सकता। 1991 के बाद सब ओर जब निजीकरण का बोलबाला हुआ तब शिक्षा क्षेत्र में भी निजीकरण हुआ। किंतु यह केवल व्यापारीकरण था। सरकारी नियन्त्रण तो बढ़ता ही रहा है। स्वतंत्रता केवल लूटने की है। छात्र व शिक्षक का शोषण निजीकरण से बढ़ा। इसके उपाय के रूप में शासन का नियन्त्रण और बढ़ाया गया। अनेक नियामक संस्थाओं का निर्माण हुआ। इनसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने के स्थान पर केवल भ्रष्टाचार ही बढ़ा। शिक्षा क्षेत्र के भ्रष्टाचार ने आज सभी सीमायें लांघ दी है। सभी स्तरों पर गुणवत्ता का प्रचंड ह्रास हुआ है। यदि शीघ्र उपाय नहीं किया गया तो 10 वर्ष बाद हम पढ़े-लिखे मूर्खों का देश हो जायेंगे।

❑ मुकुल कानिटकर

भारतीय शिक्षा की परम्परा अति प्राचीन व अत्यन्त गौरवपूर्ण है। अनादिकाल से ही भारत ने सारे विश्व को मानवता की शिक्षा दी है। केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं, हर प्रकार की लौकिक शिक्षा भी भारत ने ही विश्व को दी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में भारत न केवल प्रगत था ही तो उनके शिक्षा की प्रगत विधि भी भारत में विकसित की गई थी। इसी कारण सारे जगत से यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते रहे है। हजारों की संख्या में आनेवाले छात्रों के लिये अनेक गुरुकुल भारत में चलते थे। इसी व्यवस्था के चलते भारत को जगतगुरु कहा जाता रहा है। 11-12 वी शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया उसके फलस्वरूप सैंकड़ो विश्वविद्यालय बंद कर उनकी ग्रंथसंपदा को सुरक्षित रखा गया। ज्ञान की सुरक्षा भारत के लिये सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बाद के संघर्षकाल में भी भारत में शिक्षा का वटवृक्ष फैला हुआ था। ग्राम ग्राम में उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था भारत में थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाने पर ही ध्यान दिया। देश के कोने कोने में चल रहे शिक्षा संस्थानों के भारतीय संस्कृति में योगदान के महत्व को सम्भवत: वे लोग समझ नहीं पाये।

इसी के चलते 1823 में अंग्रजों द्वारा किये गये देश के शैक्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि पूरे भारत में लाखों की संख्या में शिक्षा संस्थान थे। प्राथमिक शिक्षा तो लगभग सभी जनसंख्या को उपलब्ध थी। समाज के 76 प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा विभूषित थे। प्रख्यात स्वदेशी चिंतक धर्मपाल ने 1966 में लंदन के अभिलेखों किये अनुसंधान पर आधारित पुस्तक ''रमणीय ज्ञानवृक्ष'' में इस सर्वेक्षण को समग्रता से प्रस्तुत किया है। देश का दुर्भाग्य ही है कि 40 वर्ष हो जाने के बाद भी यह क्रांतिकारी पुस्तक हमारे किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। सर्वेक्षण में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में अनेक तथ्य उजागर हुए हैं। सभी वर्णों के बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश था। पढ़ाने वालों में भी शुद्रों सहित सभी वर्णों के शिक्षक हुआ करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि प्राचीन समय के जैसे ही 19 शताब्दि तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: स्वायत्त थी। शासन का कोई भी हस्तक्षेप शिक्षा में नहीं था। आर्थिक रूप से भी शिक्षा पूर्णत: स्वयं पूर्ण थी। 1823 के शैक्षिक सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि इस बात को स्पष्ट करती है।

1813 में कंपनी सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा सभी प्रकार की सार्वजनिक

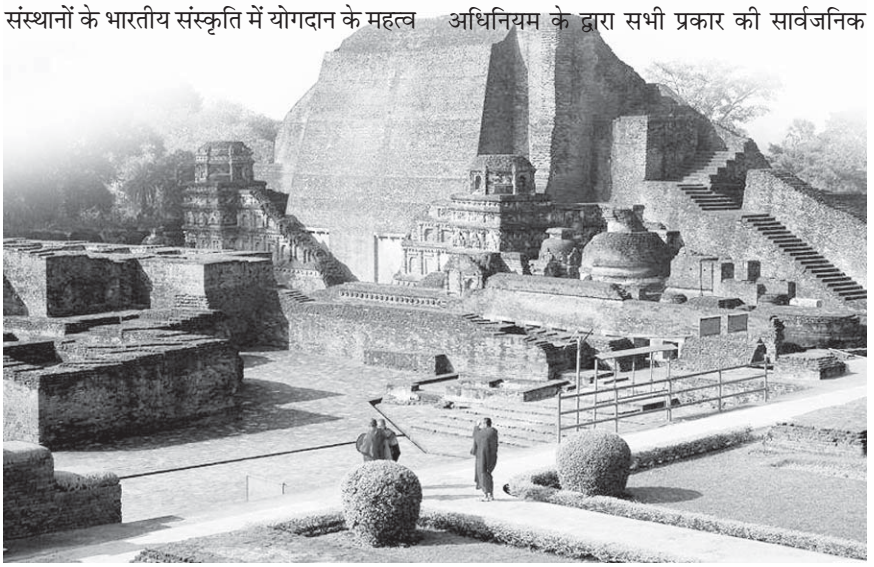

भूमि को शासकीय घोषित कर दिया। इसके द्वारा मंदिर से जुड़ी जमीन, गाँव में सामूहिक स्वामित्व की जमीन आदि के साथ ही शिक्षा संस्थानों की जमीन को भी शासन ने अपने स्वामित्व में ले लिया। इससे शिक्षा संस्थानों को चलाना कठिन व धीरे-धीरे असंभव हो गया। अनेक विद्यालय-महाविद्यालय बंद पड़ने लगे। तब कुछ प्रतिष्ठित भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप के लिये आवेदन आदि किये। शासन के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा की कि भारतीय शिक्षा संस्थानों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपयों का अनुदान दिया जायेगा। भारतीय इतिहास में यह पहला सरकारी शिक्षा अनुदान है। इससे पूर्व शिक्षा के सरकारीकरण का पाप द्रोणाचार्य को राज्यसेवा में रखने से हुआ था। उस महापाप का प्रक्षालन महाभारत के नरसंहार से हुआ। गत 180 वर्ष के पाप का प्रक्षालन ना जाने कितने रक्तप्रवाह से होगा।

इस अनुदान को बाँटने पर विधिक सलाह देने के लिये मैकाले नामक वकील को बुलाया गया। कितने शिक्षा संस्थान है जिन्हें अनुदान दिया जाय यह जानने के लिये पूरे भारत में शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया था। वकील मैकाले ने अपनी कुटिल बुद्धि से भारत की सर्वव्यापी, स्वायत्त, समाजाधारित, समृद्ध शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। 1835 में उसने शिक्षा का पूर्णत: सरकारीकरण कर दिया। भारतीयों को शिक्षा देने से कानूनन वंचित कर दिया। केवल कंपनी व ईसाई मिशनरियों को विद्यालय चलाने की अनुमति दी गई। मैकाले की शिक्षा नीति ने प्रथम बार शिक्षा में जाति के आधार पर प्रतिबंध लगाये। ब्राह्मणों के सिवा सभी जातियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। बाद में क्षत्रिय तथा वैश्यों के आवेदन करने पर इन्हें तो प्रवेश मिल गया पर असंगठित होने के कारण शुद्र शिक्षा से वंचित रह गये। कुछ ही दशकों में भारत का बहुजन समाज अशिक्षित हो गया। 1823 में जहाँ 76 प्रतिशत जनसंख्या सुशिक्षित थी आज स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी अपना नाम लिख पाने वाले को भी साक्षर समझ लेने के बाद भी केवल 74 प्रतिशत ही साक्षरता हो पायी है। यह अंतर है शासन निरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था व सरकारी व्यवस्था का।

स्वतंत्रता के बाद यह अपेक्षा थी कि अंग्रजों की व्यवस्था को बदल कर सही अर्थ में स्व के तन्त्र को लागू किया जायेगा। पर जिन लोगों के हाथ में शासन की बागड़ोर थी वे थे तो भारतीय पर मैकाले की व्यवस्था में शिक्षित -''दिखने में तो भारतीय पर अंदर से पूर्णत: अंग्रेज भक्त''। इन मैकाले पुत्रों ने अपने कतृत्व से अपने आप को मैकाले का बाप ही सिद्ध किया है। 1991 के बाद सब ओर जब निजीकरण का बोलबाला हुआ तब शिक्षा क्षेत्र में भी निजीकरण हुआ। किंतु यह केवल व्यापारीकरण था। सरकारी नियन्त्रण तो बढ़ता ही रहा है। स्वतंत्रता केवल लूटने की है। छात्र व शिक्षक का शोषण निजीकरण से बढ़ा। इसके उपाय के रूप में शासन का नियन्त्रण और बढ़ाया गया। अनेक नियामक संस्थाओं का निर्माण हुआ। इनसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने के स्थान पर केवल भ्रष्टाचार ही बढ़ा। शिक्षा क्षेत्र के भ्रष्टाचार ने आज सभी सीमायें लांघ दी है। सभी स्तरों पर गुणवत्ता का प्रचंड ह्रास हुआ है। यदि शीघ्र उपाय नहीं किया गया तो 10 वर्ष बाद हम पढ़े-लिखे मूर्खों का देश हो जायेंगे।

शासन निरपेक्ष शिक्षा ही वास्तव में गुणवत्तापूर्ण, सर्वव्यापी तथा शुचितापूर्ण हो सकती है। शासन निरपेक्ष का अर्थ निजीकरण नहीं है। निजी व्यापारियों के हाथ में शिक्षा सौंपना उपाय नहीं हो सकता। गत 25 वर्षों का अनुभव बताता हैं कि इस प्रकार के व्यापारिक निजीकरण से लाभ से अधिक नुकसान ही होता है। दूसरी ओर शासकीय संस्थानों में कर्म संस्कृति का पूर्ण अभाव पाया जाता है। काम करने के स्थान पर टालने के उपाय ही किये जाते है। आज हर स्तर पर पाठ्यक्रम पर पूरी तरह शासकीय नियन्त्रण हो गया है। अनेक अनुमतियों, सम्बद्धताओं और उनके वार्षिक नवीनीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार के साथ ही प्रशासनिक

नियन्त्रण बढ़ गया है। आज अनेक शिक्षाविद् कुलपति जैसे पदों पर आरूढ़ होते हुए भी शासन के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ही नहीं बाबूओं के सामने भी लाचार दिखाई देते है। अतार्किक नीतियों के कारण धन के होते हुए भी आवश्यक कार्यों पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। परिणामत: देश में अनुसंधान व नवोन्मेष के क्षेत्र में पूर्ण शिथिलता आ गई है। इस घोर तमस से शिक्षा व्यवस्था को उभारने के लिये केवल सरकार को ही नहीं पूरे देश को भी शिक्षा को प्रथम वरीयता की आवश्यकता मानकर उपाय करना होगा।

वास्तव में अपनी नई पीढ़ी को समय की आवश्यताओं के अनुसार जीवनोपयोगी शिक्षा देने का दायित्व समाज का है सरकार का नहीं। आज भी अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा आदर्श शिक्षा संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वैसे तो आर्थिक संसाधन भी समाज ही जुटा सकता है किन्तु जिस प्रकार आज शासन सर्वव्यापी हो गया है उसके चलते कम से कम कुछ दशकों तक तो आर्थिक भार शासन को ही वहन करना होगा। किन्तु नियन्त्रण, नियमन तथा संचालन में स्वायत्तता की ओर गति किये बिना कोई भी उपाय प्रभावी व परिणामकारी नहीं हो सकेंगे। स्वायत्तता का निर्णय शासन को ही करना है। शासन को ही अपने अधिकार कम करने का निर्णय लेना है अत: इसमें राजनयिक इच्छाशक्ति की प्रचण्ड आवश्यकता होगी। ऐसी इच्छाशक्ति या तो स्पष्ट वैचारिक प्रतिबद्धता से आती है अथवा लोकतन्त्र में जनमत के दबाव में। दोनों स्तरों पर प्रयास करने होगे।

वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था में शासन की भूमिका पर विचार करते समय शासन-निरपेक्ष शिक्षा के आदर्श को सामने रखकर उसे क्रमश: कैसे प्राप्त किया जाय इस पर विचार करना होगा। सबसे पहला कदम तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को समग्रता से संचालित करने के लिये पूर्णत: स्वायत्त शिक्षा आयोग स्थापित किया जाना होगा। वर्तमान में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व उच्चतर ऐसे भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि व शारीरिक शिक्षा आदि विषयों के अनुसार भी विविध नियामक है। इन सबके स्थान पर शिक्षा आयोग को पूरी शिक्षा को समग्रता से देखने का दायित्व दिया जाय। इससे समग्र व एकात्म शिक्षा नीति का विकास सम्भव होगा। इसी प्रकार के पूर्ण स्वायत्त शिक्षा आयोग राज्य तथा आगे जिला स्तर तक भी स्थापित करने होंगे। सच्चे अर्थों में स्वायत्त होने के लिये शिक्षा आयोग की संरचना पूर्णत: गैर राजनैतिक व गैर प्रशासनिक होनी होगी। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक की मंत्री भी इस आयोग के अधीन होने होंगे। समाज के सभी क्षेत्रों के सुयोग्य, प्रतिष्ठित व प्रामाणिक प्रतिनिधियों को ही आयोग में स्थान मिले। शिक्षा के संचालन, प्रायोजन, नियमन तथा नियन्त्रण का पूर्ण उत्तरदायित्व इस आयोग का हो।

आयोग का कार्य हो कि शिक्षा की स्वायत्तता को निचले स्तर तक लागू किया जाय। क्रमश: पाठ्यक्रम निर्धारण, नियुक्तियाँ तथा व्यय जैसे सभी कार्यों को जितना विकेन्द्रित रूप में कर सकेंगे उतना ही समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का विकास हो सकेगा। विभिन्न स्थानों की स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक अथवा व्यावसायिक अथवा सामान्य शिक्षा को वरीयता दी जा सकेगी। जहाँ जैसी परिस्थिति, आवश्यकता व विशेषता हो उसके अनुरूप शिक्षा का प्रावधान सम्भव होगा। नीति-निर्धारण के सभी स्तरों पर शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के सभी क्षेत्रों का सहभाग सुनिश्चित किया जाय ताकि शिक्षा केवल सैद्धांतिक ना रहकर व्यावहारिक भी हो सके। शासन की भूमिका प्रारम्भ में प्रेरक व पोषक की होगी। सकल उत्पाद के 10 प्रतिशत को शिक्षा हेतु आवंटित किया जाय तथा स्वायत्त शिक्षा आयोग के माध्यम से इसके सुनियोजित सम्पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जाय। शनै: शनै: समाज का आर्थिक योगदान बढ़ाया जाये व इस स्तर पर भी शिक्षा को शासन निरपेक्ष बनाया जाये। वर्तमान में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को विधिक दायित्व के रूप में अपने विशुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सामाजिक दायित्व (CSR) के प्रति व्यय करना होता है। इसका आधा हिस्सा शिक्षा आयोग को मिले ऐसा वैधानिक प्रावधान किया जा सकता है। अन्य कार्यों में भी समाज की भागीदारी ली जा सकती है। राजस्थान में भामाशाह योजना के माध्याम से शासकीय शालाओं में संरचना विकास में समाज की भागीदारी बड़े प्रमाण में होती रही है। पाली जिले के सभी विद्यालयों के भवन, फर्नीचर व अन्य शिक्षा सामग्री इस योजना से जुटाई गई। शिक्षकों व इतर कर्मचारियों का वेतन ही केवल शासन को देना पड़ता था। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि पूर्णत: शासन निरपेक्ष शिक्षा केवल आदर्श स्वप्न नहीं अपितु व्यावहारिक रूप से पूर्ण सम्भव है।

समाजोपयोगी, परिणामकारी, समग्र, व्यावहारिक, गुणवत्तायुक्त, सस्ती, सुलभ शिक्षा व्यवस्था के लिये शिक्षा को पूर्णत: शासन निरपेक्ष बनाना होगा। प्रारम्भ में नीति निर्धारण, पाठ्य रचना व शिक्षा पद्धति का निधारण सरकार के स्थान पर स्वायत्त आयोग को सौपना होगा। अगले चरण में शिक्षा के संचालन व प्रशासन को शासन से मुक्त करना और अन्तत: आर्थिक रूप से भी शासन पर निर्भरता को समाप्त करना होगा। तभी सच्चे अर्थों में शासन निरपेक्ष समाजाधारित शिक्षा व्यवस्था को साकार किया जा सकता है। यदि आज प्रारम्भ किया जाय तो देश के प्रगत राज्यों में एक दशक में और पूरे देश में 25 वर्षों में सबके लिये इस प्रकार की आदर्श शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ❑

(राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल)

शैक्षिक विकास की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार लें

स्वाधीनता के बाद देश का एक सबसे बड़ा हादसा यह रहा है कि जो शिक्षा मानसिक और वैचारिक बंधनों से मुक्त करने की सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए थी, वह शोषण का सबसे बड़ा अस्त्र बन गयी है। सच यह है कि हमारे देश में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अंतर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर नहीं शिक्षा के आधार पर है। वास्तविक रूप में देखें तो शिक्षा पुश्तैनी चीज बन गयी है। इसका यह अर्थ हुआ कि गरीब का बच्चा स्कूल जायेगा किन्तु अपनी आगे की शिक्षा जारी रख पायेगा, यह आज भी एक यक्ष सवाल बना हुआ है। यहां यह बात भी विश्वास करने लायक नहीं कि जिस देश के पास संसाधन हैं, प्रतिबद्धता और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वह स्वाधीनता के बाद साठ दशकों के बाद भी अपने सभी लोगों के लिए पर्याप्त और समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सका है।

❑ **बजरंगी सिंह**

भारत की शिक्षा की कहानी, कथनी और करनी, कामना और कर्म, प्रयास तथा परिणाम के बीच भारी अंतर की कहानी है। एक ऐसे समय में जब शिक्षा महत्तर सामाजिक न्याय की बात नहीं बल्कि आर्थिक विकास और संपदा सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण बन गयी है। हम विलम्ब, स्थगन और असमंजस की स्थिति बरकरार नहीं रख सकते। इस समय स्पष्ट दिशानिर्देशों और संकल्पयुक्त कार्य अतिआवश्यक है।

पिछले दशकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि शिक्षा की जरूरत जो हमेशा रही है, वह अब शिक्षा की मांग बन गयी है। इस प्रक्रिया में शिक्षा भी एक जिंस बनकर रह गयी है लेकिन जिस तंत्र पर इसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, वह एक बुनियादी ढांचे, कार्य और विषयवस्तु में सिमट कर रह गया है। यह भी वे चीजे हैं जिनका सृजन तब किया गया था जब बहुत कम संसाधनों के बावजूद शुरु-शुरु में इसकी पूर्ति ज्यादा थी और मांग कम। अब जब हम आर्थिक संसाधनों के साथ मांग के युग में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों की सामान्य आकांक्षाएं हैं कि इसकी उपलब्धता सहज और गुणवत्ता बेहतर हो और उन्हें विशेषत: शिक्षा के उच्च स्तर विकल्प वैविध्य और लचीलापन मिले। यहां तक कि पूर्ति प्रधान युग में भी अधिकांश नीतिगत दस्तावेजों में ऐसे लचीलेपन की आवश्यकता का उल्लेख है जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे लेकिन जो संरचना हम बना पाये वह अपरिवर्तनशील और संवेदनहीन थी। उसका उदय उस क्षैतिज विस्तार का परिणाम था जिसे वांछनीय नहीं माना जाता।

खास बात यह है कि सरकारी व्यवस्था पहले जहां प्रत्यक्ष लक्ष्यों और पहुंच सुनिश्चित करके के लिए निधियों के खर्च करके को अधिक महत्वपूर्ण मानती थी, वहीं अब वह विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षकों की भर्ती आदि का काम करके लगी है लेकिन जहां मानवीय तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, गुणवत्ता के मुद्दे प्रभावशीलता और कुशलता का सवाल होती है। यह व्यवस्था पूरी तरह विफल रही है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में जहां उच्च वर्गों के हित अधिक हैं, जल्दी परिवर्तन किये गये हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो वह क्षेत्र सुधार में काफी पीछे हैं।

इस समय महत्वपूर्ण काम यह है कि समाज में ऐसी क्षमता निर्मित की जाय जिसकी सहायता से शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। जब तक ऐसी क्षमता का निर्माण नहीं किया जायेगा, हम लोगों को शिक्षित नहीं कर पायेंगे

और जब तक हमारे पास काफी संख्या में शिक्षित और प्रशिक्षित लोग नहीं होंगे, हम क्षमताओं का सृजन नहीं कर सकेंगे। इस संदर्भ में गैर क्षैतिज विस्तार का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है।

यह सच है कि वर्तमान स्थिति इतनी बुरी है कि अगर सीखने में सुधार पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाये तो और भी बहुत कुछ करना होगा। बिना व्यवस्था को पुनरोन्मुख किये अथवा सुधारे अगर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है तो यह दीर्घावधि में पैसे की बर्बादी सिद्ध होगी।

स्वाधीनता के बाद देश का एक सबसे बड़ा हादसा यह रहा है कि जो शिक्षा मानसिक और वैचारिक बंधनों से मुक्त करने की सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए थी, वह शोषण का सबसे बड़ा अस्त्र बन गयी है। सच यह है कि हमारे देश में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अंतर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर नहीं शिक्षा के आधार पर है। वास्तविक रूप में देखें तो शिक्षा पुश्तैनी चीज बन गयी है। इसका यह अर्थ हुआ कि गरीब का बच्चा स्कूल जायेगा किन्तु अपनी आगे की शिक्षा जारी रख पायेगा, यह आज भी एक यक्ष सवाल बना हुआ है।

यहां यह बात भी विश्वास करने लायक नहीं कि जिस देश के पास संसाधन हैं, प्रतिबद्धता और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वह स्वाधीनता के बाद साठ दशकों के बाद भी अपने सभी लोगों के लिए पर्याप्त और समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सका है। इसके पीछे मुख्य कारण सरकारों की इच्छाशक्ति का मुख्य रूप से अभाव रहा है। यही वजह है कि शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय को भी हमने गंभीरता से नहीं लिया जो इधर-उधर के थोड़े प्रयास हुए वे नाकाफी थे।

आज की वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बन गयी है, जिस पर हमें निष्पक्ष और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मेरी दृष्टि में शिक्षा का समुचित विकास तभी संभव है जब सरकार आर्थिक मदद करे। अब तक ऐसा नहीं हुआ उल्टे शिक्षकों को निजीकरण की ओर धकेल दिया गया। अलग अलग राज्यों की अपनी-अपनी शिक्षानीति और व्यवस्था है। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा आज पूरी तौर पर व्यवसाय बन गयी है।

ऐसा नहीं है कि शैक्षिक विचारकों और पाठ्यक्रम निर्माताओं ने इस ओर समस्या से निपटने के प्रयास नहीं किये हैं। अनगिनत प्रतिवेदन सामने आ चुके हैं। समितियां बनीं और दर्जनों आयोग गठित हुए। उनके रिपोर्ट भी आ गयी किन्तु जो बात गायब रही वह थी हमारी अपनी शैक्षिक विचारधारा मानव का निर्माण करने वाली शिक्षा का कहीं अता-पता नहीं है। बस जगह-जगह स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय अनियोजित तरीके से खुलते जा रहे हैं। दुर्भाग्य यही रहा कि इन शैक्षिक सिद्धांतों को लेकर प्रयोग कम ही किए गये हैं जिसके ये अधिकारी हैं। सत्ता के केन्द्र पर जिनका नियंत्रण था वे उसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को विकसित करने तक सीमित रहे, जो पहले से मौजूद थी। कुल मिलाकर शैक्षिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से लोगों के विकास की बात शैक्षिक उद्देश्यों के केन्द्र से काफी दूर रही। मेरी राय है कि हमें स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ताकि समूचे देश में एक समान शिक्षा का विकास हो सके और समाज के हर वर्ग को अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। वर्तमान में जो स्थिति शिक्षा के विकास की है उससे समाज का बहुत बड़ा तबका शिक्षा पाने से आज भी वंचित है।

अच्छी शिक्षा तो उसके लिए दिवास्पप्न है।

इसके अलावा हमें राष्ट्रीय पाठ्य विषय, पाठ्य विवरण, पाठ्य सामग्री और अध्यापन साधन विकसित करने चाहिए जो मूल्योन्मुखी हों। वे मूल्य भी वस्तुपरक दृष्टि से निर्धारित किए जाने चाहिए और उनका आधार मानवीयता तथा विज्ञान हो। देश में केवल एक ही श्रेणी के स्कूल होने चाहिए इसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से सरकार को पूरा करना चाहिए जो नहीं हो सका।

हमें इस लायक हो जाना चाहिए कि हम अपने स्कूलों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का जैसे कि उपग्रह टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। किन्तु इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं। मोदी सरकार ने शिक्षा बजट बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने का वादा किया है। इससे यह उम्मीद जरूर बढ़ी है कि भविष्य में शिक्षा की दशा और दिशा दोनों सही पटरी पर आ सकेगी। अभी भी इस बात को लेकर विवाद बना हुआ है कि शिक्षा राज्यों को सहारे पूरी तौर पर छोड़ दी जाए या केन्द्र इसमें अपना हस्तक्षेप रखे। यह भी सही है कि शिक्षा के विस्तार में निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान है किन्तु उसके कारण जहां शिक्षा के बेतहाशा अनियोजित तरीके से विस्तार हुआ है। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यही नहीं इससे गरीब तबके के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आज भी वंचित रहना पड़ रहा है। सभी पढ़ें और सभी आगे बढ़ें यह तभी संभव है जब केन्द्र सरकार शिक्षा के विकास में अपना योगदान दे।

आज शिक्षा अर्थ की एक ध्रुवीय रचना में लगी है जो एक ओर आत्ममुग्धता के केन्द्र बनती है और दूसरी ओर मध्यवर्गीय लालचों को जन्म देती है। शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए इसका विरोध जरूरी है। शिक्षा के सबंध में इधर हमने सार्वजनिक रूप से चिंतन करना बंद कर दिया है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन यह अनायास नहीं है। इस चुप्पी का निहतार्थ यह है कि हमने इस शिक्षा व्यवस्था को सार्वजनिक स्वीकृति दे दी है। वैसे यहां पर यह सवाल पूछना वाजिब होगा कि सार्वजनिक स्वीकृति का गणित क्या है? सर्वजन कौन है? क्या वे मध्य वर्ग के लोग हैं जो किसी न किसी रूप में हमेशा वर्चस्वशाली, मुखर और व्यवस्थाओं के मालिक रहे हैं जिनकी चतुराई सारी सुविधाओं को अपने लिए बचा परोपकारिता की मुद्राओं का प्रदर्शन करते रहना है। क्या हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्थाओं की देखभाल और अपने हित की, अपने अभ्युदय को समृद्ध करके या कि अवसरों को बढ़ाने वाली बनाने का काम यही वर्ग करता है। फिलहाल यह स्वीकार करने में संकोच की जरूरत नहीं है कि पिछली कई शताब्दियों से हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की निगरानी करने वाला यही प्रभु वर्ग रहा है जो सम्पत्ति, जाति और भाषा के कारण कामयाब रहा है। प्राचीन से लेकर आज तक का इतिहास कुछ ऐसा ही है।

वर्तमान भारतीय शिक्षा का अध्ययन करके तथा इसकी ज्वलंत समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास में भारतीय शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करना तर्कसंगत ही होगा। भारत के शैक्षिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से विभिन्न कालों में बदलते स्वरूप का ज्ञान हो सकेगा। शिक्षक बदलते स्वरूप तथा तत्कालीन परिस्थितियों के विश्लेषण की सहायता से शिक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न व्यक्ति, समिति तथा सरकारें अतीत के उत्तर तथा वर्तमान में उपादेय बातों को अपनाये जाने का प्रयास कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अतीत से प्राप्त सफलताओं व असफलताओं तथा की गई त्रुटियों के परिणामों के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य की अनेक समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है तथा त्रुटियों से बचा जा सकता है। शैक्षिक योजना बनाते समय तथा उसका क्रियान्वयन करते समय एवं शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजते समय शिक्षा के इतिहास से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय शिक्षा के इतिहास को मोटे तौर पर पांच काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है। वैदिक काल में शिक्षा के केन्द्र एक ही व्यक्ति अर्थात गुरु तक केंद्रित थे। गुरु अपने त्याग, नि:स्वार्थ, सेवा, साधारण जीवन तथा विचारों द्वारा उसकी प्रगति में तन-मन व धन से लगा रहता था। छात्रों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना वह अपना धर्म समझता था। अपने प्रयासों द्वारा वह पूरा करता था। उस युग में शुल्क देने की परम्परा नहीं थी। शिक्षा समाजोन्मुखी थी। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था छात्रों को अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास करने के पूर्ण अवसर दिये जाते थे। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा के लगभग समान ही थे। अंतर केवल इतना था कि बुद्धकाल में आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर न देकर नैतिक अथवा शील पर अधिक जोर दिया जाता था। मुस्लिम काल में कोई नियमित तथा कोई व्यवस्थित शिक्षा योजना नहीं थी। परन्तु अधिकांश मुस्लिम शासकों के इस्लामी शिक्षा के प्रति पर्याप्त रुचि दिखलाई। अंग्रेजों के आगमन के साथ भारतीय शिक्षा नौकरी पाने का जरिया मात्र बनकर रह गई। दुर्भाग्य है कि उसी शिक्षा को हमने आज भी जारी कर रखा है। आज जरूरत है कि शिक्षा ज्ञान और अन्वेषण का केन्द्र बने और रोजी-रोटी का जरिया भी ताकि देश आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार शिक्षा पर होने वाले व्यय को खुद वहन करे और पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या की जिम्मेदारी शिक्षकों पर छोड़ दी जाए। शिक्षा का सार्वजनिकीकरण हो किन्तु बाजार के हवाले शिक्षा को न छोड़ा जाए। ❑

(स्तम्भ लेखक)

Mata

Sundha
Rope Way (P.) Ltd.

Works At :
Sundha Mata Temple, Vill.- Rajpura,
Distt. Jalore (Rajasthan)

E-mail : sundhamataropeway@gmail.com
Website : sundamataropeways.com/nimda

N.C. Agarwal
Managing Director

शिक्षा में शासन की भूमिका कैसी हो?

❑ डॉ. श्रीमती रेखा भट्ट

प्रारम्भ में शिक्षा किसी एक वर्ण-जाति तक सीमित थी। अतः उसमें शासन की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। समय के साथ शिक्षा में जाति, उम्र, लिंग भेद की सीमाएँ मिटती गई और शिक्षा का दायरा बढ़ता गया। इसके लिए आवश्यक संसाधन जैसे भूमि, निर्माण कार्य, शिक्षण के साधन, शिक्षकों को वेतन, नियुक्तियाँ आदि कार्य शासन तंत्र से ही अपेक्षित माने गये, परन्तु शिक्षण संस्थानों को कई सन्दर्भों में स्वायत्तता थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली (गुरुकुल व्यवस्था) का विलोपन भारत में अंग्रेजों के आगमन से प्रारम्भ हुआ और भारत में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया शासनाधीन होती चली गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी मान ली गई। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षण की सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ स्वतः शासन तंत्र पर निर्भर हो गयी।

शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य एक सुसंस्कृत व जिम्मेदार नागरिक बनता है। समाज कल्याण के शासन के कार्यों के तहत सामान्य सामाजिक अवधारणा रही कि शिक्षा को सर्वसुलभ करवाने का कार्य सदैव शासन का ही है।

प्रारम्भ में शिक्षा किसी एक वर्ण-जाति तक सीमित थी। अतः उसमें शासन की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। समय के साथ शिक्षा में जाति, उम्र, लिंग भेद की सीमाएँ मिटती गई और शिक्षा का दायरा बढ़ता गया। इसके लिए आवश्यक संसाधन जैसे भूमि, निर्माण कार्य, शिक्षण के साधन, शिक्षकों को वेतन, नियुक्तियाँ आदि कार्य शासन तंत्र से ही अपेक्षित माने गये, परन्तु शिक्षण संस्थानों को कई सन्दर्भों में स्वायत्तता थी। प्राचीन- भारतीय शिक्षा प्रणाली (गुरुकुल व्यवस्था) का विलोपन भारत में अंग्रेजों के आगमन से प्रारम्भ हुआ और भारत में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया शासनाधीन होती चली गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी मान ली गई। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षण की सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ स्वतः शासन तंत्र पर निर्भर हो गयी।

वर्तमान में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मुख्यतः तीन स्तर है - प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सरकारी निवेश तो किया जाता है किन्तु उसके परिणाम कितने प्रभावशाली रहे, इसे परखा नहीं जाता। इस प्रक्रिया के अभाव में सार्वजनिक तंत्र ने साक्षरता तो बढ़ाई है किन्तु बालकों में शिक्षा में निहित जीवन मूल्यों का विकास ठीक से नहीं हो पाया है। सार्वजनिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार के तहत तय समय सीमा में विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस कारण आज भी 14 लाख से अधिक बच्चे, विद्यालय का रुख नहीं कर सके हैं। उस पर भी शिक्षकों के अभाव के कारण अनुदानित पैरा शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य - महज एक औपचारिकता को पूर्ण करना है। निजी विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक अभी भी अपनी पहुँच नहीं बना पाये हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालयों में चल रहे मिड-डे-मिल (पोषाहार) कार्यक्रम एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षा पर होने वाले राजकीय खर्च को बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। आठवीं तक छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करने की प्रक्रिया ने शिक्षक को छात्रों की संख्या पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है। इस प्रकार शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों से विमुख हो रहे हैं।

अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा सबको मिले यह प्रतिमान केवल आवश्यक ही नहीं हो प्रभावी व गुणवत्ता युक्त भी बने। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर नियामक संस्था बने, जो इन संस्थानों के सतत् सम्पर्क में रहे। यह

नियामक संस्था शिक्षाविदों, बाल मनोवैज्ञानिकों के परामर्श से गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्धारण करें। विद्यालयों में शिक्षकों की नियमितता, उनके प्रशिक्षण, नवाचारों के प्रयोग में इस नियामक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के साथ ही उनके ड्रॉप-आउट में भी कमी आएगी। प्राथमिक स्तर पर इस संस्था का नियंत्रण संख्यात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिणाम भी देगा। प्राथमिक स्तर पर संस्कारों के माध्यम से बालकों में जीवन मूल्यों का विकास कर उनका सर्वांगीण विकास सम्भव है। अत: पाठ्यक्रमों और उनकी भाषा की बाध्यताको समाप्त किया जाना चाहिए।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा बालक को प्राथमिक से उच्च शिक्षा की ओर ले जाने वाली अवस्था होती है। इस स्तर पर भी शासन द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के प्रत्येक पायदान पर सतर्क अवलोकन के लिए नियमित सूचना तंत्र विकसित हो। उच्च माध्यमिक शिक्षा में यदि विद्यार्थी को संचार माध्यम से वास्तविक कक्षाएँ व आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाएँ तो उनका रुझान उच्च शिक्षा की ओर भी बढ़ेगा। जिला स्तरीय नियामक संस्था को अधिकार दिये जाए कि वह मानक परिणाम न देने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यालयों का विकास करें।

उच्चतर शिक्षा के तकनीकी प्रशासनिक व चिकित्सकीय क्षेत्र में हम नये आयाम छू रहे हैं। उच्च शिक्षा का यह क्षेत्र परिवर्तनशील होने से यहाँ निरन्तर विकास होता रहता है। उच्च शिक्षा के शेष नियमित पाठ्यक्रम आधारित उच्च शिक्षण संस्थान एक ही ढर्रे पर चलकर जड़वत् हो गए। अत: शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था के बीच हुए फासले को दूर करने के लिए इस स्तर पर भी एक नियामक तंत्र स्थापित हो। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण व विदेशी निवेश होने से संसाधनों में तो वृद्धि हुई है, किन्तु शिक्षण स्तर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। इन संस्थाओं में सार्वजनिक तंत्र के विपरीत, आर्थिक आत्मनिर्भरता के नाम पर भारी भरकम फीस वसूली जाती है। अत: सार्वजनिक नए संस्थानों की स्थापना के पहले, जीर्ण व रुग्ण संस्थानों का पुनरुद्धार हो, तो वे भी तकनीकी व प्रशासनिक संस्थाओं की तरह विकास के लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

अत: शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप शासन हर तरह से अपना सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार शासन की भूमिका में निम्न कार्य मुख्य रहे:-

1. प्रत्येक स्तर के शिक्षण की नीतियों और मापदण्डों का निर्धारण स्पष्ट रूप से हो। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर शिक्षाविदों की नियुक्तियाँ आवश्यक है।

2. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राजनीतिज्ञों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप समाप्त हो।

3. प्रत्येक स्तर पर आवश्यकतानुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाय।

तो देश में स्वत: ही एक ऐसे तंत्र का विकास होगा, जहाँ शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक राष्ट्र के सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में अपना सम्पूर्ण योगदान दे सकेंगे। ❑

(व्याख्याता, रसायन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.))

मैकालयी व्यवस्था का पोषक है शासनतन्त्र

देश में शिक्षा की बागड़ोर के माफिया के हाथ में जा चुकी है, प्रशासन अपने हित इसके साथ जोड़ कर चुपचाप मदद कर रहा है। शिक्षा में लाइसेन्स राज हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बिना लाइसेन्स कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पाती। परिवर्तन करे भी तो कौन? बात बाल केन्द्रित शिक्षा की की जाती है और प्रशिक्षण कक्षा आधारित शिक्षण का दिया जा रहा है। बात बस्ते का बोझ कम करने की जाती है और योजना किताबें भारी करने की बनाई जाती है। सरकार बदलने के साथ ही पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें बदल जाना शिक्षा के हित में तो नहीं है। परिणाम हम देख ही रहे है विश्व में ज्ञान का दीपक जलाने वाला भारत आज शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से विश्व बिरादरी में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। ज्ञान के सृजन में उसकी भूमिका नगण्य सी है।

❑ विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी

समग्र शैक्षिक परिवर्तन की बात करने का सीधा अर्थ यही निकलता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समग्रता में सही नहीं है। जब परिवर्तन की बात करते हैं तो पहला प्रश्न यह होगा कि परिवर्तन की दिशा क्या हो ? क्या हम किसी नई शिक्षा व्यवस्था की तलाश में हैं या पूर्व में प्रचलन में रही शिक्षा पद्धति में आई विकृति को दूर करना चाहते है? इस विषय में मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति अतिप्राचीन है और देश में अपनी सक्षम शिक्षा व्यवस्था रही है। उस शिक्षा व्यवस्था में आई विकृतियों को दूर कर वर्तमान के परिपेक्ष में पुन: प्रतिष्ठित करना ही हमारा अभीष्ट होना चाहिए।

मैकालयी शिक्षा से शिक्षित हुए लोग भारतीय संस्कृति के अतिप्राचीन होने पर विश्वास नहीं करते, मगर अब तो नवीनतम वैज्ञानिक तथ्यों से भी सिद्ध हो गया है कि भारतीय भूभाग पर मानव को निवास करते 70 हजार वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आधुनिकता में विश्वास करने वालों को भी अब शंका नहीं रहनी चाहिए कि संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा तथा देवनागरी लिपि जैसी वैज्ञानिक लिपि को विकसित करने वाले भारत में अपनी विकसित शिक्षा व्यवस्था रही है। वेदों व अन्य भारतीय शास्त्रों में वर्णित ज्ञान कपोल कल्पना नहीं मानव के हजारों वर्ष के अनुभवों का परिणाम है।

ब्रिटिश दस्तावेजों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 1818 से पूर्व भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था थी। उस शिक्षा व्यवस्था को क्या हुआ उसका विवरण भी मिलता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 1936 में ब्रिटिश यात्रा के समय प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक, इतिहासज्ञ, लेखक एच.जी.वेल्स से मिले थे। एच.जी.वेल्स का मानना था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को पहले मुगलों ने बरबाद किया होगा और फिर उसे और खराब करने के लिए मैकाले पहुँच गया जो घटिया साहित्य व लचर व्यवस्था द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर रहा है।

गुरुदेव ने वेल्स की बात का खण्डन करते हुए कहा ''मुगलों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कोई हानि नहीं पहुँचाई। मुगल शासनव्यवस्था अंग्रेजों की तरह चतुर व चालाक नहीं थी। मुगलों को अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए धन की आवश्यकता रहती थी। धन मिलने पर उन्होंने अन्य किसी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मुगल बादशाहों ने शिक्षा व्यवस्थापकों को किसी प्रकार का आदेश या निर्देश नहीं दिया। मुगलों के समय

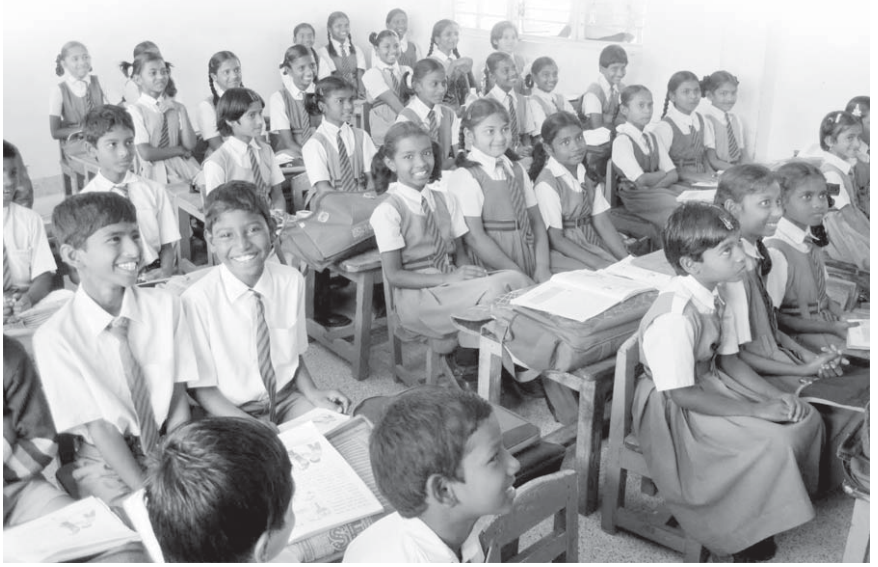

ग्रामीण भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को कोई हानि नहीं हुई। शिक्षा व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध होता रहा। अंग्रेजों ने सुनियोजित रूप से शिक्षा की ओर जाती धन स्त्रोत धाराओं को सुखा दिया है। भारतीय शिक्षा पद्धति को चलाने के लिए सरकार से अनुमति की बन्दिश लगादी गई है।''

इस पर एच.जी.वेल्स की प्रतिक्रिया थी कि शिक्षा के लिए सरकारी अनुमति का अर्थ शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना है। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की दृष्टि में मैकाले ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का हत्यारा था। वेल्स ने बताया कि तत्कालीन ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था भी भारत जैसी या उससे भी खराब थी। अधिकारी जनता से टैक्स वसूल करते थे और उसे मनचाहे तरीके से खर्च करते थे।

1947 में देश के आजाद होने से पूर्व ही देश में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात उठने लगी थी। देश स्वतन्त्र होते ही सुधार की आशा से शिक्षा आयोगों के गठित करने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ वह आज भी जारी है। इन प्रयासों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ और आज मैकालयी शिक्षा तन्त्र अंग्रेजों के जमाने से भी अधिक मजबूती से भारत में हावी है।

शिक्षा में माफिया राज

इसका कारण यह है कि अंग्रेज चले गए मगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधिपत्य के रूप में शासन करने का अंग्रेजी ढ़ाचा ज्यों का त्यों बना रहा है। इस प्रशासनिक व्यवस्था का हित मैकालयी व्यवस्था को बनाए रखने में था अत: सुधार के नाटकों के बीच भी मैकालयी ढ़ांचा मजबूत होता गया। प्रजातन्त्र के नाते शिक्षा प्रशासन का अधिकार कहने को तो जन प्रतिनिधियों के पास रहा मगर उन्होंने शिक्षकों के स्थानान्तरण, पदस्थापन व वोट बैंक की राजनीति के अतिरिक्त रुचि शिक्षा में प्रदर्शित नहीं की। यह भी माना जा सकता है कि वे इतने योग्य भी नहीं थे यथास्थिति का पोषण करने के अतिरिक्त कुछ कर भी सकते थे।

जिस देश में हर स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा की आदर्श व्यवस्था रही वहाँ पाठ्य पुस्तकों व परीक्षा के शिकंजे में कसी शिशु शिक्षा भी अविश्वसनीय रूप से मँहगी हो चुकी है। पेड़ की छाया में अच्छी शिक्षा देने में सक्षम रहे देश में भौतिक संसाधानों को ही अच्छी शिक्षा का पर्याय माने जाने लगा है। विदेशी भाषा में कोई देश उन्नति नहीं कर सका है इस तथ्य को जानते हुए भी देश में शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि देशी भाषा के विद्यालय घटिया शिक्षा के केन्द्र बन कर रह गये है। इस बाढ़ को रोकने का प्रयास करने की बजाय शासन स्वयं इस धारा में बहने लगा है। राजस्थान की भाजपा सरकार तो सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने की शुरुआत पर गर्व अनुभव कर रही है।

देश में शिक्षा की बागडोर के माफिया के हाथ में जा चुकी है, प्रशासन अपने हित इसके साथ जोड़ कर चुपचाप मदद कर रहा है। शिक्षा में लाइसेन्स राज हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बिना लाइसेन्स कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पाती। परिवर्तन करे भी तो कौन? बात बाल केन्द्रित शिक्षा की की जाती है और प्रशिक्षण कक्षा आधारित शिक्षण का दिया जा रहा है। बात बस्ते का बोझ कम करने की जाती है और योजना किताबें भारी करने की बनाई जाती है। सरकार बदलने के साथ ही पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें बदल जाना शिक्षा के हित में तो नहीं है। परिणाम हम देख ही रहे है विश्व में ज्ञान का दीपक जलाने वाला भारत आज शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से विश्व बिरादरी में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। ज्ञान के सृजन में उसकी भूमिका नगण्य सी है।

क्या हो शासन की भूमिका?

शासन यदि शिक्षा के प्रति गम्भीर हो तो सर्वप्रथम उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने में असमर्थ है। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा के संचालन हेतु एक स्वतन्त्र नियामक तंत्र की स्थापना करे जो देश की दीर्घ परम्पराओं व वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करे। शिक्षा संस्थानों के संचालन व अर्थ व्यवस्था में समाज की भागीदारी बढ़ावे। समाज के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रवृति के अनुरूप सभी स्तर की शिक्षा नि:शुल्क दी जाने की समान व्यवस्था करे। ऐसी व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवक राष्ट्र सेवा से कार्य करेगा पैसा कमाने के लिए नहीं।

अपने को आधुनिक समझने वालों को यह विचार पुरातनपंथी लग सकता है। कुछ लोग विज्ञान की उन्नति से जरूरत से अधिक अभिभूत हैं और पश्चिम को उस विज्ञान का जनक मानकर उसके पीछे चलने को ही श्रेयष्कर मानते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे मित्र विज्ञान को गहराई से नहीं समझ कर उसके सतही स्वरूप को ही देखते हैं। दुनिया को गहराई से देखें तो विज्ञान ने मानव को अपने पर्यावरण में तेजी से बदलाव करने की क्षमता ही प्रदान की है।

पश्चिमी विज्ञान का इतिहास कुछ सौ वर्ष से अधिक लम्बा नहीं है। मानव के अनुभवों का इतिहास सैकड़ों शताब्दियों पुराना है। अपने अनुभवों से प्रकृति के साथ साहचर्य बैठाने की जिन परम्पराओं का विकास मानव ने किया उन्हें अंधविश्वास कह कर त्यागना बुद्धिमता नहीं है। शाश्वत जीवन मूल्यों को आज भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाए जाने की आवश्यकता है। विद्या तथा अविद्या के सही मिश्रण से ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। तथाकथित विज्ञानभक्त इस बात को स्वीकार करे या नहीं करें मगर पश्चिम के अनेक वैज्ञानिक विज्ञान की सीमाएं समझ गए हैं। वे सृष्टि के मूलभूत प्रश्नों का हल खोजने का दम भरना छोड़ने लगे हैं। ❑

(बाल एवं विज्ञान विषयक लेखक)

शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक व शासन के प्रयत्नों से संभव

राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण एवं राजनैतिक विचारधारा से शिक्षा को प्रभावित करने के प्रयासों के कारण आधे-अधूरे मन से हुई शिक्षा नीतियों को लागू करने का जो लाभ मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाया है। समय-समय पर गठित आयोगों के सुझावों, शिक्षा सुधार हेतु विशेषज्ञों के प्रस्तावों को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर तत्कालीन सरकारों द्वारा अपनी इच्छानुसार क्रियान्विति करने के कारण लाभ के स्थान पर हानि हुई है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप को नीजि स्वार्थों में परिवर्तित कर दिया गया, अयोग्यता को आरक्षण का जामा पहना दिया गया। वोट बैंक की सुदृढ़ता हेतु शिक्षा का राजनीतिकरण हो गया। आज की आवश्यकता है कि राजनीति से ऊपर उठकर कुछ कठोर निर्णय लिये जायें। शिक्षा के संचालन की ऐसी व्यवस्था की जाये जिस पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के परिवर्तन का प्रभाव न पड़े।

❑ **बजरंग प्रसाद मजेजी**

स्वतंत्रता के पश्चात देश में शिक्षा क्षेत्र में भौतिक प्रगति तो हुई है। परन्तु राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर के प्रति आस्था, एकता की भावना, देश में उत्पादित वस्तुओं के प्रति अपनत्त्व का भाव, सहयोग, देश की गौरवमयी परम्पराओं, संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव शिक्षा के मूल्यों में गिरावट है। शिक्षा के जिस स्वरूप की कल्पना की गई थी, वह प्राप्त नहीं हो सकी है। समग्र शैक्षिक परिवर्तन की आशा वर्तमान में निराशाजनक है। राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण एवं राजनैतिक विचारधारा से शिक्षा को प्रभावित करने के प्रयासों के कारण आधे-अधूरे मन से हुई शिक्षा नीतियों को लागू करने का जो लाभ मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाया है। समय-समय पर गठित आयोगों के सुझावों, शिक्षा सुधार हेतु विशेषज्ञों के प्रस्तावों को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर तत्कालीन सरकारों द्वारा अपनी इच्छानुसार क्रियान्विति करने के कारण लाभ के स्थान पर हानि हुई है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप को नीजि स्वार्थों में परिवर्तित कर दिया गया, अयोग्यता को आरक्षण का जामा पहना दिया गया। वोट बैंक की सुदृढ़ता हेतु शिक्षा का राजनीतिकरण हो गया। आज की आवश्यकता है कि राजनीति से ऊपर उठकर कुछ कठोर निर्णय लिये जायें। शिक्षा के संचालन की ऐसी व्यवस्था की जाये जिस पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के परिवर्तन का प्रभाव न पड़े। इससे दो लाभ होंगे- 1. शिक्षा सुधार सम्बन्धी योजना लम्बे समय तक चलेगी। 2. शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का थोथा नारा नहीं लगाना पड़ेगा। समग्र शैक्षिक परिवर्तन अर्थात शैक्षिक उन्नयन के मुख्य रूप से तीन घटकों की भागीदारी मानी जाती है-

शैक्षिक विकास में बालक की ज्ञानार्जन करने के प्रति रुचि तथा शिक्षा का मनोभाव से प्रयत्न और परिश्रम तो आवश्यक है ही इससे भी अधिक उत्तरदायित्त्व सरकार का होता है। वर्तमान में विद्यालय के संचालन, प्रबन्धन शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम, भौतिक संसाधनों का जिम्मा शासन का ही है। इसलिये शासन का नियन्त्रण और प्रशासन का अधिक प्रभाव रहता है। केन्द्रीय शासन की यान्त्रिकता से मुक्त, कर विकेन्द्रीकरण के द्वारा राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं, परम्पराओं, संस्कृति, महापुरुषों के कार्यों-विचारों का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना आवश्यक है, तभी सामाजिक, राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है। शिक्षा की वर्तमान स्थिति में आवश्यकता है कि (1) देश में सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, (2) राष्ट्रीय भावनाओं का अभ्युदय हो, (3) असत्य और निराशाजनक तथ्यों का पाठ्यक्रम से विलोपन हो। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके आधार स्तम्भ इस प्रकार हो सकते हैं-

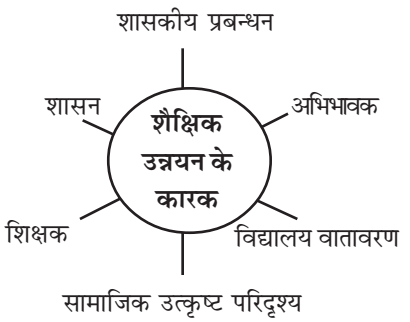

केन्द्र या राज्य सरकार जब भी शैक्षिक नवाचारों की योजना लागू करना चाहे, उससे पहले पूर्ण तैयारी की जानी चाहिये यथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों की आवश्यकतानुसार विषयानुसार नियुक्ति, पद सृजन, भवन एवं अन्य भौतिक संसाधनों की पूर्ती कर, दीर्घकालीन योजना की क्रियान्विति करे, जो राजनैतिक परिवर्तन से प्रभावित न हो। किसी भी योजना लागू करने से पहले शिक्षाविदों, शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों,

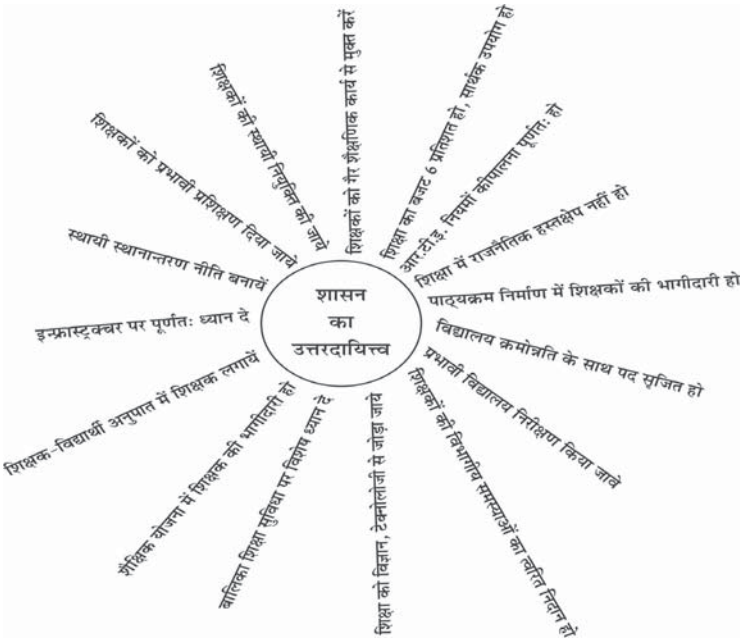

संगठनों से विशद चर्चा करके, सुझावों पर चिन्तन कर लागू करेंगे तभी लाभ अवश्यंभावी होगा। जहाँ तक विद्यार्थी, अभिभावक, समाज, शिक्षक से अपेक्षायें हैं उससे अधिक वर्तमान में शासन का उत्तरदायित्त्व है कि वह देश की शिक्षा पद्धति, व्यवस्था, नीति को कितनी ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि शिक्षा के विकास से ही देश की उन्नति संभव है। एतदर्थ शासन का उत्तरदायित्त्व है कि (मानव संसाधन मंत्री तथा राज्यों के शिक्षामंत्री) शिक्षाविदों, समाज सुधारकों, शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों के साथ गोष्ठी, चर्चा करके दीर्घकालीन योजना का निर्माण सार्वजनिक कर विचार आमंत्रित कर क्रियान्विति करें। शासन के उत्तरदायित्त्व के बिन्दु रेखांकित चित्र द्वारा दर्शाये गये हैं–

निष्कर्षत: कहा जाये तो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असमानता दूर करते हुये – 1. शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना 2. पाठ्यक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन 3. भविष्य के प्रति दृष्टिकोण को लेकर दीर्घकालीन योजना 4. पूर्णत स्वायत शिक्षा 5. नि:शुल्क शिक्षा का क्षेत्र उच्च शिक्षा में इंजिनियर, चिकित्सक, लेखा सेवाओं (सी.ए.) तक किया जाना चाहिये ताकि निर्धन विद्यार्थी भारी फीस न देने के कारण वंचित न रहे तथा उसकी ज्ञान मेधा का लाभ देश को दे सके। ❑

(कोषाध्यक्ष, अ.भा.रा.शै.महासंघ)

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

टांक शिक्षा निकेतन

पुलिस लाइन, अजमेर

सचिव

Need for Right Direction in Education System

Nationalism is basic point which need to be given prime importance. All other terms revolve around it, May it be society, region, sects, way of worship or profession etc. Economics and Security remain basic concerns. As can be seen in allocation of Planets lordship: Sun (King) and Moon (Queen) were given Leo and Cancer in zodiac signs, next was Mercury (Prince) which was given Gemini and Virgo, Venus depicting Treasure and Pleasures was allotted Taurus and Libra, Mars known for its fighting spirit termed as Leader of the Army got Aries and Scorpion, Before Jupiter (Guru) which was given Sagittarius and Pisces, and lastly Saturn depicting Servants and followers could get Capricorn and Aquarius. Thus it can be seen that Economics and Securities were given due importance right from ancient times.

❑ **Dr. A. K. Gupta**

In India Education was very much developed right from ancient time, we have rich literature available since then e.g. Vedas, Puranas, Upanishads, Philosophy, etc covering various fields e.g. Armory, Mathematics, Ayurvedas, Astronomy and Astrology to name a few. We see that so called educated person is not aware about culture of our country (Ref. Hamari Sanskritik Vichardhara ke Mool Shrot- Suresh Soni). In ancient times even agricultural activities were related to astronomical relations. Rural based works and those related to Cow were given due importance (Ref. GoSamvardhan avam Jaivik Krishi Vikas- Dr Rajesh Dube). Pleasure was not merely related to physical attainments but its spiritual gain which got priority. Prof Prafulla Chandra Roy:"We are not ashamed of our ancient contributions to the science of chemistry. I am equally proud of and not ashamed for all branches of science that grew in ancient India."

In 1835 Lord Thomas Bobington Macaulay recommended implementation of English Education system which slowly led to closure of Sanskrit Schools and made English schools compulsory. This system focused on objectives suitable to British Government ruling India.

Nationalism is basic point which need to be given prime importance. All other terms revolve around it, May it be society, region, sects, way of worship or profession etc. Economics and Security remain basic concerns. As can be seen in allocation of Planets lordship: Sun (King) and Moon (Queen) were given Leo and Cancer in zodiac signs, next was Mercury (Prince) which was given Gemini and Virgo, Venus depicting Treasure and Pleasures was allotted Taurus and Libra, Mars known for its fighting spirit termed as Leader of the Army got Aries and Scorpion, Before Jupiter (Guru) which was given Sagittarius and Pisces, and lastly Saturn depicting Servants and followers could get Capricorn and Aquarius. Thus it can be seen that Economics and Securities were given due importance right from ancient times.

Dr R Chidambaram, Principal Scientific Advisor to the Government of India, during his recent visit to Defence Laboratory, Jodhpur addressed august gathering on a relevant topic "Need for a knowledge Economy: For Development & For Security". Talking about the topic he touched various relevant issues, mainly stressing that proven technology becomes obsolete hence the need is to search for newer and better technology (Ref Current Science Vol 106, No7, 10th April 2014).

Only one way to achieve these goals is to unite with self respect, brotherlhood, quality fulfilled, disciplined, Industrious to work for upliftment of our Nation i.e. our Motherland India. Society remains prime focus for our activities. Fractured segments in the name of Regionalism, Language, Economic strata, Way of Worship etc should not affect our goals. Need of the hour is provide essential facilities in at least one institution in every state which can cater for research facilities and opportunities to students of the state & funded by the Central Government with at least half of the faculty from other places for better interaction and output.

India being second largest country in population get much attention at international level. This provides us good opportunity being a broad market to govern world Economy and share greater responsibilities in serving various sectors all over the world.

Time is just right to focus on giving right direction to Youth of the nation with full of energy and aspirations. With change in scenario at Central Government level all of us expect a gross change for better future of our Nation. One should think about many aspects before start to act upon: Demographic changes i.e. pattern of population growth considering different parts of the country, specialty of different parts based on resources natural and manmade, availability of resources to common person, limitations of applications, interaction at State or at international level, growth of human being and social customs, natural talent in any person and its identification and application for betterment.

Provisions of RUSA (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan) cannot be underestimated: Access, Equity, and Excellence should be given due weightage. Everybody should be treated at par so as to provide equal opportunities. Research with technological advancement and its application part should remain our focus. Government should focus ways to achieve these.

In the society presently ethical values and human qualities are observed to be declining. More attention is required to improve this aspect. Needless to say that formal and informal education go hand in hand. Thus family environment play an important role in this, then comes environment around the person concerned. education is a continuous process, everybody learns something or the other every moment throughout the life span.

Organised and unorganised sectors both should get due focus by considering these equally. Opportunities should remain available

at any time one wishes to continue his formal study. It should not be objective to educate by making them literate and learned but also to provide appropriate means to enable them for their earnings to look after their family responsibility with ethics being followed at all levels.

Our man power should find ways to compete at world level and make their mark. Here Our own system for Patents, Copy Rights, Recognition by different means e.g. impact factor etc should be generated and supported by the Government. Merely looking at West or somebody returned from Developed country should not be the only criterion to decide the merit. Proper weightage should be given to hard work and sincerity. Personality development is an important aspect which should not be ignored. A person who has enough knowledge and experience should be given opportunity to improve upon these aspects to overcome inferiority complex.

Teaching methods need more attention since improvement in a teacher will affect many to follow. More and more interaction among academicians and scholars is required to maintain parity of knowledge pool. Assessment is very important part which should be rationalised to boost morale of students as well as to escalate sense of responsibility in them.

Frequent interaction between academicians and industrialists is needed to fill the gap between them. Continuous development and growth of all sectors through these measures should remain our main motto. A student or a person should have opportunity to leave or to resume his educational pursuits as and when he/ she wishes to do so. Sir C V Raman:"Boys when we import, we not only pay for our ignorance but we also pay for our incompetence".

The objective is clear that the time has come to make our country leader in the field of Education and in particular Science and Technology by laying appropriate direction to follow. India is leading to be a younger aged Nation hence Education and Employment with Ethics should be the target. ❑

(Professor, JNV University, Jodhpur (Raj.))

Higher Education and the Role of State

On a final analysis, I am of the view that education should be state controlled, provided that the vision and wisdom of the state can be taken for granted. Bharat can now hope for strong and meaningful governance, and education ought to be fully under the present government. This is simply because the present government has a lot to do, in undoing the evils of the old and in recreating ancient Bharatiya knowledge tradition, a task, which is not going to be easy or simple. For Bharat, education has to be a long struggle, because the goal we shall have to set is of approximating the Vedopanishadic knowledge tradition and recreating the same in present context, time and space.

❑ **Dr. TS Girishkumar**

There ever remained a nexus; a very intimate nexus between what is education as such and the concerned nation state. As a matter of fact, I don't think that there can be any situation where education is de-linked or disconnected with the state rule perhaps at every point in time. Naturally, the extent and kind of influence, or 'patterning' the education system shall depend on the type of governance of a given state. This, of course, goes without saying, that 'in the event of a state having an established education system'.

To speak about states is also to speak about the form, or type of governance. With our present history of long existence of mankind, most of us had reached the same conclusion; among all known governances, democracy had been proven as the most practicable pattern, with all its shortcomings. But then, the best form of governance still remains a different one, of which there is hardly any dispute; and that is 'benevolent dictatorship', which is an ideal situation. One really cannot depend on 'benevolent dictatorship', simply because, 'benevolence' is such a thing that depends only on subjectivity of individuals. Even if we find a benevolent dictator, there is no guarantee that his benevolence shall last; or how long such a person can go on benevolent, and worse, for how many centuries one may have to wait for the next benevolent dictator. Withal these, we get back to square one, and democracy still remains the best form of governance, for all known practical reasons.

Bharat had both legend and history of many benevolent dictators, and they also had the same problem, after one person, there remained no guarantee that the next person shall also be another benevolent dictator. Nonetheless, Bharat had great rulers who could be termed benevolent dictators. Obviously, education used to be at its best under such circumstances, and Bharat also has evidences to this.

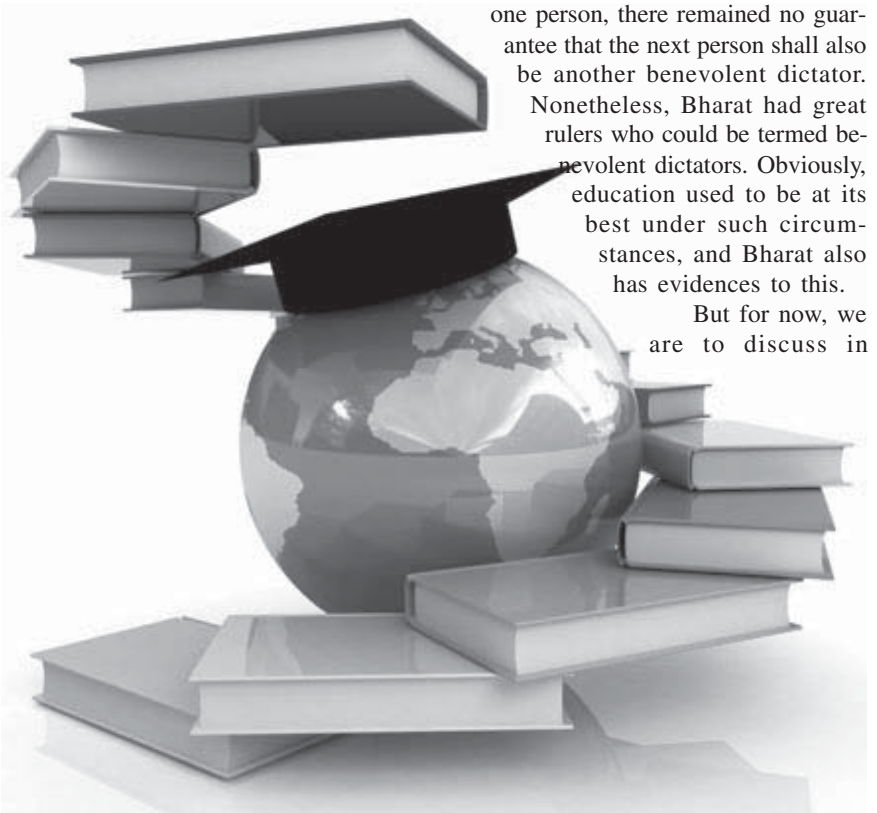

But for now, we are to discuss in

present terms, and that too, in the context of Bharat. The civilisation of Saraswati Valley and the Vedopanishadic knowledge tradition is no longer as vibrant as it used to be, we did considerably deviate from the Vedic traditions due to our own internal reasons before there was any invasion, and we find our own scholars struggling to recapture the Vedic knowledge tradition as they were going out of hands. Maharishi Aurabindo makes an excellent narration of this phenomenon in his 'Secret of the Veda' and was trying to logically speak of the struggle of ancient Bharatiyas to recapture diminishing Vedic knowledge access. Fortunately they did succeed, but to what extent, we are not very sure of.

It was under such lucid situations that Bharat had to face continuous invasions, long foreign rule from various invaders, until Bharat was officially declared independent in 1947. During the foreign rule, each distinct imposer made formidable attempt to 'pattern' education, given both their need and also fancy. Indeed there were always resistance from our ancestors, and very formidable resistance, but the influencing and patterning of education as desired by the alien rule also went on. Those Muslim invaders who subsequently settled to rule, became uncomfortable with the Vedopanishadic knowledge tradition, the Sanskrit language and even the Devanagari script. This made them to try to juxtapose Sanskrit with Persian, and Devanagari script with Persian script. With time, the situation in Bharat was that, every educated Muslim was using Persian as 'his' classical language as against the educated Hindu, whose classical language remained Sanskrit. This gave the birth of the concept of 'Urdu' which is not much different from Hindustani, and there were conscious efforts from Muslim scholars to replace Sanskrit words with Persian words as an ongoing phenomenon. Interestingly, the Persian obsession of Muslim intellectuals became a strange problem to them on many fronts, and the case of Jamaluddin Afghani is a classic example. Afghani is an additional name assumed by Jamaluddin on account of his Iranian origin to disguise himself as a Sunni and to conceal his Shia reality. His acceptance to majority Indian Muslims depended on this, and he executed this disguise completely with success. Jamaluddin Afghani had nothing to do with Afghanistan as such, but he posed as if he belonged to Afghanistan. He did not speak Pashtun, but spoke Farassi, and the Indian Muslims took his ability to speak in Persian as his scholarship. In reality, he was only speaking in his own mother tongue!

Perhaps this was the first negative impact on Bharatiya education system from the state, which went on a long way infiltrating into the very art, architecture music and perhaps to most performing art forms apart from other knowledge texts. Then comes the Europeans, the British being most prominent among them. The British were much more systematic as they already had their own pattern of education.

The McCauley and his introducing English education, the Max Muller and his 'cooked up' Aryan invasion theory etc. were all intended to mentally subjugate 'naturally proud' Bharatiyas, with the single aim of prolonging their colonial rule and making all Hindus Christians. However, these most meticulous attempts from the cunning of the colonial rulers also did not succeed, as there came great sons of Bharat like Swami Vivekananda, Maharishi Aurabindo and many such people who destroyed all their efforts.

The real infiltrating from state into education happens in post-independent Bharat, which is even a stranger case. The first prime minster himself was under communistic influences apart from his personal whims and fancies. That was a period when communists had already made their stand among the intellectuals on a global basis; the 1917 Bolshevik revolution still had its romantic grip among many. To be 'progressive was then synonymous with being communist, and on a normal course educated people had some attraction to communism and Karl Marx. Nineteenth century saw the European euphoria of science, Comte and positivism, Vienna circle and Logical Positivism which all went into the making of Existentialism and Sartre, Phenomenology, Hermeneutics, and linguistic analysis from Russell to Wittgenstein.

Eventually, books, periodicals, publishing, media etc. went into the hands of the so called progressive lot, who ranged from communist materialists to existential and phenomenological anarchists, who were mostly negative thinkers to put in a nut shell. The congress in rule were mostly trying to copy Europe, and whatever used to be the case in Europe also was recreated in Bharat, totally ignoring our original knowledge tradition and other established knowledge system. And most naturally the state continued its role of infiltrating into education and knowledge tradition.

As a result, from the time of the first invader to Bharat till present time, the state had only destroyed education system by blindly copying European phenomena without ever paying attention to an already established and complete knowledge tradition from ancient Bharat. Negative infiltration from the state used to be inadvertent in most cases as they themselves were victims of Eurocentric thoughts, but at times it also used to be wilful and arbitrary, with focused nefarious objectives.

Now to the prize question, what ought to be done? Shall we think in terms of completely delinking education from state and aspire for a total autonomy? Prima facie it may appear that education ought to be made autonomous and completely de-linked from the functions of the state. But then, this is not going to be of any good, or for that matter, any use. Earlier I discussed about benevolent dictators, and what is true of benevolent dictatorship is also true of this as well. Should education be made autonomous, then what shall be the guiding principles? There sure shall emerge autochthones of education in huge number with much shorter sights and insights, which shall be another anarchic situation.

On a final analysis, I am of the view that education should be state controlled, provided that the vision and wisdom of the state can be taken for granted. Bharat can now hope for strong and meaningful governance, and education ought to be fully under the present government. This is simply because the present government has a lot to do, in undoing the evils of the old and in recreating ancient Bharatiya knowledge tradition, a task, which is not going to be easy or simple. For Bharat, education has to be a long struggle, because the goal we shall have to set is of approximating the Vedopanishadic knowledge tradition and recreating the same in present context, time and space.

The postulates to these are simple.clear, and straight. First of all, we are convinced that the Vedopanishadic knowledge tradition is fool proof and complete. Secondly, we are aware that we have not lost them to considerable extent. Thirdly we are also aware that it is possible for us to recreate and reinvent them in our present time and space context. Maharishi Aurabindo makes such attempts and his efforts are very instructive. There are also many other great minds of our ancestry, like Swami Vivekananda himself, who had done much work for us to simply understand and follow.

What shall be of intense necessity is that the nation ought to create a band of 'national teachers'. These teachers ought to be trained, and shifted from place to place and institution to institution on a timely basis, say three years. The nation ought to take only volunteers from both existing and fresh teachers, who shall be prepared to undergo six months military training, willing to go and work anywhere in Bharat, and also they shall teach in Military academies to instil the past, glory and future of our nation to the soldiers, whose moral strength belongs to Swabhimana in being born a lucky son of Bharat. The stronger consciousness of Bharat, the stronger shall be our Swabhimana, and the stronger our Swabhimana, the stronger and integrated shall our nation be. ❑

(Professor of Philosophy, The Maharaja Sayajirao University of Baroda)

केशव विद्यापीठ समिति

जामडोली, जयपुर, राजस्थान, टेलीफोन न : 0141-2680344, 719

Email Id - info@keshavvidyapeeth.com, web site - www.keshavvidyapeeth.com

25 वर्षों से शिक्षा – सेवा के माध्यम से शाश्वत जीवन मूल्यों द्वारा व्यक्ति निर्माण हेतु समर्पित संस्थान केशव विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार की पुण्य स्मृति में उनकी जन्मशती के अवसर पर 18 मार्च 1988 को जयपुर से 10 कि.मी दूर की गई। हमारा लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से शाश्वत मूल्यों की स्थापना कर युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाना एवं समाज, राष्ट्र कार्य हेतु प्रेरित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न संस्थानों का संचालन हो रहा है। केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन में विभिन्न संस्थानों की प्रबन्ध समितियाँ अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत हैं।

केशव विद्यापीठ जामडोली, जयपुर, कार्यकारिणी समिति (2012-2015)

संरक्षक	:	श्री रामलक्ष्मण गुप्ता, श्री राधेश्याम धूत	अध्यक्ष	:	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
सचिव	:	इ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	उपाध्यक्ष	:	श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल
कोषाध्यक्ष	:	सीए. अशोक ताम्बी	उपसचिव	:	श्री देवेन्द कुमार शर्मा
सदस्य	:	श्री वीरु सिंह राठौड़, श्री शंकरलाल अग्रवाल, श्रीमती आशा गोलचा			
सहवरित सदस्य	:	श्री राजदीपक रस्तोगी, श्री अशोक डीडवानिया, श्री सुरेश उपाध्याय, श्री अनन्त ताम्बी			
पदेन सदस्य	:	श्री शिव प्रसाद, श्री भरतराम कुम्हार, श्री बनवारीलाल नाटिया, श्री अमरनाथ चंगोत्रा			
स्थाई आमंत्रित	:	श्री दुर्गादास जी, श्री प्रकाश चन्द जी, श्री शिवलहरी जी, श्री रामप्रसाद जी एवं केशव विद्यापीठ समिति द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर			

शंकरलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर ☎ 2680932

अध्यक्ष : श्री सुरेश उपाध्याय — मंत्री : श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा

कक्षा 6 से 12 तक विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का पूर्ण आवासीय विद्यालय जहाँ गुरुकुल पद्धति पर आधारित आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारयुक्त स्वस्थ वातावरण द्वारा बालक का सम्पूर्ण विकास किया जाता है। ज्ञान कौशल, शारीरिक दक्षता, भाषा, कला, केरियर मार्गदर्शन द्वारा बालक को विश्वस्तरीय स्पर्धा के योग्य बनाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा हेतु तैयारी की व्यवस्था है।

दामोदर दास डालमिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर ☎: 2680439

अध्यक्ष : श्री रामावतार तैवा — आधुनिक शिशुवाटिका से कक्षा 12वीं तक का अनिवासीय विद्यालय — मंत्री : श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा

ब्रह्मचारी श्री रामानुजाचार्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ☎: 2680455

अध्यक्ष : डॉ. शांतिपूर्णा गुप्ता — कक्षा 3 से 12 तक कला, वाणिज्य संकाय का श्रेष्ठ कन्या विद्यालय — मंत्री : श्रीमती सीमा जुत्का

KRISHNA GLOBAL SCHOOL ☎: 2680961

Play Group to Class II - An English Medium Co-Education School

श्री गौरीशंकर बिहाणी महिला महाविद्यालय ☎: 2680961

अध्यक्ष : डॉ. नन्द किशोर पाण्डे — महिला उच्च शिक्षा का श्रेष्ठ संस्थान — मंत्री : श्री अजय गोयल

देवीदत्त डालमिया शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ☎: 2680076

अध्यक्ष : श्री गोपाल सैनी — संस्कार युक्त शारीरिक शिक्षा हेतु देश का श्रेष्ठ संस्थान — मंत्री : श्री प्रकाश नारायण पारीक

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय सी.टी.ई. ☎: 2680466

श्री अग्रसेन शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय

अध्यक्ष : श्रीमती आशा गोलचा — श्रेष्ठ शिक्षक निर्माण एवं शोध कार्य में देश का प्रमुख संस्थान — मंत्री : श्री जगदीश प्रसाद सिंघल

भगवानलाल रामलाल रावत इण्डोस्विस चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल ☎: 2680209

अध्यक्ष : डॉ. एस.बी. झँवर — नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से सेवारत — मंत्री : डॉ. गिरधर गोयल

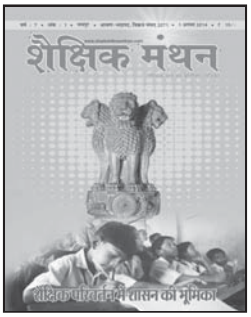

Education is essential for individual and collective progress. Education affects economic growth by increasing the productivity of the labour force. It encourages innovation which may lead to the creation of new technologies, products and processes. According to the World Bank report, education also helps in the "assimilation and diffusion of the knowledge needed to effectively use technology devised by others." Clearly, a large chunk of uneducated adults represents a huge loss of potential for the nation. "About 30% to 35% of children in India do not complete the minimum requirement of eight years of schooling. In additon to impacting the country's human resource, this violates the Right to Education guaranteed to every child in the India Constitution,"

A recent UN report shows that more than a million children between the ages of six and eleven years are out of school. This represents a real loss of potential for the country.

More than a Million have no School and no Hope for the Future

❑ **Poulomi Banrjee**

Every morning, Shiva (7) takes an autorickshaw to work. Accompanying him from his home in east Delhi are his two younger siblings and a neighbour. Shiva spends his day in central Delhi's Janpath area selling pens, four for Rs. 20, to the office crowd, shoppers and tourists, sometimes asking for an ice cream from any one who looks kind enough to indulge him. He is unsure of his daily earnings. "He doesn't have a mother and his father is ill and stays at home," his neighbour explains. Shiva has never been to school and has no hope of ever going to one. "I can't read," he says, a trifle wistfully.

There are many like Shiva, who sell flowers or toys on the streets of India's cities, work on farms, do odd jobs at restaurants, beg for a living or just while away their time when they should rightfully be in school. According to UNESCO's recently published annual Education For All Global Monitoring Report, there are 57.8 million children in the age group of six to 11 years who are out of school. 1.38 million of these are in India. India has the fourth highest number of out-of-school children in this age group. Pakistan is at number two with 5.37 million out of school children at the primary level.

"In terms of the proportion of OOSC (out of school children) at the primary level it was 1.1% in 2011. It is based on the population of children between 6 and 10," says Shailendra Sigdel, statistical advisor for South Asia, UNESCO. This means the Adjusted Net Enrolment (ANER) is 98.9% at the

primary level. However, according to the figures, the NER of recent years has gone down. The recent publication DISE: 2013-14 Flash Statistics shows 88.08% Net Enrolment. "As UNESCO collects data on administrative data we are not in a position to say that 'they were never enrolled or whether they attended school or not'. The OOSC number presented here is the number of children not enrolled on a particular day of survey," Sigdel explains.

The UNESCO figures are appalling. However, some education experts believe the numbers need to be viewed in perspective. "If we have approximately 200 million children in the age group of 6 to 11 years, 1.4 million is not as bleak a number as it seems when seen in isolation," says professor R Govinda, vice-chancellor, National University of Education Planning and Administration. Shailendra Sharma, executive director, Pratham (New Delhi), a non government organisation agrees: "According to recent studies, 96% of children in rural India are enrolled in schools. However, attendance is often not as good. On a given day, only 70% are found in class".

The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A to provide free and compulsory education as a fundamental right to all children in India in the age group of six to 14 years. The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, means every child has a right to full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. Article 21-A and the RTE Act came into effect on 1 April 2010. To achieve the goal of providing elementary education to every child, the country also

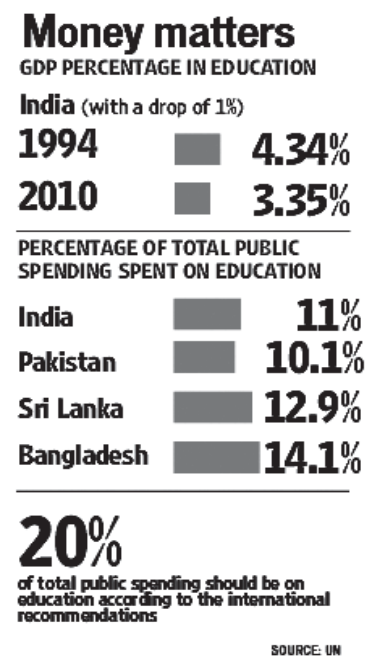

introduced the Sarva Shiksha Abhiyan in 2000-2001. The aim was to boost universal access to education, to retain students in school, to bridge gender and social category gaps in elementary education and to improve the quality of learning. Sarva Shiksha Abhiyaan interventions include the opening of new schools and alternate schooling facilities, the construction of schools and additional classrooms, providing toilets and drinking water facility in schools, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks and support for learning achievement. To boost enrolment, retention and attendance, while also improving nutritional levels in children, India introduced the National Programme of Nutritional Support to Primary Education as a centrally sponsored scheme on August 15, 1995, which became the cooked Midday Meal Scheme in 2001.

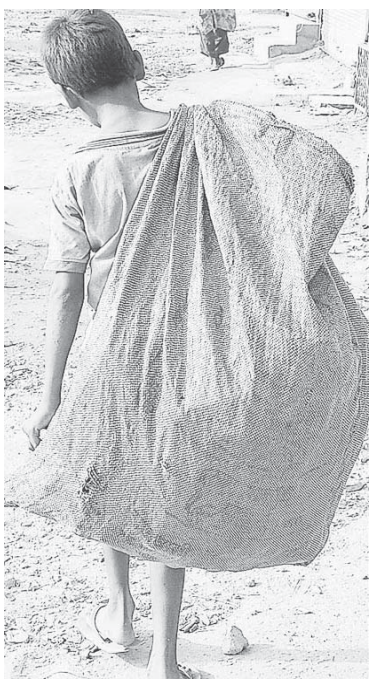

All this is very well but what explains the drop in expenditure on education that shows up in the UNESCO study? "Our data shows a reduction on education in terms of GDP proportion to education sector. The UNESCO Institute of Statistics (IS) database shows the GDP percentage in the education sector was 4.34% in 1999 and it has gone down to 3.35% in 2010," says Sigdel. Education commands only 10.1% and 11% of total public spending in Pakistan and India, respectively compared with the international recommendation of 20% of total public expenditure. The rate also remains low in Sri Lanka at 12.9% and Bangladesh at 14.1%. Domestic experts, though, feel the problem is not a lack of funds but a need to reorganise the expenditure of resources for maximum benefit. In the Eleventh Five Year Plan, total public expenditure on education increased by 4.6 folds. "However, often these resources are not properly utilised," says Shailendra Sharma. For example, according to media reports Rs. 60 lakh had been sanctioned by

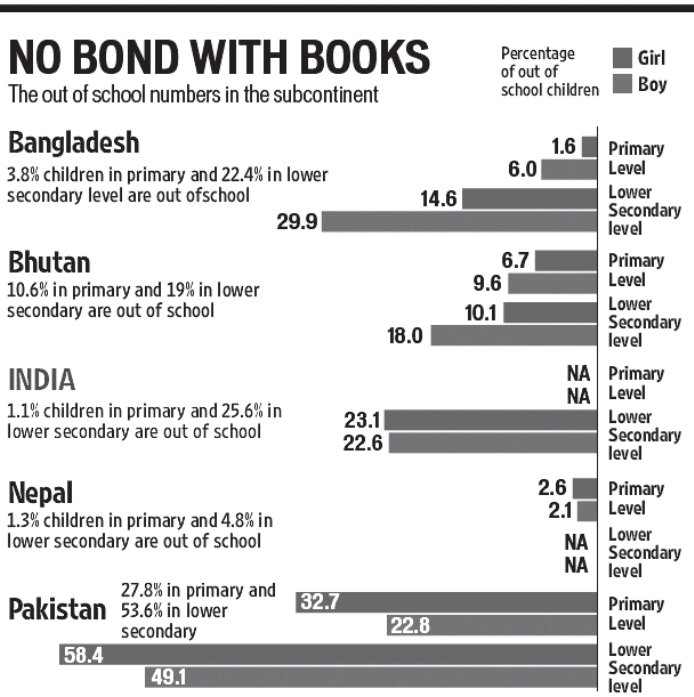

Amongst children who are out of school, there is a group that is likely to never enter primary school. This is affecting a strikingly high proportion of excluded children in Pakistan (51 percent) and in India (39 percent)

- From a theoretical perspective, there are at least three ways in which education may affect economic growth : (a) increase the productivity of the existing labour force, (b) by increasing the innovative capacity of the economy, education may lead to the creation of new technologies, products, and processes, and (c) help in the assimilation and diffusion of the knowledge needed to effectively use technology devised by others.

the government for the expansion of a school in Solan in Himachal Pradesh. The funds remained unutilised for three years because of unavailability of suitable land for expansion. Finally, the funds were transferred to Shimla. Often, in spite of funds being available, bureaucratic reasons delay the appointment of teachers. "Lack of ideas and not lack of funds is the mainn problem," insists Sharma.

Similarly, while UNESCO lists "child ld labor, poverty (as low economic quintile have less access to school than rich quintile), insufficient school infrastructure and lack of teachers," as barriers to schooling in India, Pakistan and Sri Lanka, Sharma blames the poor quality of education as the key factor for low turnouts at school. According to UNICEF's South Asia Regional Study report, "the incidence of child labour varies from 3% in Sri Lanka to 16% in Pakistan. In India and Bangladesh, an estimated 12.2% and 9% of children are engaged in child labour. In all four countries, school attendance rates for child labourers are lower than for other children of the same age." Sharma says poverty is no longer the key reason that keeps children away from school. "We now need to review our classroom process, check what we are offering these students. What kind of skills are they picking up? A big percentage of these government school students are first generation school goers. We can't expect learning support for them at home," he says, adding that teachers need to adapt their style to suit these students. "Or else these children drop out of school and engage themselves in work. The Annual Status of Education Report 2013 revealed that about 53% of students studying in grade five in government schools cannot read texts meant for students of grade two. However, 28% of students in rural India today are enrolled in private schools and the number is rising. "This shows a demand for good education. We have to increase the time devoted to these students in school. Some of our schools are so small that they are unable to provide the kind of facilities required for the students," says Govinda.

And then there's the question of the impact of poor nutrition on learning ability. A recent World Bank report (Student Learning in South Asia: challenges, opportunities and policy priorities) on the quality of education in south Asia, stresses on early childhood nutrition as a priority to improve learning outcomes. The report talks of the need for effectiveness and accountability of teaching staff, of financing as a tool to improve the quality of education, and about leveraging the contribution of the private sector. It also talks of the need to expand access to schooling for disadvantaged populations and to improve learning outcomes. UNESCO's Education for All drive

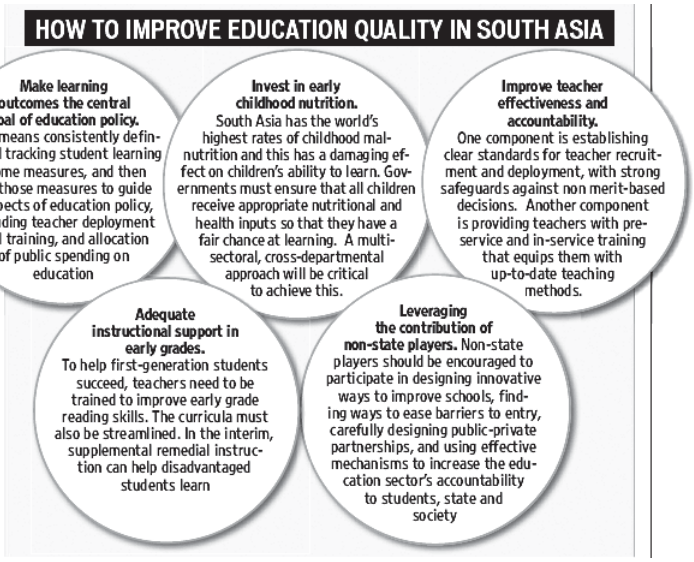

aims to see every child in school by 2015. Among children who are out of school, there is a group that is likely to never enter primary school. This is affecting a strikingly high proportion of excluded children in Pakistan (51%) and India (39%), according to the UNICEF report.

Education is essential for individual and collective progress. Education affects economic growth by increasing the productivity of the labour force. It encourages innovation which may lead to the creation of new technologies, products and processes. According to the World Bank report, education also helps in the "assimilation and diffusion of the knowledge needed to effectively use technology devised by others." Clearly, a large chunk of uneducated adults represents a huge loss of potential for the nation. "About 30% to 35% of children in India do not complete the minimum requirement of eight years of schooling. In additon to impacting the country's human resource, this violates the Right to Education guaranteed to every child in the India Constitution," Govinda says. Sadly, all this means little to children like Shiva, who spend their days on the streets attempting to earn enough to buy their next meal. ❑

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

संस्कृति पब्लिकेशन

पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता

संस्कृति पब्लिकेशन 23, शिष्य काम्पलेक्स,
डॉ. राजेश चौहान के दवाखाना के नीचे, डेरी रोड,पालनपुर(गुजरात)
चल दूरभाष :- 07802082131

Education Budget falls short of expectations

People expected the new government to initiate major reforms in education, particularly higher education, but the budget "suggests nothing remarkable," says Jandhyala B G Tilak, head, department of educational finance, National University of Educational Planning and Administration. "It does not seem to indicate any major significant direction for development of the education sector, though a few points are worth noting, such as allocation or provision of drinking water and toilet facilities in schools, and a couple of new initiatives such as school assessment programme and a (Rs 100 crore) young leader programme (to promote leadership skills)."

The Union budget falls short of expectations with no 'clear direction', experts say while welcoming proposals such as drinking water and toilets in schools, skill training and school assessment.

People expected the new government to initiate major reforms in education, particularly higher education, but the budget "suggests nothing remarkable," says Jandhyala B G Tilak, head, department of educational finance, National University of Educational Planning and Administration. "It does not seem to indicate any major significant direction for development of the education sector, though a few points are worth noting, such as allocation or provision of drinking water and toilet facilities in schools, and a couple of new initiatives such as school assessment programme and a (Rs 100 crore) young leader programme (to promote leadership skills)."

Further, experts do not cheer the proposal for new institutions, particularly IITs and IIMs, due to known issues in existing institutes. "It is necessary that expansion plans are well-designed, with adequate public funding for these institutions to become viable and sustainable, if not world-class," says Tilak.

Lakshmi Iyer, director and head of education, Sannam S4 Consulting, points out that India has 13 IITs and 16 IIMs, with a "caste system" between the old players and the new ones opened in the past decade. "We know the existing IITs and IIMs have problems that need fixing from filling faculty vacancies, adequate facilities for students and upping their game with respect to research output and competing on a global platform. Capacity-building is not about buildings and labs. It is about teachers, quality, good value education and I wonder if we are going to continue making announcements of adding more without getting down to the business of stemming the rot in education," she says.

Delhi-based career counsellor Pervin Malhotra, too, expresses mixed feelings. "There is no clear direction emerging from the Union budget 2014. Increasing the number of IITs and IIMs is a symbolic gesture which has happened earlier and which makes a great media splash, but the fact is, a miniscule percentage of the population gets into these institutions. What about the majority and making them employable?" Skill training, as proposed in the budget, can help curb unemployment, she says. "However, there is nothing on upgrading the thousands of government schools so as to ease the pressure on parents to put children into private schools. That being said, not ev-

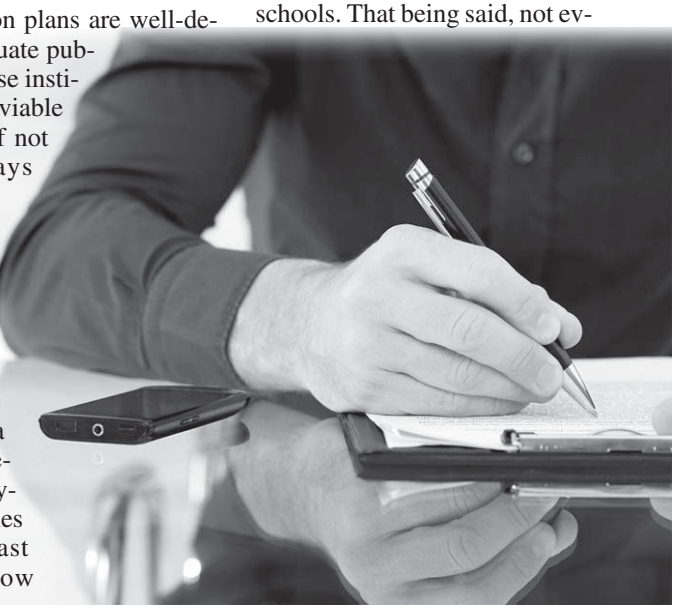

erything the government intends to do is determined by the Union budget."

Further, the announcement of biotech clusters in Faridabad and Bangalore is "promising and shows that the government understands that India needs to get its act together in STEM areas," says Iyer. As regards the Rs 100 crore for e-classes, it will be important to credentialise the competencies people gain in virtual classrooms, she adds.

THE PROPOSALS

Loo and behold

- Toilets and drinking water in all girls school. Rs 28,635 crore for Sarva Shiksha Abhiyan and Rs 4,966 crore for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
- Rs 30 crore for a new School Assessment Programme. To 'infuse new training tools and motivate teachers', Pandit Madan Mohan Malviya New Teachers Training Programme being launched with an initial sum of Rs 500 crore
- Rs 100 crore to set up virtual classrooms as Communication Linked Interface for Cultivating Knowledge (CLICK) and for online courses
- Rs 500 crore for a National Rural Internet and Technology Mission for services in schools, training in IT skills, etc
- Rs-100 crore Beti Bachao, Beti Padhao Yojana to create awareness and for better delivery of welfare services for women.

More colleges

- A Jai Prakash Narayan National Centre for Excellence in Humanities in Madhya Pradesh
- Five new IITs in Jammu, Chhattisgarh, Goa, AP and Kerala
- Five IIMs for HP, Punjab, Bihar, Odisha and Maharashtra
- Simple norms for education loans for higher studies
- 2 National Institutes of Ageing at AIIMS, Delhi and Madras Medical College, Chennai. A national research and referral Institute for higher dental studies in an existing dental institution
- 4 more AIIMS-like institutions at AP, WB, Vidarbha (Maha.) and Poorvanchal (UP) under consideration
- 12 more government medical colleges
- Film & Television Institute, Pune and Satyajit Ray Film & Television Institute, Kolkata, to become institutes of national importance
- A National Centre for Excellence in Animation, Gaming and Special Effects
- Rs 200 crore for agriculture universities in AP and Rajasthan and horticulture universities in Telangana and Haryana
- Rs 100 crore for 2 Indian Agricultural Research Institute-Pusa-like institutions of excellence in Assam and Jharkhand
- National-level sports academies for major games in different parts of India

Skills

A national multi-skill programme, Skill India, to focus on employability and entrepreneurial skills

People with disabilities

- National-level institutes for universal inclusive design and mental health rehabilitation as well as a Centre for Disability Sports
- To meet the demand for Braille textbooks, assistance to state governments to start 15 Braille presses and modernise 10 ❑

लाइसेंस राज में फँसी शिक्षा

❑ तवलीन सिंह

यूजीसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए इस तरह शिक्षा की बारीकियों में जाने का। यह अधिकार वाइस चांसलर साहब का ही होना चाहिए लेकिन जो शिक्षक और बुद्धिजीवी उनके समर्थन में निकल कर आए थे क्यों नहीं उन्होंने यही अधिकार उन कॉलेजों के लिए मांगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत जबर्दस्ती लाए जाते हैं? क्यों नहीं उस लाइसेंस राज के खिलाफ आवाज उठाई जो भारतीय उच्च शिक्षा के लिए जानलेवा बन गया है? आज अगर भारत की आला शिक्षा संस्थान दुनिया की आला शिक्षा संस्थाओं में नहीं गिनी जाती है तो कारण है यह लाइसेंस राज। मानव संसाधन विकास मंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं हम कि देश को क्या लाभ मिला है इस लाइसेंस राज से? इसके होते हुए नहीं बन पाए हैं वह कालेज, वह विश्वविद्यालय जिनके बिना भारत के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

भारतीय शिक्षा की बीमार अव्यवस्था का प्रतीक हैं, छात्रों की वे लंबी लाइनें जो लग जाती हैं विश्वविद्यालयों में हर साल इस महीने। जिंदगी की तमाम उम्मीदों को लेकर आते हैं ये बच्चे, जो जानते हैं कि वे काबिल हैं, जो जानते हैं कि उनके नतीजे अच्छे हैं लेकिन यह भी जानते हैं कि उनको शायद दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि उनके 92 प्रतिशत नंबर थोड़े पड़ सकते हैं 97 प्रतिशत वालों के सामने। 'कट-आफ' की दौड़ में वह पीछे रह सकते हैं। बाकी दुनिया के विश्वविद्यालयों में न यह 'कट-आफ' होता है न ही कतारें लगती हैं दाखिलों के लिए। अपने देश में यह चीजें इतनी नार्मल मानी जाती हैं कि पिछले दिनों ज्यादा अहमियत दी मीडिया ने उस झगड़े को जो हाल में यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के बीच हुआ था।

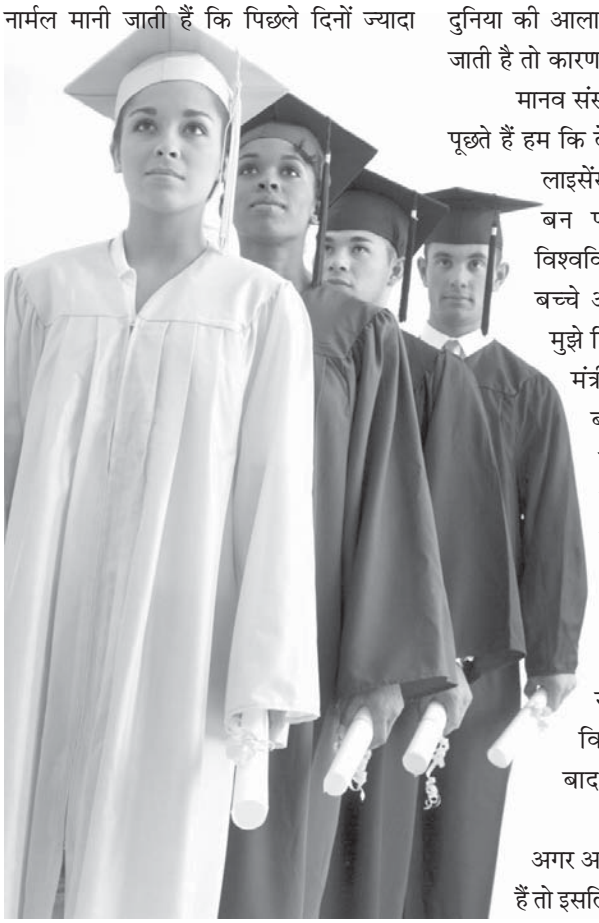

यूजीसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए इस तरह शिक्षा की बारीकियों में जाने का। यह अधिकार वाइस चांसलर साहब का ही होना चाहिए लेकिन जो शिक्षक और बुद्धिजीवी उनके समर्थन में निकल कर आए थे क्यों नहीं उन्होंने यही अधिकार उन कॉलेजों के लिए मांगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत जबर्दस्ती लाए जाते हैं? क्यों नहीं उस लाइसेंस राज के खिलाफ आवाज उठाई जो भारतीय उच्च शिक्षा के लिए जानलेवा बन गया है? आज अगर भारत की आला शिक्षा संस्थान दुनिया की आला शिक्षा संस्थाओं में नहीं गिनी जाती है तो कारण है यह लाइसेंस राज।

मानव संसाधन विकास मंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं हम कि देश को क्या लाभ मिला है इस लाइसेंस राज से? इसके होते हुए नहीं बन पाए हैं वह कॉलेज, वह विश्वविद्यालय जिनके बिना भारत के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। याद है मुझे कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, कपिल सिब्बल, ने मुझे खुद बताया था 2009 में दिए गए एक इंटरव्यू में कि विश्वविद्यालयों कितनी सख्त कमी है देश में कि उनके हिसाब से हमको जरूरत है 1500 नए विश्वविद्यालयों की। आज देश भर में विश्वविद्यालयों की संख्या 500 के करीब है निजी विश्वविद्यालयों को गिनने के बाद।

वह 1500 नए विश्वविद्यालय अगर अभी क्षितिज पर भी नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए कि यूजीसी और उसकी सगी

बहन एआईसीटीई (ऑल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन) कोटा से ज्यादा लाइसेंस देते ही नहीं हैं। इनका कब्जा बिल्कुल वैसा है जैसा किसी जमाने में उद्योग जगत पर लाइसेंस राज का कब्जा हुआ करता था। कोटे से ज्यादा अगर कोई उद्योगपति उत्पादन करने की गलती करता था, जेल जाने की नौबत आ सकती थी। इस लाइसेंस राज को समाप्त किया डाक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में जब वे वित्तमंत्री थे और भारतीय उद्योग के लिए अच्छे दिन फौरन आ गए थे। आज अगर स्मृति ईरानी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे दिन लाना चाहती हैं तो उनको लाइसेंस राज को एक झटके में खत्म करना होगा। एआईसीटीई को मिलनी चाहिए सजा-ए-मौत और यूजीसी को सौंपा जाना चाहिए गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता और वजीफे देने का काम। फिलहाल यूजीसी अपने पैसे बांटता है संस्थानों को जिसका लाभ छात्रों को कम ही मिलता है क्योंकि मामूली फीस बेशक देते हो अपनी पढ़ाई के लिए लेकिन मामूली पढ़ाई भी हासिल करते हैं। ऊपर से समस्या यह भी है कि विश्वविद्यालय इतने कंगाल हो चुके हैं कि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में कम से कम पांच लाख प्राध्यापकों की कमी है। भारतीय मूल के प्रोफेसर बेशुमार हैं दुनिया में लेकिन उन विदेशी कॉलेजों में पढ़ाना पसंद करते हैं जहां उनकी तनख्वाहें उनकी काबलियत के मुताबिक मिलती है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में खराबी, भ्रष्टाचार और गिरावट इतनी आ चुकी है कि हमको चिंता यह नहीं होनी चाहिए कि श्रीमती ईरानी सिर्फ बारहवीं पास हैं चिंता होनी चाहिए कि उनमें इस चुनौती का सामना करने की हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत है तो उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में लेकिन ऐसा होने से पहले उनको कई महिषासुर मारने होंगे जो जिंदा हैं लाइसेंस राज की बदौलत। अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है मंत्रीजी में तो वह भी कामचलाऊ सुधार करके काम चला सकती हैं जैसे अक्सर होता रहता है पिछले दशक में। दो रास्ते हैं उनके सामने और सही रास्ता अगर चुनना चाहती हैं तो इस बात को याद रख कर चलना होगा कि अगर वह गलत रास्ता चुनती हैं तो प्रधानमंत्री का वह नया भारत का सपना कभी साकार न हो सकेगा। इसलिए कि हर वर्ष इस देश में रोजगार ढूंढ़ने निकलते हैं एक करोड़ से ज्यादा नौजवान जिनको रोजगार तब ही मिलेगा जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके आएंगे। यह कैसे संभव होगा जब अच्छे कॉलेजों की इतनी गंभीर समस्या है कि काबिल छात्रों के लिए भी दाखिला मिलना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है?

इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है अगर मंत्रीजी हिम्मत दिखा कर लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म करने का काम नहीं करती हैं। बिना इजाजत के अधिकार मिलना चाहिए किसी को भी किसी नए कॉलेज या विश्वविद्यालय का निर्माण करने का। सरकार की तरफ से सिर्फ इतना होना चाहिए कि वह ठोस मापदंड तय करके सार्वजनिक कर दे।

इस काम में मंत्रीजी को पूरा समर्थन मिलना चाहिए प्रधानमंत्री का, क्योंकि विरोध बहुत होगा न सिर्फ उन सरकारी अफसरों से जिनकी रोजीरोटी- जिनकी शक्ति, इस लाइसेंस राज पर निर्भर है लेकिन उन वामपंथी बुद्धिजीवियों से भी जिनके कहने पर उच्च शिक्षा का यह ढांचा बना है।

दुख की बात है कि यह सब हुआ है गरीब छात्रों के नाम पर और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। इसलिए कि पैसे वाले छात्र चले जाते हैं विदेश जब यहां जगह नहीं मिलती है। गरीब कहीं नहीं जा सकते। ❑

(स्वतन्त्र लेखक एवं पत्रकार)

'भारत' माँ को विश्व गुरु के ...

❑ भरत शर्मा 'भारत'

हम शिक्षा के सैनानी हैं, घर घर अलख जगायेंगे।
'भारत' माँ को विश्व गुरु के, पद पर फिर पहुँचायेंगे।।
'भारत' माँ को विश्व गुरु के....
शून्य दिया दुनिया को हमने, संस्कार सद्ज्ञान दिया ।
विश्व बंधुता के प्रसार हित, सब धर्मों को मान दिया।
वेद और विज्ञान हमारे, उत्कर्षों की थाती है।
कुरुक्षेत्र में कर्मभूमि पर, दुर्लभ गीता ज्ञान दिया ।
आज उसी निष्काम कर्म का, परचम फिर लहरायेंगे।।
'भारत' माँ को विश्व गुरु के....
अमर शहीदों की कुर्बानी, हमको याद दिलाती है।
सत्ता के लोलुप लोगों की, भूलें भी बतलाती है।
देशधर्म संरक्षित रखना, नैतिक जिम्मेदारी है।
विगत काल की भूल सभी को, बारम्बार जगाती है।
जन गण मन मर्यादा रक्षण, नई चेतना लायेंगे।।
'भारत' माँ को विश्व गुरु के ....
राष्ट्र हितों की करे सुरक्षा, वो शिक्षा स्वीकार हमें।
शिक्षा हित निज ध्येय बनावें, वो शिक्षक स्वीकार हमें।
तब समाज में शिक्षक हित की, पुनः भावना आयेगी।
त्याग तपस्या से सम्पूरित, जन-मानस स्वीकार हमें।
लेना है संकल्प सभी को, बदल तभी तो आयेंगे।।
'भारत' माँ को विश्व गुरु के .....

दूर रहें नौकरशाह, तो ठीक होगी उच्च शिक्षा

❑ देवेश कपूर

जब देश की उच्च शिक्षा को बाबूशाही की मानसिकता से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। यह काम नियामकीय और मंत्रिमंडलीय स्तर पर तो करना ही होगा उसके साथ ही इसे विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी अंजाम देना होगा। आखिरकार आईआईटी अथवा आईआईएम निदेशकों अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका क्यों होनी चाहिए? इनसे सीधा संबंध तो सरकार के अलावा छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों तथा पूर्व छात्रों का ही होता है। यह भूलना नहीं होगा कि पूर्व छात्रों का अपने संस्थान से अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव होता है और इसलिए वे संस्थान की प्रगति के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो चार नौकरशाहों की तुलना में अधिक गंभीरता से सोच सकते हैं।

हाल ही में एक पत्र से जानकारी मिली कि चीन पिछले तीन दशकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। इसका संबंध न केवल उसके तेज आर्थिक विकास और शिक्षा के व्यापक विस्तार से है बल्कि इसके अलावा अकादमिक श्रेष्ठता वाला उसका श्रम बाजार भी इसमें शामिल है। बड़ी संख्या में चीनी मूल के वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं जबकि उसकी सरकार विज्ञान के क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार है।

वैश्विक विज्ञान जगत में ज्ञान के बड़े स्रोत के रूप में चीन के तेज उभार का संबंध केवल संख्या से नहीं है बल्कि गुणवत्ता के मोर्चे पर भी ऐसा देखने को मिला है। चीन की इस उपलब्धि में बहुत सी बातें सराहना योग्य हैं। वैज्ञानिक शोध की बात करें तो यह वहां सार्वजनिक वस्तु है और चीन का यह योगदान भारत समेत सारी दुनिया के लिए मददगार साबित होने जा रहा है।

इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से भी वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसऐंडटी) क्षेत्र में देश का नेतृत्व वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व से संबद्ध रहा है। फिर चाहे वह 19वीं सदी का इंगलैंड हो, 19वीं सदी के आखिर का जर्मनी या फिर 20वीं सदी के आरंभ और उसके बाद से अब तक का अमेरिका। निश्चित तौर पर वैज्ञानिक ताकत वैश्विक शक्ति बनने के लिए अनिवार्य जरूरत है। उभरती ताकतें इस मामले में उपभोक्ता की भूमिका में होती हैं जबकि वैश्विक ताकतें इसकी कर्ता-धर्ता और उत्पादक होती हैं।

सन 1990 में देश का जीडीपी चीन के जीडीपी के 83 प्रतिशत के बराबर था जबकि यहां होने वाला प्रकाशनों की संख्या उसके दोगुना थी। लेकिन वर्ष 2011 आते आते जीडीपी तो चीन के मुकाबले 43 प्रतिशत रह गया जबकि प्रकाशनों का अनुपात घटकर 30 प्रतिशत से भी कम रह गया। स्पष्ट है कि पिछले दो दशक के दौरान उच्च शिक्षा और आर्थिक विकास की तेज गति के बावजूद उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में भारत चीन से बहुत पीछे रह गया।

चीन के उद्भव की वजहें वही हैं जो भारत के लडखड़ाने की। चीन ने आर्थिक तरक्की के साथ-साथ विश्वस्तरीय शिक्षकों, संस्थानों आदि की मदद से अपने उच्च शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किया। अगर कोई विदेशी संस्थान चीन में कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे चीन के संस्थान के साथ साझेदारी करनी होती है। चीन का संस्थान उससे सीख सकता है, उसका अनुकरण कर सकता है और अपने स्तर में सुधार कर सकता है। चीन के कारोबारियों ने भी ऐसा ही किया है।

भारत में इस आत्मविश्वास की कमी है। भारत के राजनीतिक वर्ग ने तो उदारीकरण को अपनाया लेकिन उसका बौद्धिक तबका इससे दूरी बनाए रहा और खुद को देश के रक्षक के रूप में पेश किया। वैसे भी देशभक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ तर्क है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि चीन की तरक्की में सरकारी निवेश की अहम भूमिका रही है। लेकिन यह काम इस अंदाज में किया गया कि जनता का पैसा स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ा रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में सामग्री प्रकाशित किए जाने के काम को वरीयता दी गई।

हमारे देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कायदों के मुताबिक सरकारी संस्थान से संबद्ध शिक्षकों को उनके सेवाकाल के दौरान स्वत: पदोन्नति मिलती रहती है। उनका वेतन भी वेतन आयोग द्वारा तय किए गए सामान्य वेतन भत्ते के ढांचे के अनुरूप ही होता है। इस पूरी प्रक्रिया ने उच्च शिक्षा से जुड़े व्याख्याताओं प्रवक्ताओं आदि को बाबू में तब्दील कर दिया है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि आज देश की उच्च शिक्षा बाबूशाही (आईआईएम बेंगलूर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पंकज चंद्रा के शब्दों में) यानी बाबूओं की बाबूओं के

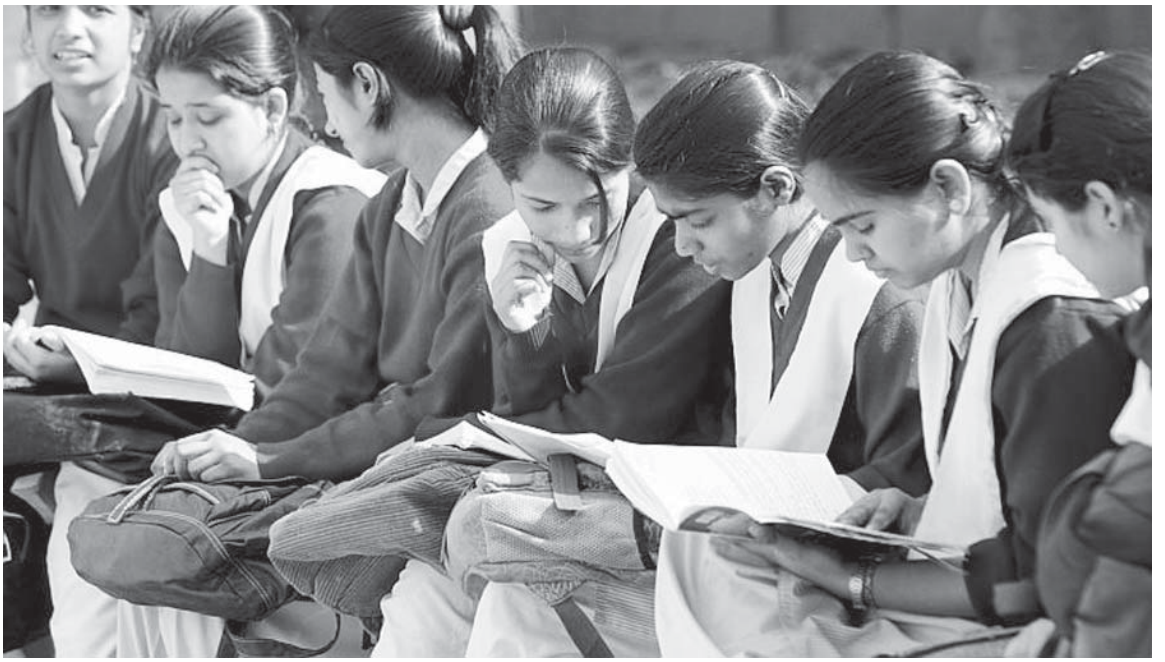

लिए और बाबूओं द्वारा बनकर रह गई है।

यह विडंबना ही है कि अधिनायकवादी देश चीन में उच्च शिक्षा के प्रशासन और नियमन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की तुलना में कहीं ज्यादा है। यकीनन यह भी कहा जा सकता है कि चीन में उच्च शिक्षा क्षेत्र की गतिविधियां भारत के मुकाबले अधिक लोकतांत्रिक ढंग से संचालित हैं और एचआरडी नौकरशाही में वहां अधिक खुलापन और रचनात्मकता है। ये दोनों ही उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं।

जरा इन बातों पर गौर कीजिए: वर्ष 2000-01 और 2011-12 के दौरान देश में कॉलेजों की संख्या 12,806 से बढ़कर 35,539 हो गई। इसका मतलब था एक दशक तक हर रोज करीब छह नए कॉलेज खुले। यह बात तब तक ही अच्छी लगती है जब तक आप यह नहीं पता करते कि यह सबकुछ कैसे हुआ और इन संस्थानों के भीतर दरअसल क्या होता है?

देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की दो प्रमुख हकीकतें हैं- पहली बात, उनका नेतृत्व अत्यंत कमजोर है और दूसरा देश के केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की चयन और पुनरीक्षा समितियों में गिनेचुने लोगों का ही दबदबा है। यही बात देश की विज्ञान प्रयोगशालाओं पर भी लागू होती है। इन सब बातों के चलते व्यवस्था को खुलकर चुनौती देने वालों की संख्या भी अत्यंत सीमित हो जाती है। हर कोई यह जानता है लेकिन खुलकर ऐसा कह नहीं सकता है क्योंकि ऐसा कहने वाले इक्कादुक्का होंगे और उनको नुकसान पहुंचने की प्रबल आशंका रहेगी। स्पष्ट है कि ये तमाम परिस्थितियां विज्ञान की उन्नति के मार्ग में बाधक ही साबित होंगी।

जब देश की उच्च शिक्षा को बाबूशाही की मानसिकता से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। यह काम नियामकीय और मंत्रिमंडलीय स्तर पर तो करना ही होगा उसके साथ ही इसे विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी अंजाम देना होगा। आखिरकार आईआईटी अथवा आईआईएम निदेशकों अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका क्यों होनी चाहिए? इनसे सीधा संबंध तो सरकार के अलावा छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों तथा पूर्व छात्रों का ही होता है। यह भूलना नहीं होगा कि पूर्व छात्रों का अपने संस्थान से अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव होता है और इसलिए वे संस्थान की प्रगति के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो चार नौकरशाहों की तुलना में अधिक गंभीरता से सोच सकते हैं।

मंत्रालयों का मुख्य काम नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्व्यन करना है। मानव संसाधन मंत्रालय विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के चयन में जितना अधिक हस्तक्षेप करेगा उतना ही वह विश्वविद्यालयों के प्रशासन को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा उसके पास नीतिगत कामों पर ध्यान देने के लिए भी वक्त नहीं रहेगा। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह धारणा भी सही नहीं है कि वह देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की निरंतर बढ़ती संख्या का समुचित प्रबंधन कर सकता है। ❑

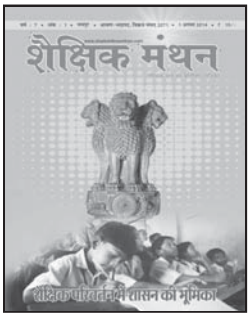

Science has also been solitary; ancient India did not erect a wall between science and art, or between science and spirituality. But science curricula at the undergraduate level tends to be highly theoretical and very dense in content. This poses two problems. ''Theory is prioritized over application and time constraints do not allow teachers to explore all concepts, in depth. As a consequence, students are frequently exposed to many concepts but fail to understand them in depth and explore their application. This structure results in 'teach more and learn less', when ideally it should be the other way around,'' the report said.

In Science, India invests far less than China, US, South Korea

❑ **Hemali Chhapia**

Observer Research Foundation Chairman Sudheendra Kulkarni said the "tight equation between a degree certificate and education has created several distortions, both in society and in the system of education itself". (TOI file photo by K Sunil Prasad)

MUMBAI: A report by a thinktank shows India's investment in science has lagged behind that of neighbouring China, the US and South Korea, resulting in these countries staying ahead when it comes to research.

While India invested 0.88 per cent of its GDP in science research, the US invested 7-8 per cent, and South Korea 3-4 per cent.

The Observer Research Foundation (ORF) report titled " Whither Science Education in Indian Colleges?" shows that India, with one of the lowest R&D spend-to-GDP ratios, is also expending resources on areas that have a weak connection to industry, thereby missing out on opportunities for economic growth.

"More than a quarter of (India's) R&D investment goes towards basic research, against 5 per cent in China and 17 per cent in the United States," the report states.

There are other fundamental reasons, too, why science is ailing. ORF chairman Sudheendra Kulkarni said the "tight equation between a degree certificate and education has created several distortions, both in society and in the system of education itself". He said it has placed a disproportionate emphasis on standardized examinations and students' ability to score well in them.

"Memorization of facts and formulae has triumphed over mastery of concepts, independent and creative thinking, integrative thinking that connects understanding of different subjects, and ability to apply that understanding to solve practical problems of society."

Science has also been solitary; ancient India did not erect a wall between science and art, or between science and spirituality. But science curricula at the undergraduate level tends to be highly theoretical and very dense in content. This poses two problems. "Theory is prioritized over application and time constraints do not allow teachers to explore all concepts, in depth. As a consequence, students are frequently exposed to many concepts but fail to understand them in depth and explore their application. This structure results in 'teach more and learn less', when ideally it should be the other way around," the report said.

The authors — Catarina Correia, Leena Chandran-Wadia, Radha Viswanathan and Adithi Muralidhar — conclude that India is facing two kinds of disconnect: a formal science education pedagogy in colleges that is too theory-based and is disconnected from the practical world; and a large workforce in the informal sector of the economy whose practice is disconnected from science education. Despite a large tertiary student population, India has not been able to increase the number of PhDs in science and engineering significantly (from 54 per 10 million in 1983 to 70 in 2004). China, which lagged India until a decade ago, now has 174 science and engineering PhDs per 10 million.

The SAC-PM Vision Document (2010) that lays the roadmap for India to become the "global leader in science" calls for a target of producing 30,000 per year by 2025, as against 8,286 PhDs (S&T, agriculture, medicine, veterinary) produced in 2013. ❑

UGC asks varsities to send teacher educators back to classrooms

Universities are directed to start extensive training programs for teacher educators as "top priority." Move aims at producing "quality teachers" in country.

The University Grants Commission (UGC), the apex body of higher education, has directed all universities across India to strengthen their education departments with designing extensive and intensive training programs for teacher educators. The move will help education (B.Ed) colleges of the varsities to churn out "quality teachers".

Ved Prakash, chairman of the UGC, has written a letter to the directors of Academic Staff Colleges (ASC), which is the most integral but almost "idle" department of all central and state varsities, on June 30. The letter states, "In carrying forward our efforts towards strengthening of the teacher education programs, may I request your personal attention in ensuring….to please include teacher education in your calendar of activities and provide a significant slot for both, refresher and orientation programs for teacher educators."

The letter also reads, "This may be accorded Top Priority please." They have also been asked to submit a report of the action taken.

According to a UGC member, the direction of strengthening the education departments/colleges of the varsities has come from Smriti Irani, the Human Resources and Development Minister who is actively taking interest in improving the quality of educators across the country.

ASCs at Universities are entrusted with conducting the training programs for the faculty of all departments, in order to help them brush-up teaching skills of the professors. "However, most of these colleges are not so dynamic and their programs are also mainly ceremonial," said a professor of Mumbai university.

The teaching colleges are also marred with a lack of quality teachers and are accused of churning out "substandard teachers," which ultimately affects the quality of school education in the country.

Welcoming the move, Hari Chandan, director of Institute of Distance and Open Learning at Mumbai university, who is also a senior teacher educator, says that the UGC move is in accordance with the 2012 report of Justice Verma Commission which has recommended several reforms in the field of teachers' education. "This will certainly help educators brush-up their skills, which would subsequently help teaching schools provide better education to B.Ed students," says Prof Hari Chandan.

He however adds, "Most of the teaching colleges in India are in the private sector and suffer largely from lack of infrastructure and well-trained teachers. Varsities must include all private colleges under their ambit into this program." ❑

मत कीजिये विज्ञान की अनदेखी

❑ शशांक द्विवेदी

केंद्रीय बजट में सरकार ने विज्ञान के विकास, शोध परियोजनाओं की बढ़ोत्तरी तथा अनुसंधान कार्य के लिए शोध फंड संगठन बनाने की बात कही है। इस संगठन के जरिए छात्रों को शोध परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी। फिलहाल देश में प्रौद्योगिकी विकास कोष के नाम पर सौ करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। पांच नए आईआईटी और पांच आईआईएम बनाने की घोषणा भी हुई है लेकिन बजट में देश में बुनियादी विज्ञान के विकास के लिए कुछ खास नहीं है। कुल मिलाकर सरकार ने विज्ञान और तकनीक के पूरे क्षेत्र के लिए बजट में जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत दिया है जो उम्मीद से काफी कम है। यह उम्मीद से कम इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने की बात कई मंचों पर कह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस समारोह में कहा था कि हमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना चाहिए। यह सरकार और उद्योग जगत दोनों की तरफ से होना चाहिए। बाकी देशों से तुलना करें तो अमेरिका और चीन सहित दुनिया के तमाम छोटे-बड़े देश विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में बजट बढ़ाते रहे हैं। दक्षिण कोरिया जैसे देश में भी सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा विज्ञान क्षेत्र पर खर्च होता है, जिसमें उद्योग जगत का सहयोग भी अहम है। सरकार द्वारा इस बारे में चिंता तो व्यक्त की जाती रही है लेकिन समाधानस्वरूप वास्तविक धरातल पर कुछ भी क्रियान्वित नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर देश में वैज्ञानिक शोधों की दशा अत्यंत दयनीय है। भारत रत्न प्रोफेसर सीएनआर राव भी देश में विज्ञान और तकनीक क्षेत्र के लिए कम बजट देने के लिए सरकार और राजनीतिज्ञों की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी बजट है या जो फंड है, वह काफी कम है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत तरक्की जरूर कर रहा है लेकिन वहां के लिए भी समुचित बजट उपलब्ध नहीं है। अमेरिका की तर्ज पर चीन अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा रहा है लेकिन हमारे देश में विज्ञान का मौजूदा बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है। देश में विज्ञान

'वर्ल्ड क्लास' बनने के लिए बुनियादी विज्ञान का विकास जरूरी है। संसद या सर्वदलीय बैठक में देश के शीर्ष वैज्ञानिकों से विचार करके 5-5 वर्षों के लिए विज्ञान के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए ताकि जाना जा सके कि देश चरणबद्ध तरीके से आखिर कितना आगे जा सकता है और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? प्रधानमंत्री को वादे पर अमल करते हुए विज्ञान और अनुसंधान के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान में धन की कमी आड़े न आये और देश में वैज्ञानिक शोध और आविष्कार का सकारात्मक माहौल बने।

और शोध की स्थिति का आलम यह है कि विज्ञान में पीएचडी करने वाले हजारों लोगों में से 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं। इस स्थिति के लिए हमारे विद्यार्थी या उनके अभिभावक जिम्मेदार नहीं हैं। दरअसल हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा बोध ही पैदा नहीं किया जा सका है कि विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल विषय से आगे समझा जाए। शायद यही वजह है कि पिछले 50 सालों में देश एक भी ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं कर पाया, जिसे पूरी दुनिया उसके अद्वितीय शोध के कारण पहचाने। बतौर वैज्ञानिक भारतीय नागरिक (सीवी रमन) को नोबेल 84 साल पहले (1930 भौतिकी) मिला था। तब से हम भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित नोबेल पर ही खुशी मनाते आए हैं। आजादी के समय जब देश में संसाधन कम थे, तब हमारे यहां जगदीश चंद्र बोस, नोबल पुरस्कार विजेता सर सी वी रमण, मेघनाद साहा और सत्येन बोस जैसे महान वैज्ञानिक हुए, लेकिन आज जब संसाधनों की कमी नहीं है, तो देश में विज्ञान शोधों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह विडम्बना है कि बाद के समय में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हरगोबिंद खुराना, एस. चन्द्रशेखर, अमर्त्य सेन और डॉ. वेंकटरामन रामकृष्णन जैसे देश में जन्मे वैज्ञानिकों ने विदेशों में जाकर उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबल प्राप्त किया। देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में शोध के लिए स्पेस काफी कम रह गया है। उच्च शिक्षा पाने वालों में से केवल एक प्रतिशत छात्र ही शोध करते हैं। किन विषयों पर शोध हो रहा है और समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, इसका मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं है। इसके उलट यूजीसी के कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, जो गंभीर शोधपरक संस्कृति के विकास में रुकावट डालते हैं। वास्तव में विज्ञान के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय नीति जरूरी है। विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत होगी और वो भी आधारभूत विज्ञान विषयों से जुड़े शोधार्थियों की, इसलिए यह जरूरी है कि मेधावी छात्रों को विज्ञान विषय पढ़ने के प्रति प्रेरित किया जाए। विज्ञान के छात्रों और शोधार्थियों को रोजगार की गारंटी दी जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान कल-कल बहती जलधारा की तरह हैं। इनमें सततता जरूरी है एवं स्वायत्तता भी। विज्ञान के विषय में राष्ट्रीय नीति बनाने और उस पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत। ऐसा नहीं है कि हमने उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, लेकिन हमारी योग्यता और क्षमता के लिहाज से हम इस मोर्चे पर अब भी काफी पीछे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में बेशक हमारी कुछ उपलब्धियां भी हैं, लेकिन इससे इतर कोई नई खोज अब तक हमने कहीं की है। जबकि पड़ोसी देश चीन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। वहां जो भी काम होता है, वृहत और युद्ध स्तर पर होता है। चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो या फिर ओलम्पिक फतह का काम। चीन ने यह जान और मान लिया है कि बौद्धिक संपदा के विकास और समृद्धि बिना वह 2020 तक अमेरिका को नहीं पछाड़ सकता है। इसी का नतीजा है कि अब वह वैज्ञानिक शोध और विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जुट गया है। चीन के विश्वविद्यालय और उद्योग बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए अनुकूल माहौल के साथ वहां की सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं। इसी तरह अमेरिका बुनियादी विज्ञान विषयों की प्रगति का पूरा ध्यान रखता है। उसकी नीति है कि वैज्ञानिक मजदूर तो वह भारत से लेगा पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान पर कड़ा नियत्रंण रखेगा। चीन में भी शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, पर बुनियादी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति का उसने पूरा ध्यान रखा है। भारत को चीन से शिक्षा लेनी चाहिए। 'वर्ल्ड क्लास' बनने के लिए बुनियादी विज्ञान का विकास जरूरी है। संसद या सर्वदलीय बैठक में देश के शीर्ष वैज्ञानिकों से विचार करके 5-5 वर्षों के लिए विज्ञान के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए ताकि जाना जा सके कि देश चरणबद्ध तरीके से आखिर कितना आगे जा सकता है और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? प्रधानमंत्री को वादे पर अमल करते हुए विज्ञान और अनुसंधान के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान में धन की कमी आड़े न आये और देश में वैज्ञानिक शोध और आविष्कार का सकारात्मक माहौल बने। ❑

(स्वतंत्र लेखक/ टिप्पणीकार)

ये युवा कैसा भारत बनाएंगे

❑ एन. के. सिंह

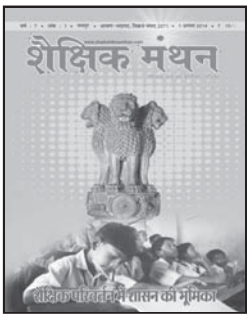

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस युवा शक्ति का जिक्र किया और विश्वास जाहिर किया कि विश्व पटल पर यही शक्ति भारत को आगे ले जाएगी। लेकिन शायद इस शक्ति को वास्तव में उपादेय बनाने के लिए एक नई क्रांति का आगाज करना होगा देश की शिक्षा नीति में। अन्यथा विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि यह शक्ति एक बोझ बन जाएगी देश की छाती पर। हाल ही में एक बड़े मीडिया शिक्षा संस्थान में भर्ती के लिए आयोजित एक इंटरव्यू में पाया गया कि जो छात्र-छात्राएं पत्रकारिता में परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएशन) में दाखिले के लिए आए उनमें नब्बे प्रतिशत को यह नहीं मालूम था कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। कई छात्रों को नेहरू और इंदिरा गांधी में क्या संबंध थे नहीं मालूम था और लगभग पंचानवे प्रतिशत भारत के पांच पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम नहीं बता पाए।

विश्व बैंक ने 'दक्षिण एशियाई छात्रों में ज्ञान' शीर्षक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत सहित दक्षिण एशियाई देश शिक्षा पर खर्च तो कर रहे हैं पर शिक्षण की गुणवत्ता खराब होने की वजह से इन देशों का आर्थिक विकास ही नहीं अवरुद्ध हो रहा है बल्कि इससे युवाओं में बेरोजगारी-जनित गरीबी भी बढ़ रही है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के कक्षा पांच के विद्यार्थी सामान्य माप-तौल, दो-अंकों का जोड़-घटाना, अपनी बात को वाक्य में लिख कर समझाना या शुद्ध वाक्य लिखना तक नहीं जानते। न ही वे सौ तक के अंकों या पूरी ककहरा (संपूर्ण वर्णमाला) का ज्ञान रखते हैं।

उधर बिहार सरकार ने पिछले सप्ताह पाया कि प्राइमरी स्तर पर जिन 1.50 लाख शिक्षकों की संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर नियुक्ति कुछ साल पहले की गई थी उनमें से जब पचास हजार की जांच की गई तो उनमें से बीस हजार की डिग्रियां या सर्टिफिकेट फर्जी थे। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वह यह कि शिक्षक की नियुक्तियों में अधिकारियों, मुखियाओं ने जमकर पैसे कमाए हैं और अधिकतर नियुक्तियां डेढ़ लाख से दो लाख रुपए घूस लेकर की गई हैं। उस पर तुर्रा यह कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद भी केवल कुछ मुखियाओं को हटाया गया लेकिन किसी भी स्तर के एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस युवा शक्ति का जिक्र किया और विश्वास जाहिर किया कि विश्व पटल पर यही शक्ति भारत को आगे ले जाएगी। लेकिन शायद इस शक्ति को वास्तव में उपादेय बनाने के लिए एक नई क्रांति का आगाज करना होगा देश की शिक्षा नीति में। अन्यथा विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि यह शक्ति एक बोझ बन जाएगी देश की छाती पर।

हाल ही में एक बड़े मीडिया शिक्षा संस्थान में भर्ती के लिए आयोजित एक इंटरव्यू में पाया गया कि जो छात्र-छात्राएं पत्रकारिता में परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएशन) में दाखिले के लिए आए उनमें नब्बे प्रतिशत को यह नहीं मालूम था कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। कई छात्रों को नेहरू और इंदिरा गांधी में क्या संबंध थे नहीं मालूम था और लगभग पंचानबे प्रतिशत भारत के पांच पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम नहीं बता पाए। लगभग इतने ही तुलसीदास को नहीं जानते थे और अगर इक्के-दुक्के ने बताया भी तो यह कह कर कि इनका एक 'रामायण' नामक सीरियल से संबंध है।

भारत प्रतिवर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत (दो लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए, जिसमें से पैंसठ हजार करोड़ रुपए केवल केंद्र सरकार का बजट है) शिक्षा पर खर्च करता है। दबाव यह है कि इसे कम से कम ढाई गुना किया जाए। हालांकि कुछ राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश यह दावा तो करते हैं कि इनके यहां पंजीकरण (एनरोलमेंट) का प्रतिशत नब्बे से सत्तानबे हो गया है, पर इसका कारण शिक्षा के प्रति समाज में रुझान न होकर छात्रों को मिलने वाली मदद (वस्तु या नकद के रूप में) और मध्याह्न भोजन है।

गैर-सरकारी संस्था 'प्रथम' की पिछले पांच वर्षों की रिपोर्ट (असर) लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रही है कि 'बीमारू' राज्य खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में कक्षा पांच के बासठ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा दो का ज्ञान नहीं रखते और सामान्य जोड़-घटाव भी नहीं कर पाते। पर शायद राज्य सरकारों के भ्रष्ट और निकम्मे तंत्र को केंद्र से मिलने वाले अनुदान या वोट की राजनीति से ज्यादा लगाव है।

बिहार की नीतीश सरकार ने स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिल देना चुनाव का मुद्दा बनाया बगैर यह सोचे हुए कि राज्य में जो पौध लगाई जा रही है वह राष्ट्रीय स्तर पर जब नौकरी के बाजार में जाएगी तो कोई उन्हें नहीं पूछेगा। और तब आरोप लगेगा कि कि देश में अस्सी प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। इन राज्यों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहद खराब रही है। और ऐसा नहीं है कि इन राज्यों के मुखिया यह सब नहीं जानते।

'असर' ने शिक्षा को लेकर अधिकारियों और शिक्षकों की आपराधिक उदासीनता और चालाकी पर दो वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जिले का एक किस्सा बयान किया। प्रधानाचार्य की एक बैठक में एक सरकारी अधिकारी ने कहा 'सभी बच्चों का दाखिला हो उनके साथ मारपीट न करें उन्हें पास करके अगली कक्षा में भेजें और सुनिश्चित करें कि वे अगले साल भी दाखिला लें और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यह तय मानिए कि आपने शिक्षा के अधिकार के तहत मिले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।'

अधिकारी के इस आदेश के पीछे छिपा संदेश स्पष्ट था। संकेत यह था कि बच्चा पढ़ने आए न आए, रजिस्टर में नाम होना चाहिए। पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले साल भी यही काम करना है ताकि येन केन प्रकारेण 'लक्ष्य' हासिल हो सके।

व्यापक रूप से किए गए इस सर्वेक्षण में सरकार के तमाम दावों के खोखलेपन को उजागर किया गया है। अध्ययन में इस बात को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से बीमारू राज्य (बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़) शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहे हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के बजट को बढ़ाते हुए 68,710 करोड़ (2007-08) से बढ़ा कर 97,255 करोड़ (2009-10) कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सारे प्रयासों पर संबंधित राज्य सरकारों के भ्रष्टतंत्र ने पानी फेर दिया है। दरअसल, शिक्षा देने की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से ही नहीं, व्यावहारिक रूप से भी राज्य सरकारों की ही है।

'असर' की रिपोर्ट देखने के बाद यहां प्रश्न उठता है कि क्या इसी किस्म के प्रयासों से हम चीन जैसे राष्ट्रों से मुकाबला कर सकेंगे। आज भारत में जहां उच्च-शिक्षा के लिए केवल साढ़े तेरह प्रतिशत छात्र दाखिला ले रहे हैं, वहीं चीन और मलेशिया जो हमसे काफी पीछे रहा करते थे- के 22.1 और 24 प्रतिशत छात्र आज उच्च शिक्षा में दाखिला लेते हैं। जबकि अमेरिका में उच्च-शिक्षा में 81.6 प्रतिशत छात्र प्रवेश लेते हैं। एक और उदाहरण देखिए। आज से अठारह साल पहले जहां चीन में केवल उन्नीस सौ पीएचडी हुआ करते थे (जबकि भारत में करीब तीन हजार पीएचडी होते थे) आज बाईस हजार पीएचडी हर साल निकलते हैं। भारत में केवल छह हजार पीएचडी निकल रहे हैं जबकि अमेरिका में चालीस हजार। अगर यही स्थिति रही तो भारत 'पॉवर इज नॉलेज' (ज्ञान ही शक्ति है) की दौड़ में कितना पीछे रहेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

'असर' की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश में कक्षा पांच में आधे से ज्यादा छात्रों को कक्षा दो का ज्ञान नहीं रहता, वे गणित से घबराए हुए हैं। दाखिले के जो आंकड़े राज्य सरकारों के हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के वे 'असर' के आंकड़ों के मुताबिक फर्जी हैं।

विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के कई देश हैं (श्रीलंका को छोड़ कर) जिनमें शिक्षक का ज्ञान उस प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी के ही समकक्ष होता है।

रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत और पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को जब उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के कुछ सवाल दिए गए तो वे उन्हें हल नहीं कर पाए, यानी उन्हें सामान्य जोड़-घटाव के सवाल नहीं आते थे। यही वजह है कि न तो शिक्षक को पढ़ने की सलाहियत है न ही विद्यार्थियों को पढ़ने में दिलचस्पी। शिक्षक का भी काम मात्र मध्याह्न भोजन बांटना होता है और अगर जुगाड़ लगे तो उसके मद में आए पैसे हजम करना। बाकी काम कागजों पर।

हाल में बिहार के एक गांव में जब एक युवा ग्राम प्रधान ने पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए उन्हें स्वयं कतार में लगवाया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया और पता चला कि एक कक्षा के 95 में से 91 विद्यार्थी अपना नाम नहीं लिख पाते।

जाने-माने शिक्षाविद डॉ दौलत सिंह कोठारी ने 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी चर्चित रिपोर्ट 'राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा' तैयार की और यह रिपोर्ट देश की शिक्षा नीति का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनी। पच्चीस वर्षों बाद जब उनसे पूछा गया कि अगर वे फिर से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने तो क्या यही रिपोर्ट देंगे। उन्होंने बेबाकी से कहा मैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन करूंगा और नई रिपोर्ट का मूलमंत्र होगा। चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा।

कोठारी की वेदना समझना मुश्किल नहीं है। जो छात्र-छात्राएं-नेहरू राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री या इंदिरा गांधी पहले हुईं या नेहरू- नहीं जानते, वे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे इसमें शक है। जो युवा महाकवि तुलसी को 'रामायण' सीरियल से जानता होगा उसके लिए मंदिर बने तो ठीक न बने तो ठीक, सीरियल चलते रहना चाहिए। कैसे इस युवा से सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद की जाएगी। दरअसल, बलात्कार के खिलाफ इंडिया गेट पर मोमबत्ती जलाना कुछ लोगों के उत्तम सोच की उपज तो हो सकती है पर इसे पूरे समाज की धारा नहीं मान सकते।

अण्णा के आंदोलन की असमय मृत्यु इसका ताजा उदाहरण है। यह अपेक्षा करना कि ऐसी उथली शिक्षा देकर हम देश का चरित्र निर्माण करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार और बलात्कार नहीं होगा, अपने को मृगमरीचिका का शिकार बनाना होगा। वे अच्छे नागरिक तो नहीं ही होंगे, खासकर ऐसे नागरिक जो देश में भ्रष्टाचार या बलात्कार के खिलाफ लंबे समय तक आवाज उठाएं, यानी न करें न करने दें।

चूंकि शिक्षा मूल रूप से राज्य का विषय है इसलिए केंद्र सरकार राज्यों से अनुनय-विनय ही कर सकती है या वित्तीय मदद पर कुछ अंकुश लगा सकती है। लेकिन राज्य सरकारों की गैर-जिम्मेदाराना और कुछ हद तक आपराधिक उदासीनता देश के विकास के प्रयासों को नीचे लाने के लिए काफी होगी। ❑

मानसिकता बदलने से बनेगी बात

❑ एन आर नारायण मूर्ति

सरकारी एकाधिकार दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों और लोगों के लाभों के बीच अभिन्न रूप से विषमता पैदा करते हैं। इसके अलावा, हमारा कुलीन वर्ग अब भी, जैसा कि फ्रैंज फैनन ने उत्तर-औपनिवेशिक समाजों पर लिखी अपनी मशहूर किताब में कहा है, काली चमड़ी और गोरी नकाब चढ़ाए लोगों की तरह बर्ताव करता है। यह मानसिकता बदलनी होगी, वर्ना आप खुद को और अपने आसपास के समाज को हमेशा एक-दूसरे के विरोध में खड़ा पाएंगे। हमारी हजार साल की गुलामी का एक और अभिशाप उदासीनता है। भारत के अभी तक पिछड़ा होने की मुख्य वजह सक्रिय कार्य करने की हमारी अनिच्छा है, तब भी जब हल हमारे समक्ष खड़ा होता है। नियति को दोष देकर हम अपनी समस्याएं हल करने की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। अब आपको बातें कम और कायरे पर अधिक फोकस करना होगा।

भारत में हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं लेकिन इस तरह जताते हैं मानो किसी भी जनसुविधा का सुधार हमारा काम न हो। इस मानसिकता को ऐसी मानसिकता में बदलना होगा जो सभी सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ सके और सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए तेजी से कार्य कर सके। इसके लिए हर व्यक्ति को, जितना उसने समाज से लिया है, उससे ज्यादा किसी न किसी रूप में समाज को वापस देना होगा। इसी तरह देश उन्नति करते हैं।

आज हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त है, मगर आर्थिक स्वतंत्रता- भूख, बीमारी और अज्ञानता से स्वतंत्रता- नहीं। मेरा विश्वास है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना इस पीढ़ी का दायित्व है। इस समाज को बदलना, हरेक गरीब बच्चे की आंख से आंसू पोछने के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना हमारा दायित्व है। क्या हम यह कर सकते हैं? मेरा जवाब तो स्पष्ट रूप से 'हां' है। क्या आप जानते हैं कि मुझे इतना विश्वास क्यों हैं? यह इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक संभाव्य असंभवता एक निश्चित संभावना से बेहतर है। इसके अलावा, युवा शक्ति में मुझे जबरदस्त भरोसा है, उस ऊर्जा, आत्मविास, दृढ़ निश्चय और उत्साह में जो हमारे युवा नागरिकों में कूट-कूटकर भरा है। मगर यह बड़ा भारी काम है और इसके लिए आवश्यक है कि आप सख्त मनन करें, आत्मनिरीक्षण में लगें और वे काम करने का फैसला करें जो पिछली पीढ़ियों ने नहीं किए। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें एक सुसंस्कृत समाज बनाना होगा- एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे; जहां हर बच्चे को खाना, आवास, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा प्राप्त होगी; जहां हर पीढ़ी अगली पीढ़ी का जीवन बेहतर बनाने के लिए त्याग करेगी। ऐसा बदलाव लाने और गरीबी मिटाने के लिए इक्कीसवीं सदी की एक नई मानसिकता की आवश्यकता है- वह जो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हमारा निश्चय दृढ़ बना सके। सीके प्रह्लाद ने एक बार मुझसे कहा था, 'विकासशील देश होना महज एक मानसिकता है।' मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव में, जब सत्तर के दशक के शुरू में मैं फ्रांस गया था तो पहला फर्क मैंने विकसित देश और विकासशील देश की 'मानसिकता' का पाया। फ्रांस में हर कोई इस तरह दिखता मानो जनसुविधाएं सुधारने पर चर्चा करना, बहस करना और फटाफट

इस दिशा में कार्य करना उनका ही काम हो। भारत में हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं लेकिन इस तरह जताते हैं मानो किसी भी जन सुविधा का सुधार हमारा काम न हो। इस मानसिकता को ऐसी मानसिकता में बदलना होगा जो सभी सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ सके और सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए तेजी से कार्य कर सके। इसके लिए हर व्यक्ति को, जितना उसने समाज से लिया है, उससे ज्यादा किसी न किसी रूप में समाज को वापस देना होगा। इसी तरह देश उन्नति करते हैं। हर मेहनतकश, निष्कपट और ईमानदार नागरिक को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कोई छोटा नहीं है। मगर, हममें से शिक्षित लोगों के लिए, जिन्होंने हमारे कम भाग्यशाली बंधुओं के त्याग से लाभ उठाया है, बाकी सबकी बनिस्पत ज्यादा अवसर और जिम्मेदारी है। इक्कीसवीं सदी की मानसिकता को अपनाने वाले शिक्षित भारतीयों को कुछ विहित गुणों को मानना होगा। मैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ– सबसे पहले तो हमें उच्च महात्वाकांक्षाएं चाहिए। महत्वाकांक्षाएं हमें उन सीमाओं को पार करने की ऊर्जा देती हैं जिन्हें हमारा माहौल हमारे ऊपर थोप देता है। वे उम्मीदों को जन्म देती हैं और उन्हें कायम रखती हैं। वे चमत्कारों को हासिल करने में सहायक होती हैं। स्वतंत्र भारत की महात्मा गांधी की महात्वाकांक्षा के कारण ही आज मैं और आप आजाद लोगों की तरह घूम-फिर पा रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महत्वाकांक्षाएं ही सभ्यताओं को बनाती हैं। इसलिए आप जो भी करते हों, अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची रखें। प्रगति के लिए आत्मविश्वास भी बेहद अहम है। खुलापन ऐसे ही आत्मविश्वास का चिह्न है। इसलिए नए विचारों को स्वीकार करने, आंकने, उन्हें अनुकूल बनाने और अपनाने की योग्यता ही सफल लोगों को कम सफल लोगों से अलग करेगी। हमें ऐसे कोई भी विचार और अवधारणाएं छोड़नी होंगी जो हमें कौमपरस्ती, उग्र राष्ट्रीयता और संकीर्णता की ओर ले जाती हैं। आपस में जुड़े विश्व-ग्राम के इस युग में, आर्थिक उन्नति चाहने वाले किसी भी राष्ट्र को बाहरी दुनिया से खुद को काटना नहीं चाहिए। आखिरकार, सफल होने के लिए हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ खड़ा होना होगा। इससे जरा भी कम नीति हमें शिखर पर नहीं ले जाएगी। हजार सालों से ज्यादा के हमारे औपनिवेशीकरण के कारण, हमारे समाज में लोग अविश्वासी और दमित हैं। हम एक ऐसा समाज हैं जहां शासन के हितों को लोगों के हितों से ज्यादा अहम समझा जाता है; जहां सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कुछ हजार लोगों की नौकरियों को उन लाखों उपभोक्ताओं से ज्यादा पुनीत समझा जाता है जिन्हें इन संस्थानों द्वारा सेवा देने की उम्मीद की जाती है; जहां एक भारतीय मल्टीनेशनल विदेशी सरकारों की तुलना में अपने ही देश की सरकार द्वारा विकास की कमी को महसूस करती है; और जहां नौकरशाह मानते हैं कि विश्व स्तर के शैक्षिक संस्थानों को चलाने के बारे में उन संस्थानों के जहीन बुद्धिजीवियों की तुलना में वे कहीं ज्यादा जानते हैं। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पचास साल बाद भी हम अब तक पूर्व शासकों की बपौती से पार नहीं पा सके हैं, जो कि खुद इस बीच तेजी से बदल गए हैं। हमें समझना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के हित सार्वजनिक हित नहीं हैं और यह भी कि सरकार के हित लोगों के हित नहीं हैं। इस बोध का एक उदाहरण भी सरकार शासितों के सारे एकाधिकारों को हटाने में सक्रिय होगा। सरकारी एकाधिकार दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों और लोगों के लाभों के बीच अभिन्न रूप से विषमता पैदा करते हैं। इसके अलावा, हमारा कुलीन वर्ग अब भी, जैसा कि फ्रैंज फैनन ने उत्तर-औपनिवेशिक समाजों पर लिखी अपनी मशहूर किताब में कहा है, काली चमड़ी और गोरी नकाब चढ़ाए लोगों की तरह बर्ताव करता है। यह मानसिकता बदलनी होगी, वर्ना आप खुद को और अपने आसपास के समाज को हमेशा एक-दूसरे के विरोध में खड़ा पाएंगे। हमारी हजार साल की गुलामी का एक और अभिशाप उदासीनता है। भारत के अभी तक पिछड़ा होने की मुख्य वजह सक्रिय कार्य करने की हमारी अनिच्छा है, तब भी जब हल हमारे समक्ष खड़ा होता है। नियति को दोष देकर हम अपनी समस्याएं हल करने की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। अब आपको बातें कम और कायरे पर अधिक फोकस करना होगा। ❑

(संपादित अंश 'बेहतर भारत, बेहतर दुनिया' से साभार)

सृष्टि में अतुलनीय विज्ञान के सृजनकर्ता हम

❑ साकेन्द्र प्रताप वर्मा

आज भारत ही नहीं दुनिया के अनेकों देश पश्चिम की ओर ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के लिये आशा भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि आज से लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने जो चिंतन और दर्शन दुनिया को दिया था, मात्र उसकी पुनरावृत्ति ही पश्चिम के द्वारा हो रही है। वास्तविकता यह है कि पश्चिम अस्तगामी सूर्य का विश्रामस्थल है, जबकि पूर्व सूर्य के उदय का प्रतीक है। उसी का परिणाम है कि हमारे वेद और पुराणों में जिस ज्ञान और विज्ञान का उल्लेख है, उससे अलग हटकर देने के लिये दुनिया के देशों के पास कुछ भी नहीं है। पाश्चात्य देशों के जो वैज्ञानिक अपने ऊपर अहंकार करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि संसार को आयुर्वेद जैसा महान ज्ञान भारत ने दिया, जिसकी सहायता से अनेक असाध्य रोगों पर दुनिया के करोड़ों लोगों ने विजय प्राप्त की।

आज भारत ही नहीं दुनिया के अनेकों देश पश्चिम की ओर ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के लिये आशा भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि आज से लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने जो चिंतन और दर्शन दुनिया को दिया था, मात्र उसकी पुनरावृत्ति ही पश्चिम के द्वारा हो रही है। वास्तविकता यह है कि पश्चिम अस्तगामी सूर्य का विश्रामस्थल है, जबकि पूर्व सूर्य के उदय का प्रतीक है। उसी का परिणाम है कि हमारे वेद और पुराणों में जिस ज्ञान और विज्ञान का उल्लेख है, उससे अलग हटकर देने के लिये दुनिया के देशों के पास कुछ भी नहीं है। पाश्चात्य देशों के जो वैज्ञानिक अपने ऊपर अहंकार करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि संसार को आयुर्वेद जैसा महान ज्ञान भारत ने दिया, जिसकी सहायता से अनेक असाध्य रोगों पर दुनिया के करोड़ों लोगों ने विजय प्राप्त की। किन्तु हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पर पूरा विश्वास न करके अंग्रेजी दवाओं पर अधिक विश्वास करते हैं। यह उच्च आयुर्वेदिक ज्ञान भी रसायन शास्त्र का एक अंश है। भारत ने शून्य का आविष्कार करके दुनिया को गणितीय ज्ञान की आधार शिला प्रदान की। इतना ही नहीं भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान और ज्योतिषविज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ भी कम नहीं हैं। वास्तव में ज्ञान विज्ञान के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने के बाद भी जब दुनिया को शांति नहीं मिली, तब भारत ने अध्यात्म का मार्ग तलाशा, जिसमें से साधना का जन्म हुआ और साधना के वाहक ही ऋषि कहलाये। हमारे विद्वानों ने कहा है कि जहाँ पहुँचकर विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहीं से दर्शन का जन्म होता है। दुर्भाग्य यह है कि उच्च स्तर की इन बातों को हम इसलिये नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि यह बाते वेद, पुराण और उपनिषदों में लिखी है, और हमारे ये ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं। आजादी के बाद हमने संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा की है और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसी कारण दुनिया की खोजों को हम आश्चर्य से देखते रह जाते हैं।

वैसे तो आधुनिक काल के वैज्ञानिक आविष्कारों की तुलना, जब हम प्राचीन काल के वैज्ञानिकों से करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की माटी से निकला विज्ञान ही दुनिया का श्रेष्ठतम विज्ञान है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान विज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित की थी उसी की प्रकाश किरण के सहारे आज दुनिया प्रकाशवान हो रही है।

त्रिपुरासुर दैत्य राजा था, उसने इन्द्र को भी चुनौती दी थी। उससे युद्ध होने की स्थिति में भगवान शंकर ने देवताओं को सतर्क करते हुये कहा था कि वह प्रकाश से अधिक गति से चलने वाले आकाशयान से चलने का सामर्थ्य रखता है। इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है किन्तु हमारे वैज्ञानिक जार्ज सुदर्शन ने आधुनिक युग में एक ऐसी वस्तु को खोज निकाला जिसकी गति भी प्रकाश की गति से अधिक है। उस वस्तु का नाम है 'टाकियन'।

हमें ज्ञात ही है कि देव और दानव सभी शिवजी से तपस्या के पश्चात् कुछ वरदान तथा अस्त्र-शस्त्र अर्जित करते थे। लेकिन हमारे पौराणिक ग्रन्थ गवाह हैं कि भोलेनाथ ने सबकुछ तो दे दिया किन्तु अपना त्रिशूल किसी को नहीं दिया। उनका त्रिशूल अद्‌भुत वैज्ञानिक यंत्र था। आकाश, पाताल, पृथ्वी, हवा, पानी, नदी, पहाड़ और भूगर्भ की सम्पूर्ण जानकारी उसी त्रिशूल रुपी 'एण्टीना' से प्राप्त होती थी। आज भी रडार, टी.वी., टेलीफोन तथा लेसर यंत्र की सहायता से वर्षा, तूफान, ग्रहों का चित्रांकन और आकाशीय मार्ग की जानकारी संग्रहीत की जाती है। हमें यह भी पता है कि मनुष्य की प्राण शक्ति अल्फा, बीटा और गामा रश्मियों पर निर्भर है। त्रिशूल की आकृति इन्हीं तीनों किरणों की गति दिशा की प्रकट करती है जिसमें अल्फा किरण सीधे, बीटा किरण दायीं ओर तथा गामा किरण बायीं ओर झुककर चलती है। ये तीनों किरणें अपने पास संग्रहीत रखने के कारण भगवान शंकर मृत्युञ्जयी बने। प्राकृतिक विद्युत गिरने से बचाव करने के लिये आज भी तड़ित चालक में त्रिशूलाकार एण्टीना लगाया जाता है। जो त्रिशूल की वैज्ञानिकता को प्रकट करता है।

भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्म का लेपन करते थे, लोग आश्चर्य चकित होते थे। जबकि भस्मलेपन उनकी वैज्ञानिक क्रिया थी। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि परमाणु से निकलने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों से हमारी रक्षा का एकमात्र उपाय है शरीर पर भस्म का लेपन। चूंकि शिव जी

अपने पास पाशुपत अस्त्र धारण करते थे और पाशुपत अस्त्र परमाणु बम के समान था, इसलिये भस्म लेपन आवश्यक था।

महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से 'पाशुपत' अस्त्र प्राप्त किया था, किन्तु भोलेनाथ ने इसका प्रयोग पृथ्वी पर न करने की चेतावनी भी अर्जुन को दी थी। महाभारत युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व सभी श्रेष्ठ वीरों से जब पूछा गया कि इस युद्ध को आप कितने दिन में खत्म कर सकते हैं तब भीष्म ने उत्तर दिया पाँच दिन में, कर्ण ने उत्तर दिया दस दिन में किन्तु अर्जुन ने उत्तर दिया एक पल में। एक पल में महाभारत का युद्ध समाप्त करने का संकेत ही था कि उनके पास सुरक्षित है पाशुपत अस्त्र याने परमाणु बम। वैसे अर्जुन ने इस पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कालकेयपुर नामक ग्रह पर किया था, क्योंकि कालकेयपुर ने इन्द्र के विरुद्ध विद्रोह किया था तथा अर्जुन को परास्त भी किया था। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। उस कालकेयपुर की दशा द्वितीय विश्वयुद्ध में परमाणु बम के प्रयोग के पश्चात् हिरोशिमा और नागासाकी की भाँति ही हो गयी थी। आजकल वैज्ञानिक इलेक्ट्रोवेव का आविष्कार करके बहुत खुश हैं। इसके द्वारा भूमितल से ऊपर कर कुछ भाग सुरक्षित करने में सफलता प्राप्त हो गयी है। किन्तु हमारे यहाँ इसकी जानकारी तो पहले से ही थी। लक्ष्मण जी ने सीता माता की कुटिया के चारों ओर जो, लक्ष्मण रेखा खींची थी वह और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोवेव्स ही थीं, जिसे पार कर पाना रावण जैसे महान विज्ञानी के बस में भी नहीं था।

वर्तमान काल के वैज्ञानिकों ने साउण्ड राकेट की खोज की, जो ध्वनि का संकेत पाकर प्रक्षेपित किया जाता है। इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किसी टैंक, विमान या अन्य युद्धास्त्र की आहट सुनकर किया जाता है। प्राचीन काल में इसी आहट को सुनकर प्रक्षेपित किये जाने वाले बाण शब्द भेदी कहलाते थे। यही बाण तो राजा दशरथ ने चलाया था, जिससे श्रवण कुमार आहत हुये थे, तब इसे काल्पनिक कहा था आधुनिक विज्ञानियों ने।

ऐसा कहा गया कि राजा दशरथ चन्द्रमा

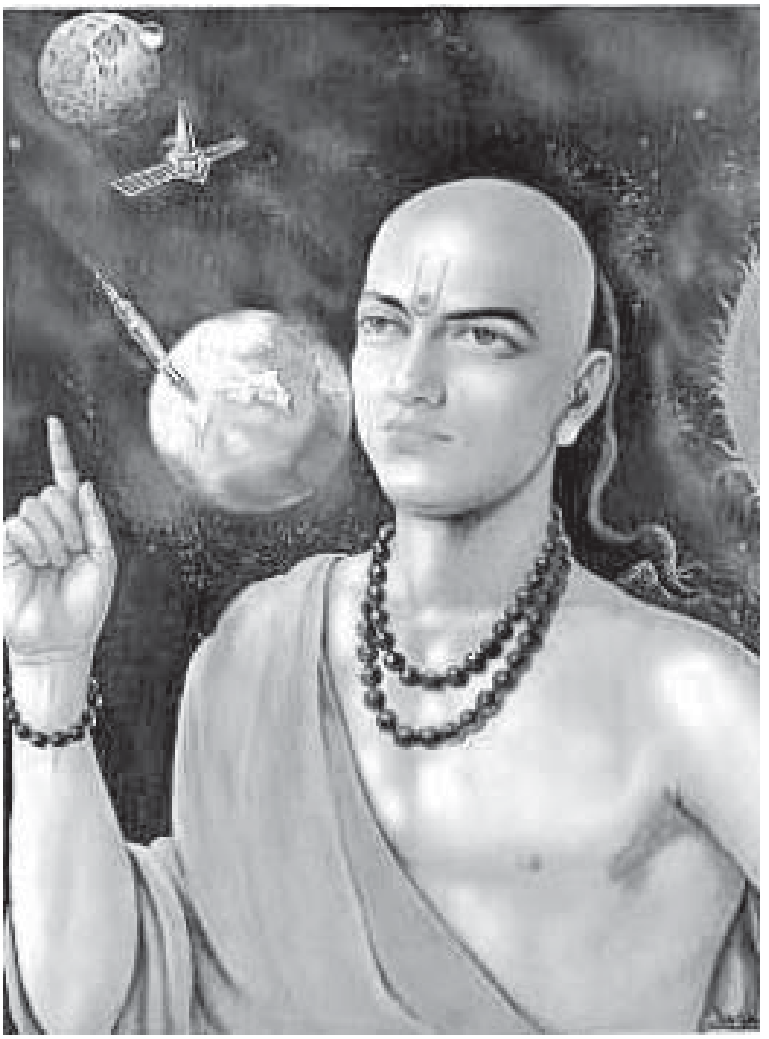

के विवाह में उपस्थित थे, लेकिन आज इसे मानने वाले लोग बहुत कम हैं, जबकि आधुनिक युग में तमाम लोग चन्द्रमा पर अपने पद चिह्न छोड़ आये हैं।

लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, तो सुदूर दक्षिण में स्थित लंका तक हिमालय पर्वत से औषधि लाना बहुत आश्चर्यजनक था, वह भी 8-10 घंटे के अंदर। किन्तु हमने देखा कि द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर ने क्रीट विजय के लिये विमान से बड़े-बड़े टैंक पहुँचाकर उनका प्रयोग किया, फिर हनुमान ही का लंका से आना जाना और पहाड़ लादकर लाना कैसे काल्पनिक कह दिया गया? कहते हैं जब हनुमान जी लंका वापस जा रहे थे तब शत्रु समझकर अयोध्या में भरत ने बाण चलाया जिससे वे भूमिपर आ गये, किन्तु कोई शारीरिक क्षति नहीं हुयी। इसे भी मनगढ़न्त ही कहा गया किन्तु कुछ दिनों पूर्व सोवियत संघ ने प्रक्षेपास्त्र की सहायता से अमेरिका के 'यू-विमान' को अनन्त ऊँचाई से नीचे उतारकर विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया।

प्राचीन काल में गंधर्व बाण के प्रयोग से सेनाओं का शत्रु-मित्र भाव समाप्त हो जाता था और सैनिक आपस में लड़ने लगते थे, यह बात भी अविश्वसनीय लगती थी किन्तु आधुनिक युग में आंसू गैस का प्रयोग या लाफिंग गैस का प्रयोग और उससे उत्पन्न स्थिति क्या इससे मिलती-जुलती नहीं है।

सुदर्शन चक्र की कार्य शैली बहुत विचित्र लगती थी, विश्वास भी कम ही होता था किन्तु आधुनिक काल में तमाम बम वर्षक विमान बन गये जो मानव रहित होते हुये निर्धारित लक्ष्य पर बम वर्षा करके पुन: अपने-अपने देशों को वापस आ जाने की क्षमता रखते हैं। इसे क्या माना जाय? आज तो मैग्नेटिक राकेट बन गये जो किसी वस्तु या विमान के पीछे पड़कर निर्धारित लक्ष्य तक प्रक्षेपित होते हैं। लूना, अपोलो चन्द्रग्रह पर भेजे गये और पुन: पृथ्वी पर वापस उतार लिया गया तथा आवश्यकतानुसार उनके मार्ग में परिवर्तन भी कर लिया गया। क्या इसे भी काल्पनिक कहा जायेगा?

'अक्षय तूणीर' जिसमें बाण कभी समाप्त ही नहीं होते थे आज की स्वचालित बन्दूकों को प्रकट करता है, जिसमें गोली समाप्त ही नहीं होती। पाञ्चजन्य शंख के उद्घोष से सेनायें कांप उठती थी, यह भी विश्वास लायक नहीं लगता। किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि राष्ट्र को प्रचण्ड से प्रचण्डतर बना देने पर मनुष्य का रक्त संचार थम जायेगा तथा हृदय का कम्पन भी रुक जायेगा। क्या पाञ्चजन्य की उद्घोष क्षमता ऐसे नहीं थी फिर अविश्वास क्यों?

पाण्डवों के अज्ञातवास में जब राजा विराट का गौधन लूटने कौरव आये, तो अर्जुन ने छद्मवेश में जिस प्रकार सम्मोहन बाण का प्रयोग करके कौरव सेना को दो-दो पहर अचेत कर दिया, वह भी आधुनिक युग के लिये कौतूहल का विषय था। किन्तु 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध में हमने देखा कि काइजर सेना ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध क्लोरीन गैस का प्रयोग करके अंग्रेजी सेना को 2-3 घण्टे के लिये बेहोश कर दिया। अब क्या अंतर है सम्मोहन बाण या क्लोरीन गैस की कार्यशैली में?

आज तो घर-घर में टेलीविजन है फिर भी लोगों को लगता है कि संजय महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन सी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुनाते थे।

भारत के प्राचीन विज्ञान के अनेक तथ्य ऐसे हैं जिनकी कोई तुलना आज नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में वैद्य का व्यवसाय करने वालों को एक शपथ लेनी पड़ती थी, जिसमें वैद्य का जीवन, व्यवहार, व्यवसाय की मर्यादा आदि कैसी हो इसका ऐसा उल्लेख था। किन्तु हमने उसे छोड़ दिया और यूनानी चिकित्सा हिप्पोक्रेट्स के नाम पर शपथ लेना प्रारम्भ कर दिया। यह बात अलग है कि पाठ्यक्रम से चरक द्वारा लिखी गयी चरक संहिता को बाहर निकाल पाना भारत के आधुनिक आयुर्वेद विशेषज्ञों के बस में नहीं है। संयोगवश सुश्रुत और पतंजलि को भी चिकित्सा शास्त्र में यथोचित स्थान नहीं मिला, यद्यपि पतंजलि द्वारा बतायी गयी राह पर चलकर योग ऋषि बाबा रामदेव दुनिया में लोकप्रिय हो गये।

इसलिये भारतवंशियों को चाहिए कि स्वयं को कुण्ठित बुद्धि मानकर पश्चिम का अंधानुकरण करने की गलती न करें और वापस लौटें अपने ज्ञान की ओर, अपनी भाषा की ओर, जिससे पौराणिक और वैदिक ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सके। आइये। विश्व में अतुलनीय अपने प्राचीन ज्ञान और विज्ञान पर गर्व करें तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानें।❑

(स्वतंत्र लेखक/ टिप्पणीकार)

शिक्षक की गरिमा

❑ शारदा कुमारी

संजीव शर्मा की टिप्पणी 'बाजार में शिक्षक' (शैक्षिक मंथन जुलाई 2014) बहुत कुछ कहने के लिए बाध्य कर रही है। संजीव जी ने तो सिर्फ इस वर्ष की प्रवीणता सूचियों में स्थान बनाने वाले बच्चों के सपनों का आंकलन किया है, मैं तो पिछले दस-बारह वर्षों से यह सब देख रही हूँ। मैं एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापकों की तैयारी से संबद्ध 'अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम' से जुड़ी हूँ। विद्यालयों में अध्यापन के लिए नौकरी पाने को आतुर युवक-युवतियों से भी मिलने के अवसर मिलते हैं, जब वे साक्षात्कार के लिए आते हैं। किसी न किसी रूप में प्रशिक्षणार्थियों से यह सवाल करने का मौका मिल ही जाता है कि आखिर क्यों वे अध्यापन और वह भी स्कूली अध्यापन के लिए तैयार हुए। जो पहली प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है, वह निश्चित रूप से बनावटी होती है। जैसे कि वे कहेंगे 'मुझे बचपन से ही बच्चों से प्यार है। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता/चाहती हूं। अध्यापन से अधिक कोई सम्मानजनक पेशा है क्या?' आदि-आदि।

इस तरह के जवाब देते समय वे इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की अपनी बेबसी और अनिच्छा को छिपाने की विफल कोशिशें साथ-साथ करते रहते हैं। आखिरकार बड़ी ईमानदारी से बता देते हैं कि 'अगर मैं ईमानदार उत्तर दूं तो मेरे साक्षात्कार पर उसका कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा?' पूरी तरह आश्वस्त हो जाने पर वे सच्चाई बयां करेंगे कि इच्छा तो उनकी एमबीबीएस, आइआइटी, आइआइएम जैसे पाठ्यक्रमों के लिए ही थी। चूंकि वे इस तरह के हर दरवाजे की चौखट से वापस कर दिए गए हैं तो अब उनके पास विद्यालय में अध्यापक बनने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। कुछ विद्यार्थी विशेषकर लड़कियां इसलिए इन पाठ्यक्रमों को चुनती हैं, क्योंकि उनके अभिभावक उनके मानस में ठूंसते रहेंगे कि 'लड़कियों के लिए स्कूल टीचिंग से बढ़िया और कोई नौकरी नहीं है।' पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तनख्वाह तो कहीं नहीं गई। आधे दिन की नौकरी और फिर बाकी समय अपना घर-बार संभालो।

कुछ लड़कों का उत्तर होता है कि 'जी अपना तो अच्छा-खासा व्यवसाय है। यह काम तो बस ऐसे ही पाकेट मनी के बतौर चुनना चाहते हैं। दो-चार घंटे स्कूल की तफरीह फिर अपने धंधे की देखभाल। कुछ लड़के कहेंगे कि माता-पिता को चाहिए कि हम जल्द से जल्द कमाई-धंधे में जुट जाएं। अब बाकी जगह तो काम की जबरदस्त मारामारी है। यहां तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है, भले ही अनुबंध पर क्यों न मिले।' मेरे सत्रह वर्ष के अनुभव में केवल सात-आठ ऐसे विद्यार्थी थे, जो बेशक दिल से अध्यापक बनने आए थे। खैर कारण कुछ भी रहा हो, दुख की बात यह है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तरह-तरह के तथ्यों को रटाने का काम तो बखूबी करते हैं, पर यह नहीं कर पाते कि उनके भीतर अध्यापन के प्रति रुझान पैदा कर सकें बल्कि उनके भीतर उपजी कुंठा और निराशा के समंदर को और गहरा करने का काम करते हैं। जैसा कि मेरे कुछ सहयोगी करते हैं, 'अरे बेटा! बारहवीं में इतने ऊंचे अंक लेकर भी यहां सड़ने आ गए, तुम्हें तो कहीं आइएमएम या आइआइटी में होना चाहिए था। हालांकि मैं उनसे उलझती भी हूं कि क्या स्कूलों को अच्छे अध्यापकों की जरूरत नहीं है! ❑

– आरकेपुरम्, नई दिल्ली

कुछ लड़के कहेंगे कि माता-पिता को चाहिए कि हम जल्द से जल्द कमाई-धंधे में जुट जाएं। अब बाकी जगह तो काम की जबरदस्त मारामारी है। यहां तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है, भले ही अनुबंध पर क्यों न मिले।' मेरे सत्रह वर्ष के अनुभव में केवल सात-आठ ऐसे विद्यार्थी थे, जो बेशक दिल से अध्यापक बनने आए थे। कारण कुछ भी रहा हो, दुख की बात यह है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तरह-तरह के तथ्यों को रटाने का काम तो बखूबी करते हैं, पर यह नहीं कर पाते कि उनके भीतर अध्यापन के प्रति रुझान पैदा कर सकें बल्कि उनके भीतर उपजी कुंठा और निराशा के समंदर को और गहरा करने का काम करते हैं। जैसा कि मेरे कुछ सहयोगी करते हैं, 'अरे बेटा! बारहवीं में इतने ऊंचे अंक लेकर भी यहां सड़ने आ गए, तुम्हें तो कहीं आइएमएम या आइआइटी में होना चाहिए था। हालांकि मैं उनसे उलझती भी हूं कि क्या स्कूलों को अच्छे अध्यापकों की जरूरत नहीं है!

शिक्षा से आएगा दुनिया में भारतीय युग

❑ केविन रैफर्टी

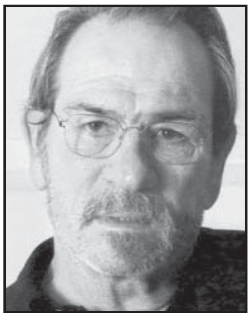

शिक्षा का अधिकार देने के लिए 63 लाख स्कूल शिक्षकों की जरूरत है। ये कहां से आएंगे खासतौर से तब जब शिक्षा के अधिकार के तहत पात्रता परीक्षा में सिर्फ एक प्रतिशत सफल हो पा रहे हैं। शिक्षकों के वेतन पर भी विकास संबंधी विशेषज्ञों के बीच विवाद है। यह कुछ तो सुधरा है पर फिनलैंड या सिंगापुर जैसे देशों के पासंग भी नहीं है जहां शिक्षकों को इंजीनियरों के समकक्ष वेतन दिया जाता है। फिर क्या पढ़ाया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का विश्वास है कि भारतीय स्कूलों को महात्मा गांधी की बजाय रवींद्रनाथ टैगोर के रास्ते पर चलने चाहिए। वे टैगोर को उद्धृत करते हैं जिन्होंने कहा था, 'भारत के हृदय पर मुफलिसी का जो बोझ है उसकी पूरी नींव शिक्षा के अभाव पर है।' सेन के मुताबिक भारत के शुरुआती योजनाकारों ने ढीले-ढाले ढंग से कहा था कि वे मूलभूत शिक्षा चाहते हैं। यह पूरी तरह गलत था। उन्हें बड़ी संख्या में अच्छे स्कूल चाहिए थे न कि चरखा चलाने वाले लोग या अस्पष्ट रूप से परिभाषित मूलभूत शिक्षा देने वाले शिक्षक।

थोड़े दिन पहले मैं उत्तरप्रदेश के एक गांव में गया था। वहां मैं पिछले 30 वर्षों से जा रहा हूँ। इस बार मुझे नई बात पता चली। गांव के मध्य में पांच-छह वर्ष से लेकर किशोर उम्र तक के 100 से ज्यादा बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे थे। पलटूका नांगला में आखिर स्कूल खुल ही गया। गांव आगरा से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह पिछली सदी का गांव लगता है। इसे प्रगति कहा जा सकता है। कम से कम इस अर्थ में कि बच्चों के पालकों ने शिक्षा के महत्व को तो पहचाना। यह निजी स्कूल है और पालकों को फीस देनी पड़ती है।

वहां सिर्फ पढ़ना-लिखना ही सिखाया जाता है, लेकिन भारत को यदि 21वीं सदी में उड़ान भरना है तो शिक्षा के लिए जनता की ओर से ऐसी जागरुकता की जरूरत है। यदि देश अपने बच्चों को शिक्षित कर सके तो आर्थिक वृद्धि दर भी बढ़ेगी और यदि इसमें नाकाम रहा तो युवा आबादी होने के जिस फायदे की बात की जा रही है, वह तो मिलेगा ही नहीं बल्कि यह एक टाइम बम साबित होगा, जो सारी उम्मीदों व सपनों को ध्वस्त कर सकता है।

अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। इसमें भारत में शिक्षा को लेकर प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान खींचा गया है। स्कूल शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी अनुपस्थिति। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सेन डिएगो के कार्तिक मुरलीधरन और वर्ल्ड बैंक व मिशिगन यूनिवर्सिटी के उनके सहयोगी लेखकों का अनुमान है कि स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति से भारत को सालाना 1.5 अरब डॉलर की चपत लगती है।

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों का स्कूल से गायब रहना भारत के लिए खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चंडीगढ़ जैसे अच्छे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षकों के गायब रहने की दर 15 प्रतिशत या इससे कम है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में तो यह 46 प्रतिशत तक है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अचानकनिरीक्षण के दौरान 23.6 प्रतिशत शिक्षक नदारद पाए गए। शायद यह अजीब लगे कि रिपोर्ट शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की वकालत नहीं करती बल्कि इसका कहना है कि शिक्षक-छात्र के बिगड़े अनुपात का

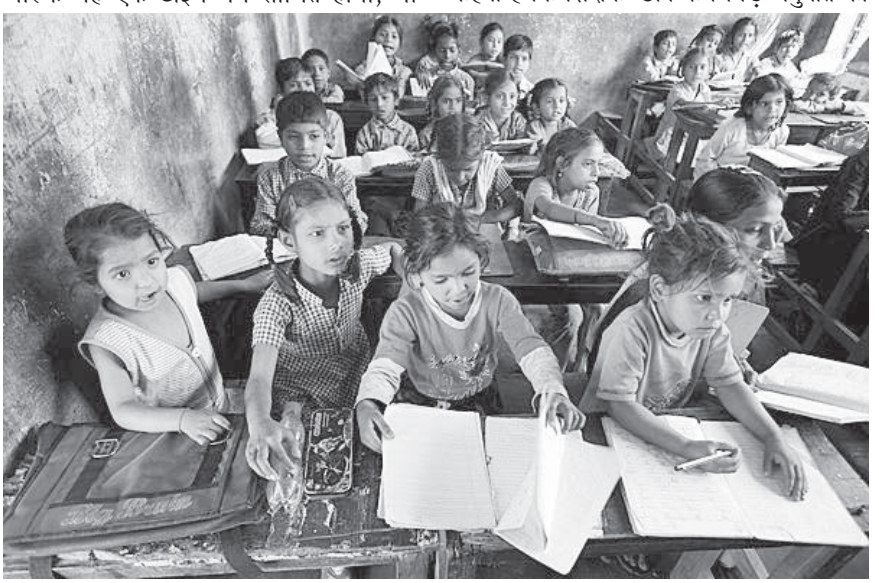

कारण शिक्षकों का गैर-हाजिर रहना ही है। यह जरूर कहा गया है कि अधिक स्कूल इंस्पेक्टर रखे जाएं ताकि शिक्षकों के गायब रहने पर अंकुश लगाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अधिक शिक्षक रखने की तुलना में यह दस गुना सस्ता पड़ेगा।

हालांकि, रिपोर्ट में केंद्र व राज्य सरकारों की इस बात के लिए तारीफ की गई है कि उन्होंने पिछले दशक में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च बढ़ाया है। इस रिपोर्ट से यह सवाल उठना चाहिए कि आखिर भारतीय शिक्षा किस दिशा में जा रही है और शिक्षा से जुड़े लोगों को इस बात का अहसास है कि नहीं कि इस मामले में क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है।

कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षा पर भारत का खर्च कम ही है। 2006 में भारत ने शिक्षा पर जीडीपी का 3.1 प्रतिशत खर्च किया। उसी वर्ष ब्रिटेन व अमेरिका की सरकारों ने 5.5 प्रतिशत खर्च किया। इसमें भी भारत ने उच्च शिक्षा पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा खर्च किया, जबकि ब्रिटेन में इसके उलट प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया गया। बावजूद इसके कि हाल ही में वहां यूनिवर्सिटी के स्तर पर शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ है।

भारत के सामने बहुत बड़ा मौका है। खासतौर पर तब जब चीन में आबादी तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है। 2020 तक भारत की औसत उम्र 29 वर्ष होगी, जबकि तब चीन व अमेरिका में औसत उम्र होगी 37 वर्ष। पश्चिमी यूरोप में 45 तो जापान में यह आंकड़ा होगा 48 वर्ष! इन सारे देशों में 65 वर्ष से ऊपर वालों की आबादी 25 प्रतिशत या इससे ज्यादा हो जाएगी। 2015 से 2040 तक का समय भारतीय युग होना चाहिए। तब तक इसकी श्रम शक्ति जबर्दस्त बढ़ जाएगी। यदि नई पीढ़ी को शिक्षा देकर मौका भुनाने लायक बनाया गया तो यह जबर्दस्त अवसर साबित होगा और यदि नई पीढ़ी कुपोषित, अशिक्षित और इसके कारण बेरोजगार रही तो यह आबादी बोझ साबित होगी। आलोचकों का कहना है कि दुनियाभर में प्रखर बुद्धिमत्ता वाले भारतीय मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, फार्चून 500 कंपनियों के मालिक, महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ। हालांकि, आंकड़े चकमा देते हैं, क्योंकि करोड़ों की आबादी वाले देश में ऐसे लोग कुछ लाख ही हैं। भारत के संगठित क्षेत्र में 30 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जबकि 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हवाले हैं। खेती में अब भी 60 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान 18 प्रतिशत ही रह गया है। जाहिर है उत्पादकता कम है और बेरोजगारी छद्म वेश में मौजूद है।

अच्छी बात यह है कि बेहतर शिक्षा की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। देश में शिक्षा का अधिकार तो लाया ही गया है, पालक भी अपने सीमित स्रोतों के बावजूद शिक्षा पर अधिक खर्च करने को राजी हैं। पिछले तीन साल में निजी स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों में जबर्दस्त इजाफा होकर इनकी संख्या 33 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पलटूका नांगला जैसे गांवों में भी 30 प्रतिशत छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि, गुणवत्ता को लेकर संदेह है। शिक्षा संबंधी गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम' के मुताबिक स्कूलों में दाखिले तो बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं। स्कूल में तीन साल बिताने पर भी 60 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे पढ़ नहीं पाते। दाखिला लेने वाले केवल 20 प्रतिशत बच्चे 12वीं कक्षा तक पहुंचते हैं यानी 2.70 करोड़ में से सिर्फ 54 लाख। समस्या फिर वही आती है। शिक्षा का अधिकार देने के लिए 63 लाख स्कूल शिक्षकों की जरूरत है। ये कहां से आएंगे खासतौर से तब जब शिक्षा के अधिकार के तहत पात्रता परीक्षा में सिर्फ एक प्रतिशत सफल हो पा रहे हैं। शिक्षकों के वेतन पर भी विकास संबंधी विशेषज्ञों के बीच विवाद है। यह कुछ तो सुधरा है पर फिनलैंड या सिंगापुर जैसे देशों के पासंग भी नहीं है जहां शिक्षकों को इंजीनियरों के समकक्ष वेतन दिया जाता है। फिर क्या पढ़ाया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का विश्वास है कि भारतीय स्कूलों को महात्मा गांधी की बजाय रवींद्रनाथ टैगोर के रास्ते पर चलने चाहिए। वे टैगोर को उद्धृत करते हैं जिन्होंने कहा था, 'भारत के हृदय पर मुफलिसी का जो बोझ है उसकी पूरी नींव शिक्षा के अभाव पर है।' सेन के मुताबिक भारत के शुरुआती योजनाकारों ने ढीले-ढाले ढंग से कहा था कि वे मूलभूत शिक्षा चाहते हैं। यह पूरी तरह गलत था। उन्हें बड़ी संख्या में अच्छे स्कूल चाहिए थे न कि चरखा चलाने वाले लोग या अस्पष्ट रूप से परिभाषित मूलभूत शिक्षा देने वाले शिक्षक। ❑

(प्लेनवर्ड्स मीडिया के एडिटर इन चीफ)

देशी भाषाओं में हों भर्ती परीक्षाएं

❑ वेदप्रताप वैदिक

सरकारी नौकरियों पर सिर्फ मुट्ठीभर लोगों का कब्जा बना रहेगा। शहरी, मालदार, ऊंची जातियों और अंग्रेजीदां लोगों का! देश के गरीब, ग्रामीण, वंचित, पिछड़े लोग नरेंद्र मोदी के राज में भी क्या वैसे ही रहेंगे, जैसे अंग्रेजों के राज में रहते आए थे? मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वह करिश्मा दिखाया था, जो भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। उन्होंने विदेशी नेता से अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बात की। उन्होंने सरकारी तंत्र को भी हिंदी में काम करने का आदेश दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन यदि संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर यही ढर्रा चलता रहा तो मोदी की छवि को गहरा धक्का लगेगा। यदि मोदी सरकार समस्त भारतीय भाषाओं को भर्ती-परीक्षाओं में उनका उचित स्थान दिलवा दें तो वे गुजरातियों और हिंदी भाषियों के ही नहीं, समस्त भारतीयों के प्रेमपात्र बन जाएंगे।

लोक सेवा आयोग की भर्ती-परीक्षा में 'सीसैट' के प्रश्न-पत्रों का इतना तगड़ा विरोध होगा, इसका अंदाजा न तो पिछली सरकार को था और न ही वर्तमान सरकार को। पिछले साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में जब इन छात्रों की पहली सभा को मैंने संबोधित किया था तो मुझे ऐसा जरूर लगा था कि यह आंदोलन पिछले कुछ हिंदी आंदोलनों की तरह बीच में ही ठप नहीं होगा, क्योंकि आंदोलनकारी छात्रों का भविष्य इस आंदोलन से सीधा जुड़ा हुआ था। लगभग दस लाख छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इन भर्ती-परीक्षाओं में अंग्रेजी का इतना बोलबाला है कि हिंदी माध्यम से पास छात्रों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। पिछले साल 1,122 लोग चुने गए, जिनमें से सिर्फ26 हिंदी वाले थे। शेष सभी भारतीय भाषाओं के सिर्फ27 लोग चुने गए यानी किसी भाषा के सिर्फ एक-दो आदमी सरकारी नौकरी में भर्ती हुए और किसी भाषा के एक भी नहीं! क्या दुनिया के किसी स्वतंत्र राष्ट्र में कभी ऐसा होता है? भारत की यह स्थिति तो गुलाम राष्ट्रों से भी बदतर है।

यह मामला सिर्फ हिंदी का नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं का है। जब मैंने 1965 में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपना पीएच.डी. शोधग्रंथ मातृभाषा (हिंदी) में लिखने की मांग की तो संसद में जबर्दस्त हंगामा हो गया। कई बार संसद ठप हुई। महीनों बहस चली। आखिर उच्च शोध के लिए भारतीय भाषाओं के द्वारा खुले। तब संसद में यह बहस भी चली कि सरकारी नौकरियों की भर्ती-परीक्षाएं सिर्फ अंग्रेजी में क्यों होती हैं? एक के बाद एक कई आयोग बने, लेकिन इन परीक्षाओं में बरसों-बरस अंग्रेजी का रुतबा ज्यों का त्यों बना रहा। लगभग 15 साल तक मेरे कुछ साथियों ने आयोग के द्वार पर लगातार धरना भी दिया। 12 मई 1994 को हमारे समर्थन में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह, अटलबिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार तथा अन्य कई नामी-गिरामी नेता भी शामिल हुए। आयोग की परीक्षाओं में धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं को छूट तो मिली, लेकिन अंग्रेजी की दमघोंटू अनिवार्यता अभी तक बनी हुई है। यही अनिवार्यता अब छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन सिर्फदिल्ली में हो रहा है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरू तथा अन्य प्रांतीय राजधानियों में भी काफी सुगबुगाहट है।

वर्तमान छात्र-आंदोलन का लक्ष्य सीमित है। यह केवल 'सीसैट' के प्रश्न-पत्रों को हटवाना चाहता है। 'सीसैट' भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का अंग्रेजी नाम है। इसका पूरा नाम है, 'सिविल सर्विसेस एप्टीट्यूड टेस्ट'। यानी सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वालों के बौद्धिक रुझान, मानसिक स्तर,

सामान्य ज्ञान आदि की परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इसमें तकनीकी, वैज्ञानिक, गणितीय और व्यावसायिक प्रश्नों की भरमार रहती है। इन्हीं विषयों को पढ़कर आने वाले छात्र उन प्रश्नों को दनादन हल कर लेते हैं और कला, सामाजिकी और मानविकी आदि विषय पढ़कर आने वाले छात्र बगले झांकते रहते हैं। यानी सीसैट प्रश्न-पत्रों का मूल चरित्र ही प्रश्नों के घेरे में है। इसके अलावा जो सवाल हिंदी में पूछे जाते हैं, उनकी हिंदी माशा अल्ला होती है, क्योंकि वह हिंदी नहीं अंग्रेजी का भ्रष्ट अनुवाद होता है। गूगल का ऊटपटांग अनुवाद दे दिया जाता है। जैसे 'स्टील प्लांट' का अर्थ 'लोहे का पौधा' और 'वॉचडॉग' का अर्थ 'कुकुरदृष्टि' कर दिया जाता है। अब छात्र क्या करें? जब प्रश्न ही पल्ले नहीं पड़ेगा तो वे उत्तर क्या देंगे? उन्हें हिंदी या मातृभाषा के माध्यम से परीक्षा देने की छूट जरूर है, लेकिन यह छूट भी क्या छूट है। सारे प्रश्न-पत्र सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में क्यों होते हैं? अन्य भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं?

इसके अलावा 200 अंकों के दो प्रश्न-पत्रों में 22 अंक के सवाल अंग्रेजी में होते हैं। उनके जवाब भी अंग्रेजी में देने होते हैं। इन 20-22 अंकों का घाटा जिन छात्रों को होता है, वे तो फिजूल में ही मारे गए न! भर्ती-परीक्षा में तो एक-एक अंक पर छात्रों का भविष्य बनता-बिगड़ता है।

आप उनकी योग्यता, कार्यक्षमता और बौद्धिक रुचि की परीक्षा ले रहे हैं या यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अंग्रेजी की रटंत-विद्या में निष्णात हैं या नहीं? अंग्रेजी की रटंत-विद्या से पैदा हुई नौकरशाही ने आजाद भारत में क्या गुल खिलाए हैं, यह सबको पता है। हमारे बड़े-बड़े नेता इसी अंग्रेजी की दहशत के कारण अपने नौकरशाहों के नौकर बने रहते हैं। कानून बनाने वाले सांसदों को कानून की धाराओं के सही अर्थ मालूम नहीं होते,

क्योंकि वे अंग्रेजी में बने होते हैं। हमारी अदालतों में बरसों तक करोड़ों मुकदमे क्यों लटके रहते हैं? उसमें बहुत-सी भूमिका अंग्रेजी की भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह मामला सिर्फ 'सीसैट' के प्रश्न-पत्रों का नही है, संपूर्ण भारत की शासन-व्यवस्था का है। यदि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी छाई हुई है तो आप उसे भर्ती-परीक्षा से कैसे हटा सकते हैं? सभी पिछली सरकारों ने इस मजबूरी के सामने घुटने टेके हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार भी यही करेगी?

मोदी सरकार ने छात्रों की मांग पर आवश्यक ध्यान दिया है। तुरंत कमेटी बैठाई, लेकिन कमेटी और आयोग ने टके-सा जवाब दे दिया है। वे कुछ भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। 24 अगस्त को परीक्षा होनी है। इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ किया तो कई छात्र आयोग के खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं। नौकरशाह यही कहेंगे, लेकिन मोदी-सरकार की यह अग्नि-परीक्षा है। या तो वह कोई बीच का रास्ता निकाले या सीसैट को ही रद्द कर दे। सिर्फ सीसैट को रद्द करना ही काफी नहीं है, वह अंग्रेजी के 'क्वालीफाइंग' पर्चे को भी रद्द करे। इस अंग्रेजी की अनिवार्य परीक्षा के अंक चाहे न जोड़े जाते हों, लेकिन यदि इसमें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के शेष पर्चे जांचे ही नहीं जाते हों तो क्या माना जाएगा? क्या यह नहीं कि भारत सरकार के अफसर बनने की सिर्फ एक ही योग्यता है- आपका अंग्रेजी ज्ञान! आपकी बाकी सभी योग्यताएं बेकार हैं। जनता की दृष्टि से इसका क्या अर्थ निकला? यही कि देश के लगभग 110 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चों का शासन-संचालन से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के खर्चीले स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। सरकारी नौकरियों पर सिर्फ मुट्ठीभर लोगों का कब्जा बना रहेगा। शहरी, मालदार, ऊंची जातियों और अंग्रेजीदां लोगों का! देश के गरीब, ग्रामीण, वंचित, पिछड़े लोग नरेंद्र मोदी के राज में भी क्या वैसे ही रहेंगे, जैसे अंग्रेजों के राज में रहते आए थे? मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वह करिश्मा दिखाया था, जो भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। उन्होंने विदेशी नेता से अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बात की। उन्होंने सरकारी तंत्र को भी हिंदी में काम करने का आदेश दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन यदि संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर यही ढर्रा चलता रहा तो मोदी की छवि को गहरा धक्का लगेगा। यदि मोदी सरकार समस्त भारतीय भाषाओं को भर्ती-परीक्षाओं में उनका उचित स्थान दिलवा दें तो वे गुजरातियों और हिंदी भाषियों के ही नहीं, समस्त भारतीयों के प्रेमपात्र बन जाएंगे। ❑

(भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष)

अखण्ड भारत कैसे ?

❑ सत्यपाल हर्ष

यह कोरी कल्पना नहीं हैं, कोटि कोटि हिन्दू हृदयों का विश्वास है। अखण्ड भारत के बारे में हमारे महापुरूषों ने जो भविष्यवाणियां की हैं, वे हमारे इस विश्वास को दृढता प्रदान करती हैं। हमारे महापुरुषों ने सारे विश्व के घटनाचक्र को बहुत पहले ही योग्य-दृष्टि से अत्यन्त सूक्ष्मता से देखा है। वे कहते हैं:-

स्वामी विवेकानन्दः

मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं परन्तु मुझे सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं कि 'भारत माँ' विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर अधिष्ठित हो चुकी हैं और उसका यश दिगदिंगत तक फैल रहा है, हम भारत माँ की आराधना करें। जब उन्हें (विवेकानन्द जी को) पूछा गया कि आपके इस मन्तव्य का आधार भी तो होना चाहिये। तब उन्होंने कहा था कि जब 1836 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था तब युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। युग सन्धि का काल 175 वर्ष का होता हैं। 1836 में 175 वर्ष जोड़ने पर 2011 होता है। उन्होंने कहा कि 2011 से भारत का भाग्य-सूर्य दुनियां में चमकना शुरू होगा और अब सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने का दायित्व भारत के ऊपर आने वाला है। आज 2014 में क्या हम आशा लगाये नहीं बैठे हैं? परिवर्तन अवश्यंभावी लग नहीं रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी एकात्म मानव दर्शन की पुस्तक में अंत में लिखा है, 'विश्व का ज्ञान और अपनी आज तक की परम्परा के आधार पर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक महान होगा जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ न केवल समग्र मानव अपितु सम्पूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार करता हुआ नर से नारायण बनने में समर्थ होगा।'

योगी अरविन्द

भारत विभाजन पर अत्यन्त ही करुणाजनक स्वर में 15 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा था, 'हम स्वतन्त्र अवश्य हुए हैं परन्तु यह स्वतन्त्रता अधूरी है। विभाजन अप्राकृतिक है, अखण्ड भारत नियति है, उन्होंने कहा, कुछ समय तक इसके कारण अनेक समस्याऐं पैदा होंगी तथा हम गलत रास्ते पर चलेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी तथा भारत को नया रास्ता दिखेगा। भारत अपने स्वत्व के जागरण के साथ ही अखण्ड होगा तथा विश्व में पुनरपि अपनी पहचान बनायेगा।'

महात्मा गाँधी :

'हिन्दुत्व सत्य के अनवरत अनुसंधान का दूसरा नाम है। आज हिन्दुत्व का भाव धूमिल हो गया है क्योंकि हम थक गए हैं। कल जब थकावट दूर होगी तब हिन्दुत्व अपने सम्पूर्ण शक्ति के साथ इतना जबरदस्त विस्फोट करेगा जैसा भूतकाल में कभी नहीं हुआ।' उन्होंने कहा, 'विस्फोट की घड़ी निकट है, हम सब लोग इसके लिए कमर कस लें।' संघ के अधिकारी भी अगली शताब्दी हिन्दू शताब्दी की बात कर रहे हैं। नास्त्रेदमस नामक एक भविष्य दृष्टा ने अठारहवीं शताब्दी में ही भारत के उत्कृष्ट भविष्य की घोषणा की है। परन्तु कुछ सहयोगी बन्धु जब शंका व्यक्त करते हुए प्रश्न करते हैं कि क्या अखण्ड भारत की हमारी कल्पना कभी साकार होगी? वे वातावरण के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहते हैं, कि ''पाकिस्तान तो अब स्थाई तथ्य (Settled Facts) हो चुका हैं। अब यह कैसे संभव होगा? इस विपरीत परिस्थिति में अनेक बन्धुओं का विश्वास हिल चुका है, परन्तु इतिहास के कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी गहराईयों में जाने से यह ध्यान में आता है कि इस निरन्तर बदलती हुई विश्व की परिस्थितियों में स्थायित्व जैसी कोई बात नहीं हैं। आज से पचास वर्ष पूर्व हममें से अनेकों नहीं थे और पचास वर्ष बाद हममें से कितने रहेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। याने यह विश्व निरन्तर बदलता ही जा रहा है, यह प्रकृति का स्वभाव है। विश्व की बदलती हुई परिस्थिति के कारण ही इतिहास में कुछ अनहोनी घटनाऐं सम्भव हो सकी हैं। निम्न उदाहरण साक्षी हैं तथा सम्भावना व्यक्त करते हैं कि भारत पुनरपि अखण्ड हो सकता है।

पाकिस्तान के पुरातत्वीय परामर्शदाता एम. वीलर ने '5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान' नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रचुर सामग्री है। ऋग्वेद, बुद्ध तक्षशिला तथा अशोक का भी वर्णन है। जातक कथाओं तथा हिन्दू मन्दिरों का भी उद्धरण हैं। वे सिद्ध करना चाहते हैं कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी इस देश में सिन्धु घाटी की सभ्यता थी जो एशिया में महानत सभ्यता रही है। ये सभी सांस्कृतिक चिन्ह वहां पर हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा ही सिद्ध करती हैं। पाणिनी, राजा दाहिर आदि महापुरूष हिन्दूओं के ही तो राष्ट्र पुरुष थे। ढाकेश्वरी तथा चटगाँव में भी तो हिन्दू मन्दिर स्थित हैं, सिद्ध करते हैं कि मुगलों के आक्रमण से पूर्व यह प्रदेश भारत का ही अभिन्न अंग रहा हैं। अंत में राम मनोहर लोहिया के इस कथन को न भुलावें।

6 नवम्बर 1991 को बर्लिन की दीवारों का टूटना, उसी समय रूस में कम्यूनिज्म की मृत्यु का घंटानाद का होना तथा ठीक उसी समय अयोध्या में राजमन्जभूमि का शिलान्यास होना, प्रकृति का विश्व को एक विशिष्ठ संकेत है। एक चीज उभर रही थी, दूसरी समाप्त हो रही थी।

किसको पता था कि 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में जबरदस्त विस्फोट होगा। बाबरी ढांचा ढहा दिया जायेगा, विश्व के लिए कल्पनातीत घटना सिद्ध हुई।

इज़राइल से यहूदियों को हमेशा-हमेशा के लिए खदेड़ दिया गया। 1800 वर्षों तक वे अपनी भूमि के दर्शन नहीं कर सके। परन्तु यह इतिहास का तथ्य है कि अपने देश के प्रति उत्कृष्ट भक्ति के परिणामस्वरूप वे अपने को पुनः स्वतंत्र करवा सके। ध्यान देने की बात है कि इतने लम्बे समय तक यहूदी लोग विश्व के अलग-अलग देशों में टुकड़ों में भटकते रहे। उन्होंने कष्ट भी खूब पाया, परन्तु अपने प्रिय मातृभूमि पेलेस्टाईन को भूल न पाये। जब भी दो यहूदी हॉटल अथवा रेस्टोरेन्ट में आपस में मिलते थे तब हमेशा एक वाक्य बोलते थे All right next time we will meet in urasliam (यूरेस्लियम), यद्यपि मिलते वहीं थे, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जब अंग्रेज जीत गये तब चर्चिल की मानवंदना करने के समय जब अंग्रेजों की जनता ने कहा कि, You are the Loin of our Country तब देशभक्त चर्चिल ने जवाब में कहा था, No-NO, I am not the Loin, I only roared on behalf of our Country's people जीत का सबसे बड़ा श्रेय तो उस यहूदी वैज्ञानिक को मिलना चाहिये, जिसने इस देश के लिये परमाणु-बम बनाया था। वैज्ञानिक ने भी देशभक्ति का परिचय देते हुए कहा 'मुझे कुछ नहीं चाहिये, मैंने तो अपनी मातृभूमि के लिये कर्तव्य का पालन किया हैं।' परन्तु जब बहुत आग्रह हुआ तब वैज्ञानिक ने कहा कि यदि कुछ देना ही है तो मेरे पेलेस्टाईन को स्वतंत्रता दिलवा दो और इस प्रकार 1800 वर्षों के उपरान्त यहूदी पुनः अपनी मातृभूमि के दर्शन कर सके। वह राष्ट्र पुनः जीवित हो उठा। मानो चिता से उठाकर खड़ा हो गया हो। क्या भारत के पुनः एकीकरण का स्वप्न इससे भी कठिन है ?

अंग्रेज लोग बड़े गर्व से कहते थे कि ''ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के विजयी होने के उपरान्त भी संसार ने देखा कि 1947 के बाद के दशक में अंग्रेजों के चंगुल से अनेक देश स्वतंत्र हुए और दुनिया इस बात को जानने लगी कि अब अंग्रेजों के राज्य में भी सूर्य अस्त होने लगा है।

उपर्युक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि दुनिया में बदल आता है और वह सब कुछ सम्भव है जो आज हमें असम्भव लगता है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि अपराजेय रावण भी समय आने पर निस्तेज हो गया था। दुनिया में भगवान ने ऐसी कोई काल-रात्रि नहीं बनाई है जिसका कोई सवेरा नहीं हो। आवश्यकता है अपने समाज के अबाल, वृद्ध व्यक्तियों में देश के प्रति निश्चल भक्ति उत्पन्न करने की। सिन्ध प्रान्त में ही भक्त प्रहलाद हुए थे, लवकुश का जन्म लाहोर में हुआ, ननकाना साहेब वहीं है, पचनद वहीं है, वहीं मोहनजोदड़ो, हिंगलाज माता का मन्दिर, ज्वालामुखी पर्वत सब वहीं हैं।

वहीं सरस्वती नदी के किनारे बैठकर हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की थी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में लाने से उस भूमि के चप्पे-चप्पे के प्रति आत्मीयता का भाव नैसर्गिक रूप से उत्पन्न होता है। यह भाव जैसे-जैसे प्रबल होगा, हम अपनी अधूरी स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता में अवश्य ही बदल सकेंगे।

केवल भारत का ही विभाजन नहीं अपितु विश्व के अनेक राष्ट्रों का साम्राज्यवादी शक्तियों की जालसाजियों के फलस्वरूप विभाजन किया गया। उत्तर व दक्षिण कोरिया का विभाजन, पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का विभाजन, वियतनाम का विभाजन, अलस्टर को आयरलैण्ड से पृथक करना आदि। इनमें से दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ तथा वियतनाम भी लम्बे और कठोर संघर्ष के बाद वह पुन: एक हो गया है। अत: इस बात की सम्भावना हैं कि प्रयत्न करने पर ये अप्राकृतिक विभाजन समाप्त किए जा सकते हैं।

पाकिस्तान के पुरातत्वीय परामर्शदाता एम. वीलर ने '5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान' नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रचुर सामग्री है। ऋग्वेद, बुद्ध तक्षशिला तथा अशोक का भी वर्णन है। जातक कथाओं तथा हिन्दू मन्दिरों का भी उद्धरण हैं। वे सिद्ध करना चाहते हैं कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी इस देश में सिन्धु घाटी की सभ्यता थी जो एशिया में महानत सभ्यता रही है। ये सभी सांस्कृतिक चिन्ह वहां पर हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा ही सिद्ध करती हैं। पाणिनी, राजा दाहिर आदि महापुरुष हिन्दूओं के ही तो राष्ट्र पुरुष थे। ढाकेश्वरी तथा चटगाँव में भी तो हिन्दू मन्दिर स्थित हैं, सिद्ध करते हैं कि मुगलों के आक्रमण से पूर्व यह प्रदेश भारत का ही अभिन्न अंग रहा हैं। अंत में राम मनोहर लोहिया के इस कथन को न भुलावें। 'पश्चाताप से पाप प्राय: धुल जाते हैं, किन्तु जिनकी आत्मा को विभाजन कुकृत्य से सन्तप्त होना चाहिये था वे ही लोग अपनी अपकीर्ति को धूल में लोट लगाकर प्रसन्न हो रहे हैं। आईये, अब जनता ही पश्चाताप कर लें- न केवल अपनी भूलचूक के लिये, बल्कि अपने नेताओं के कुकृत्यों के लिये भी।'

भारत फिर से अखण्ड होगा, यह तो तय है। कब होगा यह हमारे पौरुष और प्रयासों पर ही निर्भर है। वे लोग सौभाग्यशाली होंगे जो दृढ निश्चय के साथ अखण्ड भारत के लिये संकल्पबद्ध होंगे। याद रखो, 'संकल्प-बद्ध कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण करते हैं।' ❑

(शैक्षिक एवं सामाजिक अध्ययेता)

SARGUJA UNIVERSITY, AMBIKAPUR (CHHATTISGARH)

ADVERTISEMENT: TEACHING POSTS IN ARTS, SOCIALSCIENCES, SCIENCES, LIFE SCIENCES, LAW &ENGINEERING & TECHNOLOGY

Advertisement No. SUA/Estt.//2014; Dated:04th August 2014

Applications are invited from the Indian Nationals in prescribed format for the post of Professor,Associate Professor and Assistant Professor.

Faculty of Arts- Functional Hindi- Prof. UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, Asst. Prof. ST-1, **Faculty of Law- Legal Studies-** Prof. UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, Asst. Prof. UR-1/ST-1,**Faculty of Science/Life Sciences- Biotechnology-** Prof. UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, **Computer Science-** Prof. UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, Asst. Prof. ST-1,**Environmental Science-** Associate Prof. UR-1/ST-1, Asst. Prof. ST-1/ **Farm Forestry-** Prof. UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, **Pharmacy-** Prof. UR-1, Associate Prof. ST-1

Faculty/College of Engineering-Civil Engineering Prof. – UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, Asst. Prof. UR-1/SC-1, **Computer Science Engineering** - Prof. SC-1, Associate Prof. UR-1/ST-1,**Electrical Engineering-** Prof. UR-1, Associate Prof. UR-1/OBC-1, Asst. Prof. UR-1*/ST-1,**Mechanical Engineering** Prof. ST-1, Associate Prof. SC-1,**Chemistry -** Prof. OBC-1, **English** – Asst. Prof. SC-1, **Geology** – Asst. Prof. ST-1, **Mathematics** – Professor UR-1, Associate Prof. UR-1/ST-1, Asst. Prof. ST-1, **Physics:** Professor UR-1, Associate Prof. SC-1

Note: * stands for **"One"** post reserved for **female.**

The candidate(s) will download the format of **"Application Form"** from University website www.sargujauniversity.in The details of Qualifications, terms and conditions, distribution of posts in different categories (General (UR), SEBC/OBC, SC & ST etc.) and other relevant information are available on the University website.

Duly filled in application form, complete in all respect, together with all supporting documents must be submitted to the Registrar, Sarguja University, Ambikapur-497001 (C.G.) personally or through Registered/ Speed Post Mail along with a demand draft of Rs. 700/- for General and SEBC/OBC; and Rs. 500/- for SC/ ST categories in favour of the Registrar, Sarguja University, Ambikapur-497001 (C.G.) payable at Ambikapur on or before **15 September 2014** up to 05:00 P.M. The non-resident of Chhattisgarh, irrespective of reservation, has to submit demand draft of Rs. 700/- . Applications received after this date will not be entertained in any circumstances.

Note: *1. Candidate(s)submitting their application(s) for the post of Professor or Associate Professor are directed to fill the data required for the purpose of API on the calculators uploaded on the Sarguja University Website vide **SUA-API CALCULATOR** and take a hard copy and self attest their API scoring sheet with eligibility to submit it to the University along with their application form without failure.*

*2. For detail and application Performa: Refer*University website www.sargujauniversity.in

(R. K CHAUHAN)
REGISTRAR

रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा राजस्थान में गुरुवंदन के कार्यक्रम सम्पन्न

अखिल भारतीय योजनानुसार संगठन द्वारा गुरुवंदन कार्यक्रम व्यापक रूप में 54 स्थानों पर संपन्न किये गए।

चूरू में सम्पन्न कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रा.स्व.संघ के वरिष्ठ प्रचारक मा. नंदलालजी थे। उन्होंने पाथेय देते हुए कहा कि वैचारिक स्पष्टता रखते हुए देश का हर शिक्षक विद्यार्थियों को और अधिक सुसंस्कारित बनाए, हमें इस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसे अपने देश से प्रेम नहीं वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। संस्कृति को सम्मान दिए बिना किसी भी देश का गुरु ज्ञान सम्पन्न नहीं हो सकता। इस अवसर पर सेवानिवृत शिक्षक प्रो. बी. एल. वर्मा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य एम. डी. गोरा ने की। प्रो. भवानी शर्मा ने अतिथियों का परिचय कराया। संचालन प्रो. सुरेन्द्र डी. सोनी ने किया तथा प्रो. महावीर सिंह ने आभार जताया।

राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली में सम्पन्न गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उद्‌बोधन देते हुए शैक्षिक मंथन पत्रिका के संपादक प्रो. संतोष पाण्डेय ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेदव्यास की परम्परा को आगे बढ़ाना सभी शिक्षकों का दायित्व है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के अभीष्ट को सिद्ध करने में शिक्षकों को कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देना होगा तभी देश परम् वैभव प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य ने की।

डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संवितु सोमगिरी महाराज ने कहा कि संस्कृति के मूल रूप में वेदव्यास हैं। उन्होंने श्रुतियों में पाँच कृत्य बताए, जिनमें अनुग्रह गुरु है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. कृष्णा राठौड़ तोमर ने की। संचालन इकाई सचिव मूलचन्द माली ने किया।

राजर्षि महाविद्यालय, गौरीदेवी कन्या महाविद्यालय एवं कला महाविद्यालय, अलवर की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवंदन कार्यक्रम कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं संत श्री सुदर्शनचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में सम्पन्न हुआ। डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने प्रबोधन करते हुए कहा कि जीवन मूल्यों के क्षरण को रोकने में शिक्षक ही प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। सतं सुदर्शनाचार्यजी ने शिक्षकों से ऐसे गुण विकसित करने का आह्वान किया जिससे समाज और विद्यार्थी प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम का संचालन संगठन के प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ. गंगाश्याम गुर्जर एवं विभाग अध्यक्ष डॉ. शशिकांत गुप्ता ने किया तथा धन्यवाद डॉ. धनंजय सिंह ने ज्ञापित किया।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रो. कैलाश भसीन ने कहा कि गुरु को अपने शिष्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण हेतु प्रयास करना चाहिए तभी शिष्य की गुरु के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास बना रहेगा। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. विजयलक्ष्मी महेन्द्रा ने की, संचालन विभागीय सचिव डॉ. श्यामलाल ने किया।

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर में गुरुवंदन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गुरुसिंह सभा के जिलाध्यक्ष सरदार श्री तारासिंहजी थे। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में गुरु की महत्ता बताते हुए कहा कि गुरु अपने शिष्यों को मात्र किताबी ज्ञान ही नहीं देता अपितु मानव जीवन में आने वाली जटिल परिस्थितियों से अवगत करा उसका मार्गदर्शन करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अशोक बंसल ने की। संचालन डॉ. सुनील गुप्ता ने किया एवं आभार प्रदर्शन डॉ. मानवेन्द्र चतुर्वेदी ने किया।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में गुरु में गुरु पूर्णिमा पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें संगठन उपाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा, शैक्षिक प्रकोष्ठ संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा, संयुक्त निदेशक डॉ. अनूप श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. रामनिवास चौधरी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉ. अखिलेश्वर शर्मा, प्रांतीय अंकेक्षक डॉ. सोमकांत भोजक ने अपने विचार रखे।

राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल में गुरुवंदन कार्यक्रम प्रो. भेरसिंह के मुख्य आतिथ्य एवं डॉ. अरुण कुमार दवे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। संचालन विभागीय सह सचिव प्रो. संदीप शर्मा ने किया।

राजकीय बागंड़ महाविद्यालय, डीडवाना इकाई द्वारा सम्पन्न गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. मोहनलाल वर्मा ने कहा कि मानव को जीवनोपयोगी ज्ञान एवं विवेक की प्राप्ति के लिए अनेक उपक्रम एवं माध्यम उपलब्ध है किन्तु इन सब माध्यमों में गुरु ही श्रेष्ठ माना जाता हैं क्योंकि गुरु अपने शिष्यों की जिज्ञासाओं का शमन करने के साथ उनके जीवन की दशा एवं दिशा भी तय करता हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रो. चन्द्रप्रकाश, इकाई अध्यक्ष डॉ एन. आर. ढाका, इकाई सचिव डॉ. गजादान चारण एवं वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. चन्द्रप्रकाश गौड़ ने भी कार्यक्रम में विचार व्यक्त किये। आभार प्रदर्शन विभागीय सहसचिव डॉ. ओमप्रकाश शर्मा ने किया।

राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर

में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय मंत्री श्री हरिप्रसाद शर्मा थे। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान तथा नैतिक, बौद्धिक उन्नयन में शिक्षकों की अहम भूमिका है। अपनी समृद्ध परम्परा के अनुसार ही हमें गरिमामय आचरण करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपाचार्य डॉ. रमेशचन्द वर्मा ने की तथा संचालन इकाई सचिव विजयसिंह जाट ने किया।

राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें वक्ताओं डॉ. सजंय भल्ला, डॉ. चम्मा अग्रवाल, प्रो.आशुतोष बिरला, डॉ. प्रतिभा किरण ने प्राचीन गुरु शिष्य परम्परा का स्मरण करते हुए शिक्षकों के समाज के प्रति दायित्वों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. कृष्ण कुमार ने की। संचालन विभागीय सह सचिव डॉ. राहुल सक्सेना ने किया। राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्तव्य विद्या भारती के श्री वासुदेव प्रजापति द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रिछपालसिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. ओ. पी. देवासी ने दिया। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा में प्राचार्य प्रो. आर. के. वैद की अध्यक्षता में गुरुवंदन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. एम. एल. साहू थे। मुख्य अतिथि डॉ. एस. एन. गर्ग एवं विशिष्ठ अतिथि श्री ओ. पी. गर्ग थे। कार्यक्रम का संचालन इकाई सचिव डॉ. अशोक गुप्ता ने किया।

राजकीय महाविद्यालय, जयपुर में मुख्य अतिथि डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने शिक्षक एवं विद्यार्थियों के आदर्श जीवन मूल्यों एवं लक्ष्यों के बारे में प्राचीन से लेकर अर्वाचीन उदाहरणों द्वारा मार्गदर्शन दिया। प्राचार्य डॉ. सुभाषचन्द्र गुप्ता ने धन्यवाद दिया तथा संचालन डॉ. जमनालाल शर्मा द्वारा किया गया। एम. एस. जे. महाविद्यालय, भरतपुर में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्तव्य देते हुए श्री वासुदेव गुप्ता, पूर्व अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा कि ज्ञानदाता के रूप में गुरु ब्रह्मा है, ज्ञान को पुष्ट करने, उसके संवर्धन करने के रूप में वह विष्णु है तथा पथ भ्रमित शिष्य को सद्मार्ग प्रदर्शन के रूप में गुरु महेश है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपाचार्य डॉ. कमलनयन एवं अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा थे। संचालन इकाई सचिव डॉ. अनिल सक्सेना एवं आभार प्रदर्शन विभागीय अध्यक्ष डॉ. जग्गोसिंह ने किया। राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक में गुरुवंदन कार्यक्रम में ख्यातनाम चित्रकार एवं शिक्षक श्री कन्हैयालाल ने मुख्य वक्तव्य देते हुए शिक्षकों एवं छात्रों से भारतीय संस्कृति के अनुरूप व्यवहार कर शिक्षा जगत को प्रकाशित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य श्री अरविन्द कुमार ने की तथा संचालन प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री गिरधारीलाल रैगर ने किया।

श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर में गुरुवंदन कार्यक्रम प्राचार्य श्री हनुमानाराम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संगठन मंत्री ग्यारसीलाल जाट ने भारत की गुरु परम्परा एवं हमारा दायित्व विषय पर मार्गदर्शन देते हुए अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। एस. डी. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें विभागीय अध्यक्ष प्रो. पुखराज देपाल सहित अनेक शिक्षकों ने भारतीय गुरु परम्परा पर अपने विचार व्यक्त किये। राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में गुरुवंदन कार्यक्रम संगठन अध्यक्ष एवं प्राचार्य डॉ. मधुर मोहन रंगा की अध्यक्षता एवं शिक्षाविद् डॉ. श्याम सुन्दर भट्ट के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। डॉ. भट्ट ने अपने उद्बोधन में कहा शिक्षक को गुरु बनना है तो छात्र के समग्र कल्याण को केन्द्र में रखना होगा तथा स्वयं के निरन्तर विकास का प्रयत्न शिष्य के उन्नयन को दृष्टिगत रख कर करना होगा। विषय प्रर्वतन महामंत्री ने किया। संचालन डॉ. जितेन्द्र थड़ानी एवं आभार प्रदर्शन डॉ. एस. के. बिस्सु ने किया। राजकीय महाविद्यालय, नोखा में गुरुवंदन कार्यक्रम के अर्न्तगत एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डॉ. सुमन राठौड़ , डॉ. मदन सैनी, डॉ. सुनील व्यास, डॉ. सुलोचना पूनिया, डॉ. एच. एम. देवड़ा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यवक्ता डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, मुख्य अतिथि डॉ. फूलचन्द भिण्डा ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों को बनाये रखने का कार्य शिक्षक ही कर सकते हैं। डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि मनुष्य के जीवन में अज्ञान का अंधेरा गुरु ही दूर कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सरस्वती मित्तल ने किया, धन्यवाद ज्ञापन इकाई सचिव डॉ. सूरजमल चांदोलिया ने किया।

राजकीय महाविद्यालय, कोटा में सम्पन्न गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री बृजमोहन शर्मा पूर्व शिक्षा उपनिदेशक ने गुरु एवं गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताते हुए महर्षि वेद व्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अनेक दृष्टांतों द्वारा समझाया। विषय प्रवर्तन विभागीय अध्यक्ष डॉ. बृज कुमार योगी ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. टी. सी. लोया एवं विशिष्ट अतिथि डॉ. सीताराम गालव थे। संचालन डॉ. सुलेखा जोशी एवं प्रो. सोहराब शर्मा ने किया। राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. मुरली मनोहर अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य वक्तव्य डॉ. शिव सिंह दुलावत ने दिया जबकि संचालन इकाई सचिव डॉ. रामसिंह भाटी ने दिया।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की प्रान्त बैठक शिमला में सम्पन्न

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव एवं उतर क्षेत्र प्रमुख जगदीश चौहान की अध्यक्षता में रा.व.मा.पा. छोटा शिमला में संपन हुई जिसमें प्रदेश के 11 जिलों के प्रधान, महासचिव व प्रदेश कार्यकारिणी के 109 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में महासंघ ने जिन मुदों पर चर्चा की उसमें आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया शाश्वत जीवन मूल्यों पर चर्चा के साथ साथ प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम को 31 अगस्त को शिमला में मनाने का फैसला लिया, प्रदेश के 600 से ज्यादा शिक्षक, अधिकारी भाग लेंगे तथा राज्यस्तरीय शाश्वत मूल्यों पर एक कार्यशाला काँगड़ा में नवम्बर में कराने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश का एक मात्र ऐसा संगठन हैं जो अपनी मांगों को मनवाने से पहले अध्यापकों के कर्तव्य का ध्यान रखते हैं। इस नाते से हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शाश्वत मूल्यों को लेकर पूरे पांच साल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला किया।

बैठक में चर्चा के साथ सरकार से मांग की कि हाल ही में सरकार ने जिस प्रकार के फैसले लिए हैं जो हिमाचल के कर्मचारी विरोधी हैं। जिसमें सरकार ने पदोन्नति पर मिलने वाले आर्थिक लाभ जिसे वित् सचिव ने बंद कर दिया है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाये।

शिक्षक महासंघ ने शिक्षा सचिव और मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र द्वारा अनुरोध किया कि शिक्षा क्षेत्र में 5 वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू की जाए। बैठक में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हिमाचल में मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाने का धन्यवाद किया।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार को आगाह किया हैं की कर्मचारी विरोधी फैसले वापस ले अन्यथा हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ विधानसभा का घेराव करेगा।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा गुरुवन्दन कार्यक्रम सम्पन्न

प्रदेश में जहा कई शिक्षक संगठन हैं जिनका मकसद सिर्फ सरकार के सामने अपनी मांगों को उठाना है इन संगठनों से बहुत दूर अपनी पहचान और सामाजिक कार्य को शिक्षकों और बच्चों को समाज में विशेष योगदान देने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने आज शिमला और हिमाचल के कई जिलों में प्रतिभा समान समारोह और गुरु पर्व दिवस के रूप में मनाने के क्रम में शिमला में राष्ट्रीय विद्या मंदिर में हिमाचल प्रदेश के 76 से ज्यादा शिक्षाविदों और गुरुओं को शिक्षा क्षेत्र में दिए योगदान के लिए सम्मानित किया।

प्रतिभा सम्मान समारोह में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों से उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में स्कूल, खंड, जिला, राज्य तथा देश में अपनी-अपनी क्षेत्र में योगदान दिया है, प्रतिभा सम्मान समारोह में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने आज हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 340 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव जगदीश सिंह चौहान, प्रान्त अध्यक्ष पवन मिश्रा मौजूद थे। जहां हिमाचल में विभिन्न संगठन सिर्फ मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं वही हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज के विचार पर काम करते हैं जिससे शिक्षा को बाहरी ताकतों से बचाया जा सके। इस कार्यक्रम को करने के लिए हिमाचल के सभी अध्यापक अपनी ऐच्छिक निधि से दान करता हैं जिससे हम बच्चों को सम्मानित करते हैं।

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा गुरुवन्दन कार्यक्रम सम्पन्न

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की योजनानुसार म.प्र. शिक्षक संघ जबलपुर इकाई द्वारा गुरुवंदन कार्यक्रम महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.विद्यालय में भारत माता, सरस्वती माता एवं महर्षि वेदव्यास के तैल चित्र पर पुष्पार्पण कर दीप प्रज्ज्वलन के साथ प्रारंभ किया गया।

प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सुरेश्वर शर्मा पूर्वकुलपति शिक्षाविद् ने कहा कि गुरु वह है जो शिष्य में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को आलोकित करता है। आचार्य वह है जो आचरण में सिखा दे कि वह आचार्य है।

कार्यक्रम में प्रो. राधिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि गुरु ब्रह्म, विष्णु व महेश से ऊपर है। इसलिए गुरु की वंदना करना चाहिए। गुरु कुछ लेता नहीं है, सिर्फ ज्ञान देने का ही काम करता है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक ईश्वरी प्रसाद तिवारी एवं सहायक प्राध्यापक ईश्वरी मुखी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया। प्रान्त संगठन मंत्री किशन लाल नाकडा ने राष्ट्रहित, शिक्षाहित, छात्रहित व शिक्षक हित पर कार्य किए जाने पर बल दिया गया है।

नीमच (म.प्र.) में सम्पन्न गुरुवन्दन कार्यक्रम

शिक्षकों को समय पर शाला पहुंचने की दिलाई शपथ

आज का दिन हम सभी के लिये आत्मावलोकन का विषय है जब पूरा विश्व आज भारत की ओर निहार रहा है। ऐसे समय में हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस संधिकाल में हम पूर्ण क्षमता व मातृभक्ति भाव से अपने दायित्वों का पालन कर देश की उन्नति में योगदान करें । हमारे पास जो बच्चे पढने आते हैं वे वंचित वर्ग व गरीब समुदाय के हैं। उन सभी को योग्य शिक्षा देना हमारा गुरुत्तर दायित्व है। म.प्र. शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री हिम्मत सिंह जैन ने उक्त विचार व्यक्त करते हुये नीमच में गुरुवन्दन कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों से पूर्ण कर्तव्य भाव से समय से शाला में पहुंचने व समय से शाला छोड़ने की शपथ दिलाई।

म.प्र. शिक्षक संघ जिला शाखा नीमच द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक विष्णुसेन कछावा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति बनाने वालों की अदूरदर्शिता के कारण आज शिक्षा की दुर्दशा हुई है । इतने वर्षों के उपरांत शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाना इसी अनीति का परिणाम है ।

क्षेत्र प्रमुख रामकृष्ण नवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षकों की वंदना का या स्वागत का नही वरन् शिक्षकों की सामर्थ्य को बताने का हैं। शिक्षकों को यह समझना चाहिये कि वे केवल शासकीय कर्मचारी ही नहीं है अपितु राष्ट्र निर्माण के प्रमुख अंग हैं। उन्हें स्वयं को पहचान कर समाज में सहभागिता एवं समरसता का कार्य करना होगा।

अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती एवं महर्षि वेदव्यास के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रांरभ किया गया। जिलाध्यक्ष बद्रीलाल पुरोहित ने अपने स्वागत उद्‌बोधन से अतिथियों का परिचय कराया। दिलीप सांखला प्रांतीय सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विजय तिवारी जिला सचिव एवं मन्नालाल बोहरा कोषाध्यक्ष द्वारा तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। जिला, तहसील, ब्लॉक व नगर की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

दिल्ली अध्यापक परिषद् नगर निगम निकाय द्वारा आयोजित गुरुवन्दन कार्यक्रम

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर में 15 जुलाई को दिल्ली अध्यापक परिषद ने गुरु वन्दन कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी दिल्ली नगर निगम ईस्ट लक्ष्मी मार्किट में किया गया। कार्यक्रम का प्रारम्भ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ सरस्वती वन्दना से हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र चौहान (अध्यक्ष दिल्ली अध्यापक परिषद, निगम निकाय) ने किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मोहन लाल 'प्रान्त कार्यवाह (प्रोढ़) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों को स्वकर्त्तव्य के प्रति जागरुक कर प्रोत्साहन प्रदान किया। विशिष्ट अतिथि शंकर दत्त (प्रचारक पूर्वी दिल्ली व यमुना विहार विभाग) की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव (प्राथमिक संवर्ग) श्री जगदीश चौहान ने संगठन का परिचय कराया तथा शिक्षकों के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हर्षदीप मल्होत्रा (अध्यक्ष शिक्षा समिति, पूर्वी दिल्ली नगर निगम) ने शिक्षकों को अपना आचरण अनुकरणीय बनाने पर बल दिया।

अन्त में अध्यक्षीय संबोधन के पश्चात् राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम से कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन पुष्पेन्द्र सिंह मंत्री निगम निकाय ने किया। कार्यक्रम में लगभग 300 शिक्षकों की सहभागिता रही तथा इस अवसर पर शिक्षकों ने अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में रतनलाल शर्मा महामंत्री दिल्ली अध्यापक परिषद, राजेन्द्र स्वामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली अध्यापक परिषद, राकेश जैन कोषाध्यक्ष, सुभाष चन्द उपाध्यक्ष निगम निकाय, ज्ञानेन्द्र जी संगठन मंत्री निगम निकाय, प्रवीण कुमार शर्मा संयुक्त मंत्री निगम निकाय, योगेश कुमार, देवकान्त बरुआ, राकेश कुमार जैन, सन्तोष यादव, सोनू कुमार, श्रीमती रंजना हटवाल एवं श्रीमती ऋचा गर्ग आदि का विशेष रूप से उपस्थित रहे।

भावनगर में सौराष्ट्र संभाग की बैठक सम्पन्न

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सौराष्ट्र संभाग की बैठक दिनांक 20.7.2014 को संत कंवरराम हाईस्कूल, भावनगर पर आयोजित की गई। जिसमें सौराष्ट्र संभाग के भावनगर, राजकोट, जूनागढ, सुरेन्द्रनगर और कच्छ जिले से आये हुए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने एवं युनिवर्सिटी के विभिन्न विभाग के प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया।

इस बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख एवं माध्यमिक संवर्ग के राष्ट्रीय सहसचिव मोहन पुरोहित, गुजरात प्रांत अध्यक्ष घनश्यामभाई पटेल, गुजरात प्रांत महामंत्री भीखाभाई पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भावनगर विभाग कार्यवाह देवेन्द्रभाई दवे ने उपस्थित रह कर अपने बौद्धिक वक्तव्य से सभी शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया। शिक्षकों को राष्ट्रवाद के प्रति जागरुक किया गया और शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सौराष्ट्र संभाग के संयोजक के तौर पर भाविनभाई एस. भट्ट की घोषणा की गई। समग्र बैठक का संचालन प्रा.शि. समिति, भावनगर के शिक्षक परेशभाई कलसरिया ने किया। 2014-15 के साल के लिए संगठन सदस्यता का पंजीयन किया गया।

मथुरा जनपद में गुरुवन्दन कार्यक्रम सम्पन्न

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ.प्र. जनपद मथुरा ने केन्द्र के निर्देश पर सत्रारम्भ में 'गुरु वन्दन' कार्यक्रम मथुरा-वृन्दावन मार्ग स्थित श्री कृष्ण चन्द्र गाँधी विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज के सभागार में समारोहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर बी.एस.ए. कॉलेज, मथुरा के प्राचार्य डॉ. वीरेन्द्र मिश्र ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने सम्बोधन में महाभारत ग्रंथ के रचनाकार 'महर्षि वेदव्यास' के जीवन को प्रेरणास्पद एवं अनुकरणीय बताते हुये विस्तार से प्रकाश डाला। संगठन के प्रादेशिक अध्यक्ष (मा. संवर्ग) डॉ. विनोद बनर्जी ने ऋषि-मुनियों के देश भारत में 'महर्षि वेदव्यास' जैसे महापुरुषों को भारतीय सनातन संस्कृति का आदि-पुरुष बताया। उन्होंने नवयुवकों को अपने शिक्षकों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखने हेतु प्रेरित किया।

भिवानी (हरियाणा) में गुरुवन्दन कार्यक्रम सम्पन्न

भिवानी में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने राजकीय उच्च विद्यालय रामपुरा में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविदों ने गुरु की महत्ता, समाज की आवश्यकता और विद्यार्थियों की कर्त्तव्यनिष्ठा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी भानाराम शर्मा व अध्यक्षता प्राचार्य रणवीर सिंह ने की।

रा. शि. संघ (राष्ट्रीय) द्वारा प्रदेश में गुरु वन्दन कार्यक्रम सम्पन्न

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से शुरू गुरु वन्दन कार्यक्रम राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जिला जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय का प्रदेश कार्यालय सभा भवन में सायं 4.00 बजे माननीय रामचरण बोहरा सांसद लोक सभा क्षेत्र जयपुर शहर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय शंकर प्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष, संस्कार भारती राजस्थान क्षेत्र रहे।

मुख्य वक्ता श्री शुक्ल ने अपने उद्बोधन में गुरु परम्परा पर प्रकाश डाला एवं गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करते हुए अच्छे समाज के निर्माण में गुरु की महती भूमिका बताई। श्री शुक्ल ने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समाज की धारा में बहने की बजाय ऐसे मानदण्ड स्थापित करें जिससे समाज प्रेरणा ले सके। उन्होंने वर्तमान में भारतीय संस्कृति के पुरातन मूल्यों के साथ वर्तमान परिदृश्य के समायोजन की बात कही। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में गुरुओं को सादर नमन करते हुए राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे अच्छे छात्रों का निर्माण करें जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन कर सके।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) उपशाखा आबूरोड द्वारा 14 जुलाई को दरबार स्कूल परिसर स्थित बी.आर.सी.एफ भवन में गुरु-वन्दन कार्यक्रम समारोहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पश्चिम क्षेत्र प्रमुख मोहन पुरोहित ने गुरु को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बताते हुए राष्ट्रीय सोच वाले शिक्षकों के निर्माण की नितान्त आवश्यकता की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पाली विभाग सेवा प्रमुख (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) भूराराम पुरोहित ने कहा गुरु को तत्व रूप में न की शरीर रूप में स्वीकार करें। गुरु वंदनीय है उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर उनके प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा रखें तभी जीवन सफल होगा।

पुरुलिया (प. बंगाल) में आयोजित गुरुवन्दन कार्यक्रम

13 जुलाई 2014 रविवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के राजगड़िया धर्मशाला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नियोजित बंगीय नव उन्मेष प्राथमिक शिक्षक संघ ने 'गुरुवन्दन कार्यक्रम' सम्पन्न किया। यह कार्यक्रम महर्षि वेदव्यास, माँ सरस्वती एवं भारत माता के चरणों में पुष्पार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया एवं सरस्वती वन्दना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में महर्षि वेदव्यास के गुणों और महत्वों पर चर्चा की। बंगीय शिक्षक और शिक्षाकर्मी संघ के राज्य प्रदेशाध्यक्ष अबनी भूषन मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बांकुड़ा विभाग के विभाग संघचालक असित कुमार डे एवं पुरुलिया चित्तरंजन उच्च विद्यालय के प्रधान शिक्षक तथा शिक्षाविद् विवेकानन्द चैटर्जी ने विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर देश एवं समाज के गठन में शिक्षकों की भूमिका, उद्योग एवं करणीय विषयों के ऊपर चर्चा की। कार्यक्रम संचालन पार्थ गांगुली ने किया।

Odisha Rashtravadi Shiksha Parishad Observes Guru Purnima

The Fakir Mohan (FM) University unit of the Odisha Rashtravadi Shiksha Parishad observed Guru Purnima in the premises of Saraswati Shishu Mandir, Soro in the district of Balasore on 12th July. Dr. Banshidhar Dash, President of the unit was in the chair and Dr. Pabitra Kumar Ratha, General Secretary of the Parishad was the Chief Guest. Dr. Ratha highlighted the timeless contributions of Maharsi Vyasa to our literature. Dr. Narayan Mohanty. Secretary of the Higher Education Wing of ABRSM also addressed the teachers. Shri Dharmendra Das, Secretary of the FM University unit proposed a vote of thanks.

The Utkal University unit of the Parishad also observed Guru Purnima in the vicinity of Saraswati Shishu Mandir, Narasinghpur in the district of Kendrapada the same day. Well-known environmentalist Shri Prasanna Kumar Parida presided over the meeting and Dr. Chaitanya Charan Parida. Secretary of the Utkal University unit was the Chief Guest. Dr. Parida explained the significance of Guru Purnima in our age-old culture. Pradhan Acharya Shri Sarat Chandra Panda extended a vote of thanks.

Guru Purnima was also observed in many other place of the State under the auspices of the Parishad with traditional fervor.

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय सी.टी.ई.

केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर-302 031 (राज.)

दूरभाष : 0141-2680466 (कार्यालय), 0141-2681583 (प्राचार्य/फैक्स)

बेवसाइट : www.shriagrasenpgttcollegecte.com, ई-मेल : info@shriagrasenpgttcollegecte.com

संस्था अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम

- एम.एड. एक वर्षीय पाठ्यक्रम (राजस्थान वि.वि. से सम्बद्ध)
- बी.एड. एक वर्षीय पाठ्यक्रम (राजस्थान वि.वि. से सम्बद्ध)
- एस.टी.सी. द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम (राज्य सरकार से सम्बद्ध)
- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सृजित सी.टी.ई. संस्थान
- एम.एड. द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम (इग्नू, नई दिल्ली से सम्बद्ध)
- एम.ए. (शिक्षा) द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम (इग्नू, नई दिल्ली से सम्बद्ध)
- बी.एड. द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम (इग्नू, नई दिल्ली से सम्बद्ध)
- पी.जी.डी.एस.एल.एम. द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम (इग्नू, नई दिल्ली से सम्बद्ध)
- गाइडेन्स सर्टीफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स (इग्नू, नई दिल्ली से सम्बद्ध)
- मूल्य शिक्षा सर्टीफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स (इग्नू, नई दिल्ली से सम्बद्ध)

संस्था अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएँ

- छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक छात्रावास व्यवस्था
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा
- पुस्तकालय सुविधा
- शैक्षिक तकनीकी प्रयोगशाला
- मनोविज्ञान प्रयोगशाला
- विज्ञान प्रयोगशाला
- आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्रयोगशाला
- स्थापन्न प्रकोष्ठ
- परामर्श प्रकोष्ठ
- महिला प्रकोष्ठ
- शोध एवं प्रकाशन
- संस्कार केन्द्र

श्रीमती आशा गोलेचा
अध्यक्ष

प्रो. जे.पी.सिंघल
मंत्री

डॉ. रजनी शर्मा
प्राचार्य

प्रवीण राठौड़

उप सरपंच

ग्राम पंचायत खडात,
एवं तहसील अध्यक्ष

भारतीय जनता युवा मोर्चा, आबूरोड

निवासी - खडात, जिला- सिरोही, राजस्थान
मो. 9784322817

ADARSH VIDYA MANDIR SHANKAR VIDYA PEETH

(AN ENGLISH MEDIUM (BOYS) RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL)

MOUNT ABU (RAJ.)

AFFILIATED TO CBSE | ESTABLISHED IN 1995

A GOLDEN OPPORTUNITY TO PREPARE YOUR CHILD FOR

XI, XII + JEE (MAIN / ADVANCE) ENGINEERING ENTRANCE EXAM.,

XI, XII + NEET - MEDICAL ENTRANCE EXAM.

ADMISSION ANNOUNCEMENT FOR AVM - SIP BATCH

AVM - SIP is a School Integrated program (Schooling + Competitive exam preparation)

नई शिक्षण प्रणाली है वक्त की आवश्यकता

Salient features of AVM Success Batch

1. Driven by the successful system of AVM
2. Finest Teachers & Teaching methodology.
3. Highly refined and researched study material
4. Online Test Engine
5. Video Module of Lectures
6. Smart Classes with Educomp Support
7. Time Line Programs
8. English Language Strengthening
9. Research & Development Backing
10. Successfully operational from last 5 years.

TEACHING METHODOLOGY

1. Concept Classroom Sessions (CCS)
2. Doubts Removal Sessions (DRS)
3. Daily Practice Problems (DPP)
4. Exhaustive Study Material (ESM)
5. Regulars Test Series - Online & Offline (RTS)
6. Batch Re-Shuffling Through Monthly Tests

SCHOOL CAMPUS

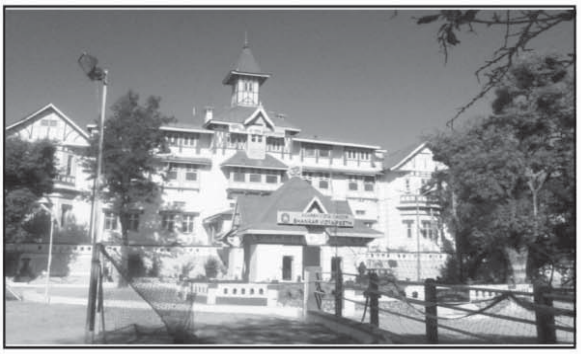

CLASS ROOMS

HOSTEL

SPORTS

Excellent Hostel Facility for Boys in School campus .

Yearlong Classroom contact programme

Target JEE (IIT / AIEEE) / NEET (AIIMS, PMT) - Medical Entrance

AVM SIP

निर्माण कन्स्ट्रक्शन

(बिल्डिंग रोड कांट्रेक्टर)

मु. पोस्ट- मोलासर, डीडवाना जिला- नागौर

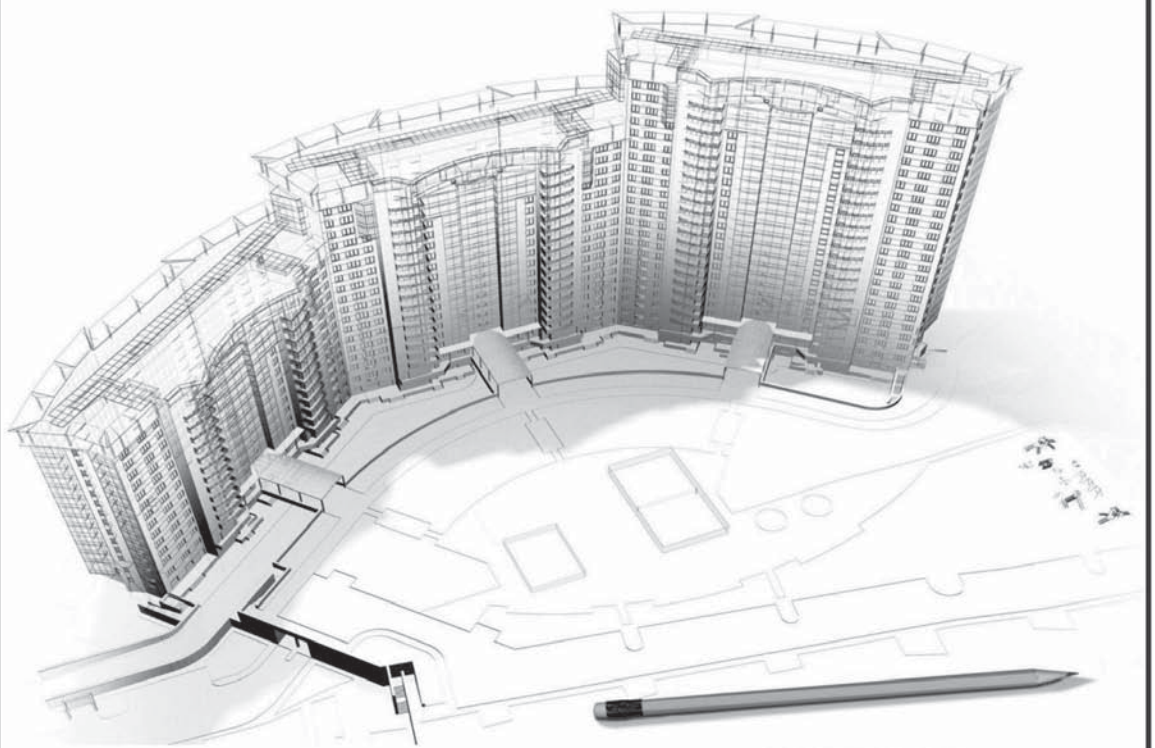

प्रो. प्रवीण पुरोहित

मो. 9928152342

पूर्व जिला प्रमुख जिला - नागौर

महामंत्री ग्रामीण मण्डल, डीडवाना जिला- नागौर